तमसो मा ज्योतिर्गमय

# शिक्षा सारथी

शिक्षा विभाग, हरियाणा की मासिक पत्रिका

वर्ष-8, अंक - 10, सितंबर 2020, मूल्य-15 रु

schooleducationharyana.gov.in | shikshasaarthi@gmail.com

## नई शिक्षा नीति करेगी साकार
## ज्ञान, योग्यता और रोज़गार

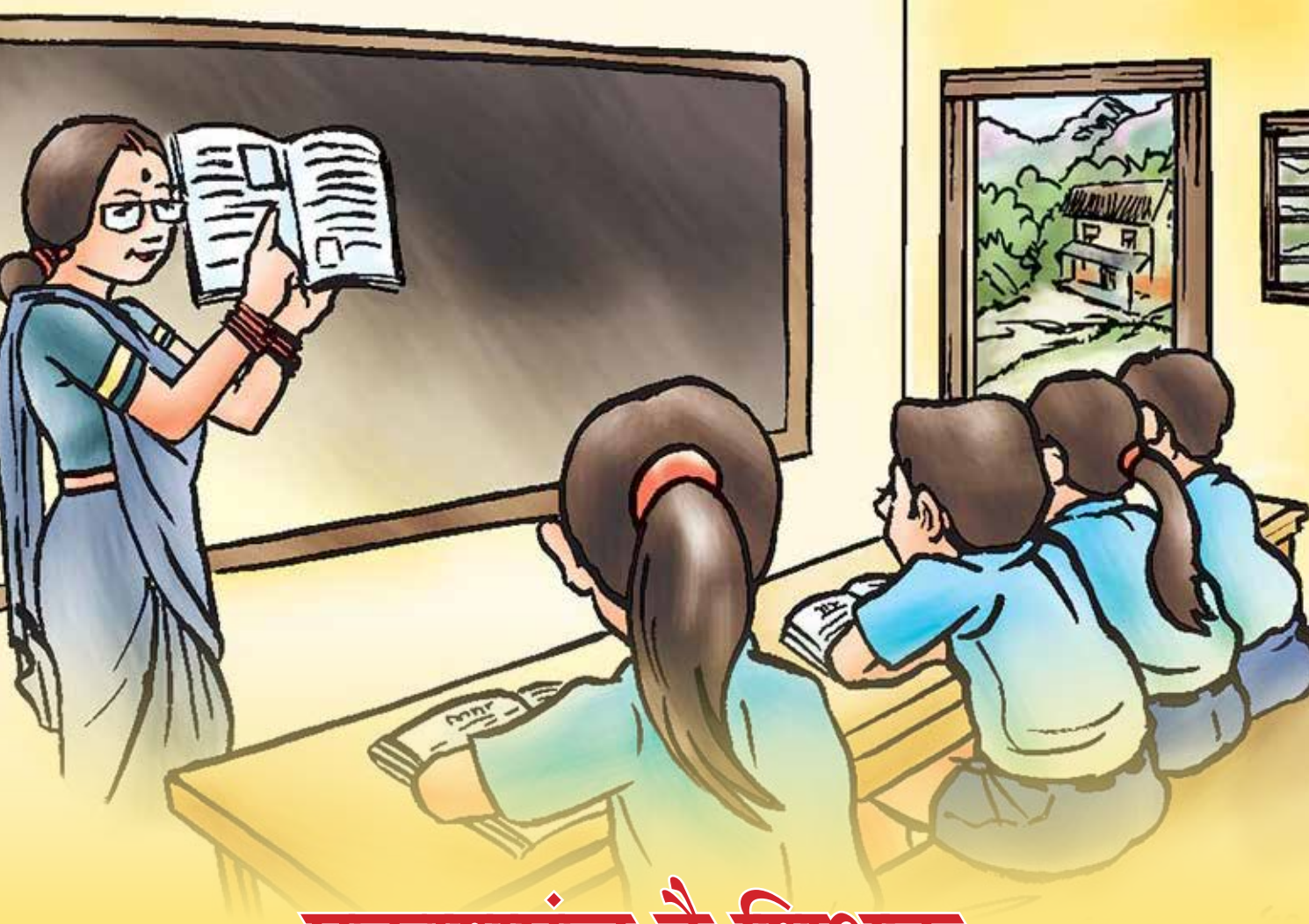

# प्रकाशपुंज है शिक्षक

नवाचारों में अग्रणी
सुविचारों का धनी
इरादों में हिमालय
हृदय से प्रशांत
विजय से विक्रांत
राधाकृष्णन जैसा शांत होता है शिक्षक ।

युधिष्ठिर जैसा धर्मी
भगीरथ जैसा कर्मी
कर्ण जैसा दानवीर
अर्जुन जैसा लक्ष्य चीर
चाणक्य जैसा बुद्धिमान होता है शिक्षक ।

पत्थरों में शिल्पकार
कच्ची मिट्टी का कुम्हार
सूक्ष्मता में स्वर्णकार
कल्पनाओं से चित्रकार
समाज का दर्पण होता है शिक्षक ।

इमारतों में इबारत
पत्थरों में पारस
पक्षियों में सारस
रसों में मधुरस
फलों में श्रीफल
झरनों में कल-कल
गंगाजल-सा पवित्र होता हैं शिक्षक ।

समरसता का प्रतीक
राष्ट्रीय एकता का दीप
शिष्य के लक्ष्य का पथिक
मोतियों से भरी जिसकी सीप
ऐसा व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं
ज्ञान का प्रकाशमान रूप होता है शिक्षक ।।

**गोपाल कौशल**
**नागदा, जिला- धार, मध्य प्रदेश**

तमसो मा ज्योतिर्गमय

# शिक्षा सारथी

**सितंबर 2020**

**प्रधान संरक्षक**
मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा

**संरक्षक**
कँवर पाल
शिक्षामंत्री, हरियाणा

**मुख्य संपादक**
डॉ. महावीर सिंह
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा

**संपादकीय परामर्श मंडल**
जे. गणेशन
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा

प्रदीप कुमार
निदेशक,
मौलिक शिक्षा, हरियाणा

डॉ. रजनीश गर्ग
राज्य परियोजना निदेशक
हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद

सतिन्द्र सिवाच
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा

**संपादक**
डॉ. देवियानी सिंह

**उप-संपादक**
डॉ. प्रदीप राठौर

**डिज़ाइन एवं प्रिंटिंग**
हरियाणा संवाद सोसायटी

**मूल्य:** 15 रुपये, **वार्षिक:** 150 रुपये

Published & Printed by Dilbag Singh on behalf of President, Shiksha Lok Society-cum-Director General Secondary Education, Haryana. Published from office of Director General Secondary Education, Haryana, Plot No. 1-B, Shiksha Sadan, Sector - 5, Panchkula.

Printed by delhi press patra prakahsna Pvt. Ltd. at its printing press PSPC Press 50, DLF Industrial Estate,

Faridabad- 121003,(Haryana)

Editor: Dr. Deviyani Singh.

"न हि ज्ञानेन सदृशं
पवित्रमिह विद्यते।'
इस संसारमें ज्ञान के समान
पवित्र (अन्य) कुछ भी
नहीं है।
-श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

- नए भारत की नींव बनेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : शिक्षा-मंत्री 5
- कौशल, रोज़गार, तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता को प्राथमिकता 6
- बाल्यावस्था देखभाल एवं प्रारंभिक शिक्षा को लेकर हुए महत्त्वपूर्ण प्रावधान 12
- जनाकांक्षाओं के अनुरूप बनी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 14
- मनोज लाकड़ा को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 15
- बुक-बैंक बनवाकर बचा लिए नन्ही आँखों के सतरंगी ख्वाब 16
- दीक्षाः अध्यापक क्षमता विकास के लिए ऑनलाइन मंच 20
- हिंदी है जन-जन की भाषा 22
- कोरोना महामारी का दौर और बच्चों की शिक्षा 24
- गीता-ज्ञान 25
- शिक्षक की पाती अपने प्यारे विद्यार्थियों के नाम 26
- लॉकडाउन में रचा अनूठा बाल साहित्य 27
- बाल सारथी 28
- जीने की कला 30
- हाँ, मैं सक्षम हूँ 31
- Can greater access to education be inequitable? 32
- Apps that stimulate learning 36
- On-Line Teaching : A Blessing in Disguise... 39
- Creating Language Rich Environment 41
- Put on Your Thinking Cap 43
- Compendium of Academic Courses After +2 45
- Amazing Facts 48
- General Quiz 49
- आपके पत्र 50

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों की निजी राय हो सकती है।
यह आवश्यक नहीं कि विभाग उनसे सहमत हो।

# आरोपित नहीं, जन भागीदारी से बनी है शिक्षा-नीति

देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन को 35 वर्षों के उपरांत स्वीकृति मिली है। यह परिवर्तन प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में किया गया है। इस नीति के आने से देश और समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावना को देखा जा रहा है। पाठ्यक्रम से आगे जाकर विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करने पर बल दिया गया है। विशेष संकाय चुनने के दबाव को समाप्त किया गया है। आरंभिक कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को वोकेशनल एक्सपोजर देने से देश के युवा ज़िंदगी के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे। साथ ही देश में ही मनपसंद रोज़गार पाने में सक्षम बनेंगे।

माननीय राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य मानते हैं कि यह शिक्षा नीति शहरी व ग्रामीण शिक्षा की खाई को मिटाने वाली है। उनके अनुसार यह कौशल, रोज़गार, तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता को प्राथमिकता देगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मानते हैं कि यह शिक्षा नीति भारत के शैक्षणिक परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी तथा नवाचार युक्त सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। माननीय शिक्षा मंत्री श्री कँवरपाल ने इस बात के लिए हर्ष व्यक्त किया है कि प्रदेश में पहले से ही शिक्षा को रुचिकर बनाने के अनेक सुधारात्मक उपाय चल रहे थे, जिन्हें अब नई शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। अब इन सुधारात्मक तरीकों का पूरा देश अनुसरण करेगा।

प्रदेश ने इस दिशा में तैयारियाँ आरंभ कर दी हैं। विभिन्न कमेटियों के गठन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। नई शिक्षा नीति व इसके लिए प्रदेश की तैयारियों की विशद जानकारी प्रस्तुत अंक के माध्यम से दी जा रही है। आइये, पूरे मन से इस नीति का स्वागत करें।

'शिक्षा सारथी' आपकी शिक्षण-यात्रा में सदैव आपके साथ है। आपके विचारों, नवाचारों व प्रतिक्रियाओं की हमेशा हमें प्रतीक्षा रहती है।

**-संपादक**

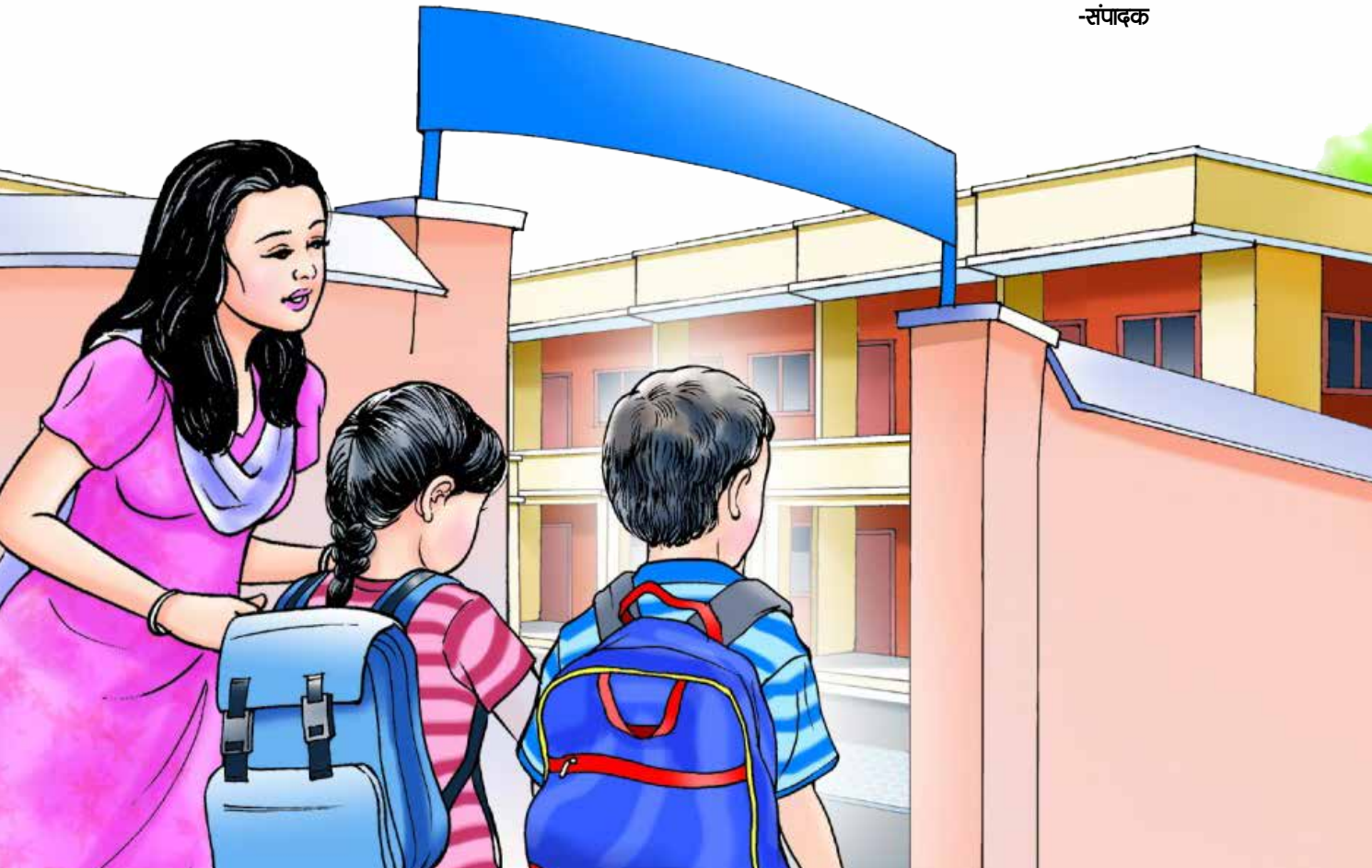

# नए भारत की नींव बनेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : शिक्षा-मंत्री

शिक्षा मंत्री श्री कँवर पाल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली है, इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ शिक्षाविदों व विद्यार्थियों के अभिभावकों को आगे आकर इस नीति के क्रियान्यवन को एक महायज्ञ समझकर आहुति डालनी होगी।

शिक्षा मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य, जो प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, द्वारा की गई उस पहल का भी स्वागत किया है, जिसमें हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में शिक्षाविदों की चार दिवसीय डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन करवाया। इसमें 250 से अधिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्राचार्यों, मुख्याध्यापकों व अन्य शिक्षाविदों ने अपने सुझाव दिए, जिन्हें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में समायोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

श्री कँवर पाल ने कहा कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के प्रति गंभीर हैं और संभवतः हरियाणा की डिजिटल कॉन्क्लेव की पहल को देखते हुए ही उन्होंने 7 सितम्बर, 2020 को सभी प्रदेशों के राज्यपाल, जो अपने-अपने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, इसी तरह की कॉन्क्लेव में नई दिल्ली बुलाया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रूपरेखा की समीक्षा की जाएगी।

श्री कँवर पाल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से सुदृढ़ है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ 15 किलोमीटर की परिधि में कोई न कोई महाविद्यालय खोला गया है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में प्राचीनकाल से ही शिक्षा दान एक महादान के रूप में प्रचलित है और यहाँ गुरु-शिष्य परम्परा युगों से चलती आ रही है। शिष्य अपनी शिक्षा पूरी करने के उपरांत गुरु को दक्षिणा देकर अपने भविष्य का लक्ष्य निर्धारित करके जो आशीर्वाद लेकर जाता है, उसी को शिक्षा का महादान कहा गया है और यह परम्परा विश्व के किसी अन्य देश में आज तक देखने को नहीं मिली।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गत 5 वर्षों में 97 नए कॉलेज खोले गए, जबकि हरियाणा गठन के बाद 48 वर्षों में केवल 75 कॉलेज ही खोले गए थे। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेश्यो (जीईआर) 50 प्रतिशत तक करना है, जो वर्तमान में देश में 26, जबकि हरियाणा में यह 32 प्रतिशत तक है। उन्होंने कहा कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव चाहते थे, वह इस नीति में देखने को मिला है और इसके तहत, अब प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह नर्सरी में हो या कॉलेज में हो, वैज्ञानिक तरीके से पढ़कर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभा सकेगा।

इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। इससे इस नीति के क्रियान्वयन में धन की कमी आड़े नहीं आएगी।

श्री कँवर पाल ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाएँ लगाकर हरियाणा ने देश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। हिमाचल व गुजरात के बाद हरियाणा देश में अव्वल स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने देश में सबसे पहले इस नीति के क्रियान्वयन की पहल की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से पहले ही प्रदेश में 1000 प्ले स्कूल खोलने की योजना तैयार की जा चुकी थी। इसके अलावा, 98 संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं।

**-शिक्षा सारथी डेस्क**

# नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
# कौशल, रोज़गार, तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता को प्राथमिकता

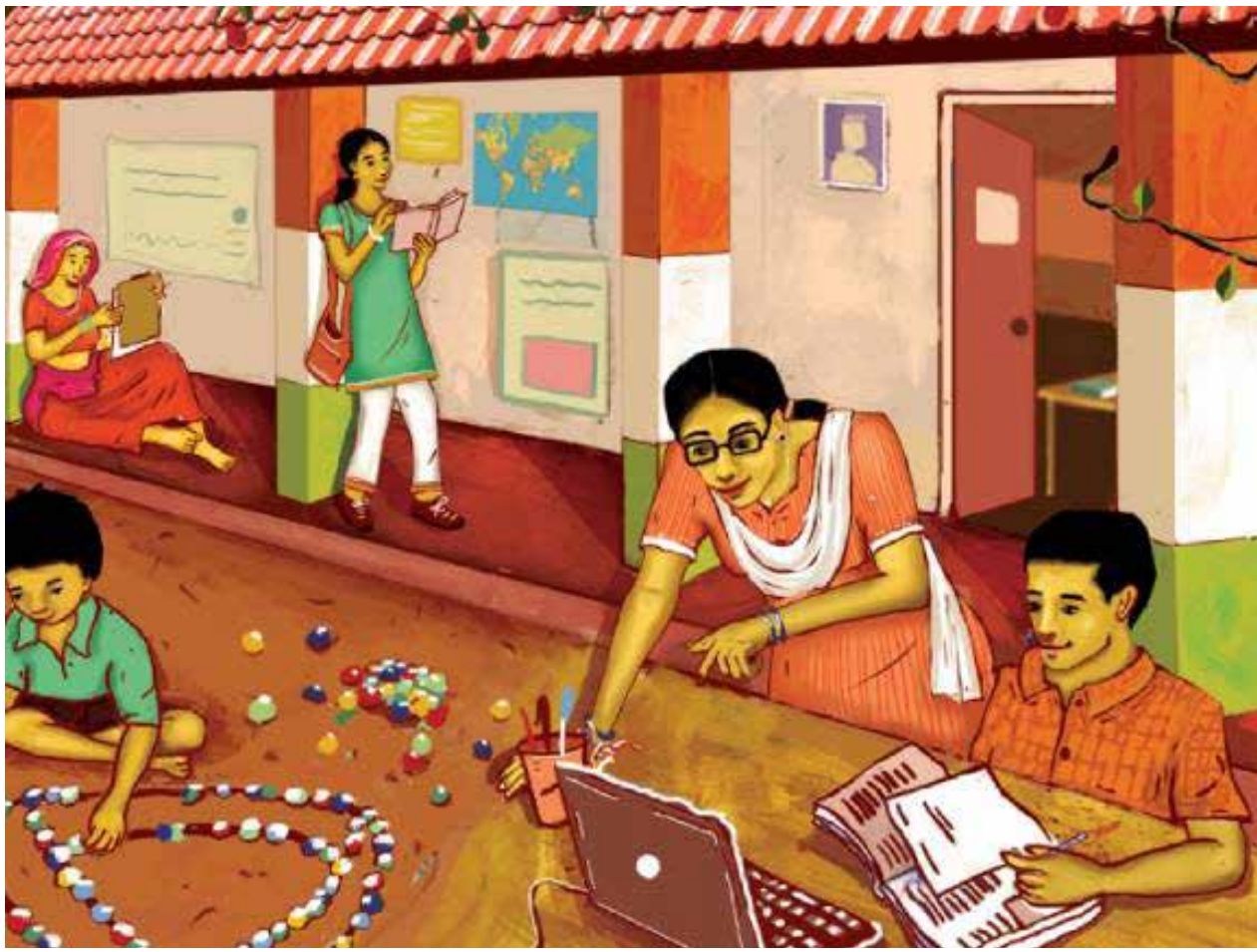

प्रमोद कुमार

प्रधानमन्त्री जी की अध्यक्षता में मन्त्रिमण्डल की बैठक में 29 जुलाई 2020 को 21वीं सदी की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब यह एनईपी-2020 के नाम से जानी जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पाँच साल के गहन अध्ययन, मंथन, चर्चा-विमर्श के उपरान्त अन्ततः मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा इसे पॉलिसी के रूप में लागू कर दिया गया। वर्ष 2015 में इस पर कार्य आरम्भ हुआ जिसमें प्रत्येक गाँव, कस्बे, नगर, शहर में चर्चा बैठकें हुईं। लाखों विचार मँगवाए गए, जिन पर आगे कार्य किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्य करने के लिए जून 2017 में गठित कमेटी द्वारा कुल 14 बैठकें की गईं जिनमें 74 संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों, ट्रस्ट, संगठन, विभाग, आयोग, प्रशिक्षण संस्थानों, फाऊंडेशन के साथ-साथ यूनीसेफ से चर्चा की गई, 217 एमीनेंट पर्सन्स के विचार लिए गए। समिति की सचिव शकीला शम्सु द्वारा अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी की अनुमति से 650 पृष्ठों का ड्राफ्ट जारी किया जिसके उपरान्त इसे सितम्बर 2019 में कैब कमेटी की बैठक में सभी राज्यों के गहन मंथन के उपरान्त मंजूरी प्राप्त हो गई है।

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने के लिए सिद्धांत-

देश में ऐसे शिक्षण संस्थान उपलब्ध करवाना जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी का स्वागत हो। उसे सुरक्षा का अहसास हो, जहाँ उसे अनुभव से सीखने के पूरे अवसर प्राप्त हों।

# शहरी व ग्रामीण शिक्षा की खाई को मिटाएगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

मुझे विश्वास है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान, अन्वेषण तथा जीविकोपार्जन से सम्बन्धित अध्ययन कार्य को गति देने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। नई शिक्षा नीति में पहले से ही सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए तय किया गया है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक रूप से दबे-कुचले लोगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को पूरी तरह अमल में लाना हम सब के लिए चुनौती होगी। इसके लिए हमें निजी संस्थानों के साथ बेहतर सामंजस्य करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति के मानदण्डों को अपनाते हुए यदि हम गरीब लोगों के लिए शिक्षा के सामान अवसर जुटा पाए तो यह देश के लिए गौरव की बात होगी।

हमें समान शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि शिक्षातंत्र में शहरी व ग्रामीण शिक्षा की खाई को मिटाना होगा जिससे सभी को शिक्षा के सामान अवसर मिलेंगे। देश में सामान शिक्षा होगी तो वर्णविहीन समाज होगा और नव भारत का निर्माण होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल, रोजगार, तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी गई है। इन्हीं सब पैमानों पर खरा उतरने के लिए विश्वविद्यालयों को उद्योगों से जुड़ना होगा ताकि दोनों संस्थाएँ आपस में ताल-मेल कर डिप्लोमा, डिग्री, व्यवसायी कोर्स करवाकर युवाओं को रोचक विषयों व कार्यों में पारंगत कर सकें।

**सत्यदेव नारायण आर्य**
**राज्यपाल हरियाणा**

स्कूल में हर ढाँचागत सुविधा उत्कृष्ट हो। शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन हो ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार अपने सीखने के रास्ते का चुनाव कर सके। जहाँ पाठ्य क्रियाओं और सहपाठ्य क्रियाओं में भेद न हो, कौशल शिक्षा और शैक्षणिक पाठ्यक्रम साथ-साथ चलें, साइंस, आर्ट, सामाजिक विज्ञान, खेलकूद, मनोविज्ञान आदि साथ-साथ चलें, जहाँ रटने की अपेक्षा अवधारणा को समझने पर बल दिया जाए, जहाँ सृजनात्मकता और विश्लेषण को बढ़ावा दिया जाता हो, जो नवाचार को बढ़ावा देता हो। ऐसा विद्यालय जो जीवन मूल्यों और सिद्धांतों, आदर्शों, जीवन कौशलों जैसे सहयोग, संगठन, समूह में काम करना, सम्प्रेषण जैसे गुणों का नेतृत्व एवं विकास के अवसर उपलब्ध करवाता हो। समता और समानता, एकीकरण एवं समावेश, विभिन्नता एवं अनेकता को खुले मन से समझने की प्रेरणा देता हो। एक ऐसा विद्यालय जो ऐसे नागरिक तैयार करे जो स्वार्थ, लालच जैसे विषयों से हटकर 'सबका साथ, सबका विकास' करने को तैयार रहें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से 10+2 तक का उल्लेख किया गया है जिसमें 'फाउंडेशन ऑफ लर्निंग' में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यवस्था बनाई गई है। अब विद्यार्थी सीधे पहली कक्षा में नहीं जाएँगे, उन्हें तीन वर्ष - पूर्व पहली-1, पूर्व पहली-2, तथा पहली कक्षा अर्थात् तीन वर्ष की औपचारिक शिक्षा लेनी होगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा लचीली होगी जो खेल-खेल में गतिविधि आधारित खोज के सिद्धांत पर होगी तथा जिसमें अंक, शब्द, भाषा, गिनती, रंग, आकार, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, कहानी, कठपुतली, संगीत आदि का समावेश होगा। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्रशिक्षण प्राप्त आँगनवाड़ी कर्मियों की मदद से दी जाएगी। कक्षा तीसरी से पाँचवीं के तीन वर्षों को 'फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी' के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुख्यतः पढ़ना, लिखना, बोलना, गिनना, गणित तथा गणित के माध्यम से अनुमान, आकलन एवं समझ का विकास करना जो जोड़, घटाव, गुणा-भाग से परिचय करवाता हो और उसे जीवन में उपयोग में सक्षम बनाता हो, शामिल किया गया है। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी अधिमान दिया गया है जिसमें पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जाना प्रस्तावित है।

**ड्रॉपआउट कम करना तथा स्कूल उपलब्ध करवाना-**

इसके सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि कक्षा पहली में दाखिल होने वाला प्रत्येक विद्यार्थी अनिवार्य शिक्षा पूरी करे, बच्चे स्कूल बीच में न छोड़ें। आज पहली कक्षा में दाखिल बच्चों का 51 प्रतिशत ही कक्षा बारहवीं तक पहुँचता है और अगर बीए पास होने के स्तर को देखा जाए जो हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य में भी 28 प्रतिशत के आसपास है। पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र में बदलाव करके शिक्षा को समग्र, एकीकृत, रुचिकर तथा आनन्दपूर्ण बनाने पर जोर दिया गया है। प्रदेश में 'जॉयफुल सैटरडे' की शुरूआत पहले से ही हो गई थी, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस पर मोहर लगा दी है।

आयु के अनुसार कक्षाओं की बाँट भी अलग की गई है जिसके अन्तर्गत 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के लिए पूर्व प्राथमिक से दूसरी तक की कक्षा, 8 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए तीसरी से पाँचवीं कक्षा, 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए छठी से आठवीं कक्षा तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए नौवीं से बारहवीं कक्षा का निर्धारण किया गया है। पूर्व की व्यवस्था जिसमें 6 से 18 वर्ष की आयु के लिए 5+3+4 कक्षाएँ थीं, अब 3 से 18 वर्ष की आयु के लिए 5+3+3+4

# नवाचार युक्त सुधारों का मार्ग करेगी प्रशस्त

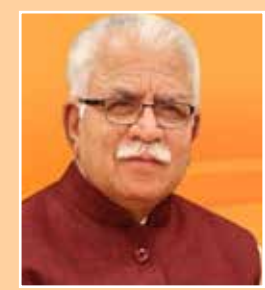

पिछले 5 वर्षों से शिक्षा नीति तैयार करने के लिए अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों व जिलों से प्राप्त दो लाख से अधिक सुझावों को इस नीति में शामिल किया गया, जो इस नीति की प्रमुख विशेषता है। सभी स्टेकहोल्डर्स व शिक्षाविदों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर नई नीति स्कूली, उच्चतर शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा में कारगर सिद्ध होगी। भारत के शैक्षणिक परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी तथा नवाचारयुक्त सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। शिक्षा पहले की तरह लाभ के लिए नहीं, व्यवहार पर आधारित होगी। हरियाणा भी इस नीति का अक्षरशः अनुसरण करेगा और इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।

**-मनोहर लाल,**
**मुख्यमंत्री हरियाणा**

# प्रदेश के कई सुधारात्मक उपायों को नई शिक्षा नीति में स्थान

**विद्यालयों में डॉपआउट रोकने के लिए हरियाणा में कारगर रहे जॉयफुल सेटरडे सहित अन्य उपायों पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। प्रदेश में संचालित शिक्षा सुधारों संबंधी कई योजनाओं को नई शिक्षा नीति में जगह मिली है। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में रेमेडियल टीचिंग, स्मार्ट क्लास, शनिवार को आयोजित होने वाला जॉयफुल डे, बैग-फ्री क्लास, स्किल पास-बुक, क्विज़ क्लब आदि के माध्यम से शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। अब उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्थान दिया गया है, यानी पूरा देश अब इन सुधारात्मक तरीकों का अनुसरण करेगा।**

**-कँवरपाल,**
**शिक्षा मंत्री, हरियाणा**

बनाई गई हैं। सीखने की अवधारणा में पाठ्यक्रम को महत्त्व न देकर कौशलों, दक्षता (कंपीटेंसी) आधारित शिक्षण अधिगम पर बल दिया गया है। एक ओर प्राथमिक कक्षाएँ जहाँ नींव मजबूत करने पर बल देंगी, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाएँ रोजगार के अवसरों पर केन्द्रित होंगी। इसमें समग्र शिक्षा और शिक्षा से समग्र विकास के लिए ऐसे शिक्षा शास्त्र पर बल दिया गया है जो यह सिखाये कि कैसे सीखा जाता है यानी लर्निंग (हाऊ टू लर्न)। यह आज के रट्टा लगाकर पढ़ने के तरीकों से दूर लेकर जाएगी और विद्यार्थी को 21वीं सदी के कौशलों के लिए तैयार करेगी।

पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री को कम करने पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोर दिया गया है क्योंकि वर्तमान पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के दबाव में अध्यापकों को विद्यार्थियों को जीवन कौशल सिखाने का समय नहीं मिलता। अतः राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र सोच, खोज आधारित, चर्चा आधारित तथा विश्लेषणात्मक पठन-पाठन को मुख्यतः स्थान दिया गया है। पाठ्य सामग्री का पूरा जोर अब अवधारणा, विचार, अपनाना, करके देखना तथा समस्या समाधान करना पर केन्द्रित होगा। प्रश्न पूछने की परम्परा को मजबूत किया जाएगा, जिज्ञासा पैदा की जाएगी, ज्ञान पिपासु बनने के अवसर खोले जाएँगे।

बच्चे अपनी दक्षता, क्षमता, रुचि के अनुसार विषयों का चयन करने के लिए स्वतन्त्र होंगे। सम्पूर्ण विकास के लिए तथा समग्र विकास के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। कक्षा पाँचवीं तक बच्चे की मातृभाषा में ही शिक्षण अधिगम होगा। उसके उपरान्त मातृभाषा एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। अध्यापकों को दो भाषाओं में कक्षा में शिक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। एक से अधिक भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, जीवन के आरम्भ के वर्षों में इन्हें सीखना सरल है। भाषाओं को परस्पर संवादात्मक तरीके से सिखाने पर बल दिया जाएगा। ड्रामा, कविता, संगीत, गाने आदि का समावेश किया जाएगा। जहाँ तक तीन भाषा फार्मूले का सम्बन्ध है, इसे लागू रखा जाएगा। किसी भी प्रकार से किसी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। इसमें व्यापक लचीलापन होगा, प्रत्येक विद्यार्थी एक प्रोजैक्ट लेगा जो रुचिकर होगा तथा जिसमें भारत की, अपने गृह राज्य से दूर के किसी राज्य की भाषा को सीखेगा। हरियाणा राज्य में यह 'जॉयफुल सैटरडे' का भाग होगा तथा इसके लिए उसे प्रोजैक्ट में अंक भी मिलेंगे। संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा को, उसके साहित्य को जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसमें गणित, दर्शनशास्त्र, व्याकरण, संगीत, राजनीति शास्त्र, आयुर्वेद, वास्तुकला, धातु विज्ञान, ड्रामा, कविता, कहानी शामिल हैं, को विद्यार्थियों तक पहुँचाया जा सकता है। भाषाओं में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत के साहित्य को भी स्कूल स्तर पर बढ़ावा

## हरियाणा में चल रहे सुधारात्मक उपाय, जिन्हें नई शिक्षा नीति में मिला स्थान

1. **बैगलैस डेज़** - हरियाणा में इसे 14 नवम्बर, 2016 को आरम्भ किया गया जिसकी सफलता के मध्यनजर इसे एनईपी में इनोवेटिव पैडागोजी का भाग बनाया गया।
2. **मंथली एसेस्मैंट टेस्ट (मैट) तथा स्टूडेंट एसेस्मैंट टेस्ट (सैट)**- हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2015 में ही मंथली एसेस्मैंट टैस्ट आरम्भ किए गए जिसकी सफलता को देखते हुए 'प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की परिणामों की सतत ट्रेकिंग' को आरम्भ किया गया।
3. **स्किल पासबुक** : हरियाणा में वर्ष 2016 से ही प्रत्येक विद्यार्थी की स्किल बेस्ड रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक कार्ड बनाया गया जिसकी सफलता को देखते हुए 'समग्र प्रगति कार्ड' को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया।
4. **क्विज़ क्लब**- हरियाणा के स्कूलों में क्विज़ क्लबों की स्थापना पहले से ही है तथा 'कौन बनेगा लखपति' जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। अब क्विज़ को भी एनईपी में शामिल किया गया है।

देने पर बल दिया गया है। विद्यार्थी 21वीं सदी के कौशलों आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, डिजाइनिंग, थिंकिंग, ऑरगेनिक लिविंग तथा सस्टेनेबल डिवेलपमैंट, डाटा साइंस आदि पर भी ध्यान केन्द्रित करें।

पूरे देश में एक जैसी पुस्तकें हों, जिनका निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया जाए तथा उसमें स्थानीय विषयों, सन्दर्भों, उदाहरण एवं उत्सवों, रिवाजों और परम्पराओं को विशेष स्थान दिया जाए। इसका उद्देश्य देश के विद्यार्थियों को सस्ती दरों पर एक जैसी उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें उपलब्ध करवाना हो। विद्यार्थी विकास के लिए मूल्यांकन व्यवस्था में भी बदलाव करने की वकालत पॉलिसी में की गई है। यह व्यवस्था विद्यार्थी का कौशल विकास आँकने, अध्यापक के अध्यापन को आँकने और पूरे विद्यालय को अपनी पठन पाठन प्रक्रिया के बदलाव में मदद करे। बोर्ड परीक्षा समग्र विकास के लिए हो, उसमें रटने की प्रक्रिया को समाप्त करने के प्रयास हों। बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाए, विद्यार्थी बिना नकल के पास हों, ऐसा विश्वास बने। उच्च स्तर के प्रवेश के लिए परीक्षाओं का आयोजन एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाए और प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का चुनाव इस प्रकार होगा जो रटने की प्रक्रिया को समाप्त करेगा। ऐसे विद्यार्थी जिनकी प्रतिभा प्रखर है उनके लिए अलग व्यवस्था होगी, उनकी प्रतिभा को सींचने, पालने और फलदायक बनाये जाने के प्रयास होंगे। ऐसी प्रतिभा की पहचान करके विशेष कार्यक्रम बनाया जाएगा, विषय आधारित, परियोजना आधारित क्लब और सर्कल बनाए जाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिसमें साइंस सर्कल, गणित सर्कल, संगीत प्रदर्शन सर्कल, शतरंज सर्कल, काव्य, भाषा, नाटक, वाद-विवाद आदि बनाकर इनके लिए धन उपलब्ध करवाकर विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि तथा उसकी प्रतिभा को सींचने का कार्य किया जाएगा। पूरे राष्ट्र में ओलंपियाड तथा अन्य प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ओलंपियाड के परिणामों को आईआईटी तथा एनआईटी जैसे संस्थान दाखिले के समय वरीयता देंगे। 'क्विज़ क्लबों' का गठन होगा तथा ऑनलाइन क्विज़ प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

अध्यापक नियुक्ति आदि के लिए एनईपी- 2020 में काफी कुछ कहा गया है। विशेषकर अध्यापक की गुणवत्ता, उसकी शिक्षा का स्तर, उसके कौशलों का स्तर, उसका साक्षात्कार तथा प्रतिभा प्रदर्शन अवलोकन उपरान्त नियुक्ति ऐसे विषय हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आदि भी इसमें शामिल हैं जैसे बीएड का चार वर्षीय पाठ्यक्रम बनाना, अध्यापकों की सुविधा के लिए आवास व्यवस्था उपलब्ध करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक अध्यापक नियुक्त हों अथवा सभी गाँवों तक, अध्यापक पहुँचें, अध्यापकों की कमी को दूर करने हेतु प्रयास किए जाएँ। अध्यापकों के स्थानान्तरण पर बहुत ही शानदार बात कही गई है कि इनका स्थानान्तरण जल्द न किया जाए। अध्यापक लम्बे समय तक एक विद्यालय में रहेगा तो समाज के साथ उसका लगाव, जुड़ाव, दायित्व मजबूत होगा और एक स्कूल भवन को संस्थान में परिवर्तित करेगा। स्थानान्तरण केवल तभी किया जाए जब अति आवश्यक हो जैसे पारिवारिक कारण, पदोन्नति आदि।

टीचर्स एलीजिबिलिटी टेस्ट को अधिक मजबूत और समग्र बनाया जाएगा जो अध्यापक के कौशलों और अभिप्रेरण के स्तर का भी आकलन करेगा। स्कूल कॉम्पलेक्स व्यवस्था आदि में स्थानीय ज्ञान, भाषा को भी शामिल किया जाएगा। कलस्टर व्यवस्था में एक अध्यापक के कौशलों का प्रयोग कलस्टर के बाकी विद्यालयों में भी कर सकेंगे। स्थानीय कला, क्राफ्ट, खेती, उद्यम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त प्रशिक्षक

## नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है नया ?

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करना।
2. स्कूल वर्षों को 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष करना।
3. 21वीं सदी के कौशलों के ऊपर ध्यान देना।
4. विज्ञान, कला, पाठ्य गतिविधियाँ, सह पाठ्य गतिविधियाँ तथा व्यावसायिक कोर्स में भेद खत्म करना।
5. प्रतिभावान बच्चों के लिए अलग व्यवस्था करना।
6. नई पाठ्यचर्या का निर्माण करना।
7. बोर्ड की परीक्षाओं में सुधार करना।
8. पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देना।
9. राष्ट्रीय स्तर पर एक समान प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना।
10. अध्यापकों के लिए मानक तैयार करना।
11. प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों के लिए एक जैसे मापदण्ड बनाना।

### अन्य महत्त्वपूर्ण बदलाव

1. साहित्य तथा वैज्ञानिक शब्दावली तथा भारतीय भाषाओं पर ध्यान देना।
2. भाषाओं पर शोध करना तथा भारतीय क्लासिकल भाषाओं का सशक्तीकरण करना।
3. लोक कलाओं और विधाओं का उत्थान करना।
4. योजना बनाने, पठन-पाठन तथा प्रबन्धन में तकनीक का इस्तेमाल।
5. लाभ से वंचित वर्ग की शिक्षा तक पहुँच मजबूत करना।
6. दिव्यांगजनों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना।
7. डिजिटल कंटेंट, लाइब्रेरी तथा उपकरणों का स्कूलों में विस्तार करना।

### समय सीमा निर्धारण-

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा - 2021 से 2024
2. नई पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन व्यवस्था - कक्षा 9 से 12 समय 2021 से 2026
3. नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स- 2023
4. कक्षा 3 तक सभी बच्चों के लिए फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी-2025 से 2026

लगाए जाएँगे। पूरे भारत में अध्यापक नियुक्त करने के लिए सतत एवं समग्र योजना बनाई जाएगी। कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाने के प्रयास पर भी बल दिया जाएगा ताकि अध्यापक, विद्यार्थी और अभिभावकों का एक अच्छा समाज समूह मददगार बन सके। स्कूलों में अच्छी ढाँचागत सुविधा, जिसमें साफ-सुथरे शौचालय, शुद्ध पेयजल, पठन-पाठन के लिए रुचिकर कक्षा कक्ष, बिजली व्यवस्था, कम्प्यूटर, इंटरनेट, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा प्रचुर मात्रा में शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल का सामान उपलब्ध होगा।

स्कूल कॉम्पलेक्स, जिसमें आसपास के स्कूलों का समूह होगा, जो आज के कलस्टर स्कूल जैसा ही होगा। इसमें स्कूल के संसाधन और मानव संसाधन आपस में आवश्यकतानुसार साँझे किए जा सकेंगे। इसमें परामर्शदाता तथा विशेष प्रशिक्षक आदि लगाए जाएँगे जो पूरे कलस्टर के लिए होंगे। इसमें स्कूल प्रबन्धन समिति के साथ कॉम्पलेक्स/कलस्टर के लिए भी एक कमेटी होगी जो साँझे संसाधनों के आवश्यकतानुसार वितरण के लिए प्रबन्धन करेगी।

अध्यापकों के गैर शैक्षणिक कामों पर खर्च होने वाले समय को कम किया जाएगा। अध्यापक केवल पठन-पाठन पर ही केन्द्रित रहेगा। इसमें इन्हें लम्बी चुनाव डयूटी जैसे बीएलओ आदि के कार्य से मुक्ति, मध्याह्न भोजन के कार्यों से मुक्ति तथा विभिन्न प्रशासनिक कार्यों से अलग रखा जाएगा। अध्यापक को उसकी पठन-पाठन प्रक्रिया और शिक्षा-शास्त्र में अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाएगी। अध्यापक अपनी व्यावसायिक योग्यता निरन्तर बढ़ाते रहें, उसे उन्नत करते रहें, इसके लिए वातावरण बनाया जाएगा। इस कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन मंच उपलब्ध करवाया जाएगा, जहाँ अध्यापक अपने उत्कृष्ट प्रयोगों को अन्य राज्यों के अध्यापकों के साथ साँझा कर सकेंगे। प्रत्येक अध्यापक को प्रतिवर्ष 50 घंटे का CPD (Continuous Professional Development) करना होगा। स्कूल मुखिया और कॉम्पलेक्स/कलस्टर मुखिया के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था होगी।

इस पॉलिसी में एक नया बिन्दु शामिल किया गया है। ऐसे अध्यापक जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर अधिक वेतनमान तथा विशेष लाभ उपलब्ध करवाए जाएँगे। अध्यापक के पूरे कार्यकाल का रिकॉर्ड देखा जाएगा जिसके आधार पर उसे पदोन्नति दी जाएगी। इसके आधार पर ही उन्हें बीआरसी आदि बनाया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। जैसे- 2030 तक 4 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना, पाठ्यक्रम में कक्षा आधारित प्रशिक्षण को वरीयता देना, सभी अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्राधिकार में शामिल करना तथा नियन्त्रित करना शामिल हैं।

'सभी के लिए शिक्षा' पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। लाभ से वंचित वर्ग जिसमें दलित, पिछड़े, बालिकाएँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ग्रामीण, टपरीवास, आदिवासी, ट्रांसजेंडर को यूआरजी यानी अंडर रिप्रेसैंटिड ग्रुप के नाम से सम्बोधित किया गया है। उनके दाखिले, ठहराव तथा अवस्थांतर पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। दाखिले के उपरान्त ड्रॉपआउट को शून्य पर लाना और उच्चतर शिक्षा में दाखिला सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाने पर बल दिया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल और नॉन स्टार्टर की संख्या शून्य हो, इसलिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया गया है। स्कूल पहुँचने तक निःशुल्क यातायात, साइकिल व्यवस्था तथा सुरक्षा उपलब्ध करवाई

देश में संचालित वर्तमान शिक्षा नीति जिसका निर्माण वर्ष 1986 में किया गया तथा जिसका अद्यतन वर्ष 1992 में हुआ, यदि उसका तुलनात्मक अध्ययन नई शिक्षा नीति के साथ किया जाए तो इसमें स्कूल शिक्षा से सम्बन्धित निम्न नये बिन्दु शामिल किए गए हैं-

### क. स्कूलिंग और प्राथमिक स्कूल स्तर की तैयारी

» 2030 तक सभी के लिए ईसीसीई, ईसीसीई के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
» 2030 तक स्कूली शिक्षा में शत-प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना

### ख. स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज

» विशेष शिक्षा क्षेत्र (एसईजेड)
» सामाजिक चेतना केन्द्रों के रूप में स्कूलों की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग

### ग. छात्र का समग्र विकास

» पाठ्यक्रम का अतिरिक्त और सह-पाठ्यक्रम, कला और विज्ञान, खेल और व्यावसायिक शिल्प का अधिक अलगाव नहीं। भारतीय संस्कृति और लोकाचार को एकीकृत करने के लिए पाठ्यक्रम
» अनुभवात्मक शिक्षण / सीखने के तरीकों के रूप में नवीन शिक्षाओं को स्थापित किया जाना

### घ. समावेशिता

» जेंडर इंक्लूजन फंड; केजीबीवी 12 वीं कक्षा तक
» गिफ्टिड बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

### ङ. आकलन

» समग्र मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र,
» समग्र विकास के लिए ज्ञान की समीक्षा और विश्लेषण –PARAKH
» ग्रेड 10 और 12 में बोर्ड परीक्षा के अलावा ग्रेड 3, 5 और 8 में परीक्षा

### च. पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा

5+3+3+4 के नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचे
मुख्य अवधारणाओं के लिए पाठ्यक्रम में कमी

### छ. शिक्षक आवश्यकताएँ / शिक्षक शिक्षा

» 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता की डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री
» टीईटी, एनटीए टैस्ट और शिक्षण प्रदर्शन के आधार पर शिक्षक भर्ती; शिक्षण के लिए टीईटी अनिवार्य

### ज. सरकारी विभागों / निकायों / संस्थानों की भूमिका-

» राज्य विभाग नीति निर्माण की देखभाल करने वाला; संचालन की देखरेख शिक्षा निदेशालय करेगा, एससीईआरटी सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन स्व-प्रकटीकरण के लिए न्यूनतम सामान्य मानकों को निर्धारित करने के लिए शिक्षाविदों और राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण का ध्यान रखेगा
» स्कूलों द्वारा स्व-प्रकटीकरण पर निरंतर ऑनलाइन प्रतिक्रिया के लिए छात्रों की रैंडम सैंपलिंग

### कमेटियों का गठन-

उपरोक्त बिन्दुओं पर नीति बनाने तथा विभागीय राय बनाने के लिए एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव है क्योंकि इन सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही के लिए विभिन्न विभागों का समन्वय अनिवार्य है जिसमें उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कौशल विकास विभाग को शामिल किया जाना है। इसके लिए निम्न कमेटियाँ बनाये जाने का प्रस्ताव है-

1.**पूर्व प्राथमिक शिक्षा-** इसके लिए डब्ल्यूसीडी विभाग के साथ कार्य किया जाना है जिसमें डीईई, एसपीडी कार्यालय से अधिकारीगण कार्य करेंगे। इसके लिए प्रथम चरण की समय सीमा 2021-22 है तथा आँगनवाड़ी के साथ सभी स्कूलों को जोड़कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की समय सारणी 2023-24 है। इसी कड़ी में विद्यार्थी को पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक मॉडयूल (3 Month Preparatory Module for Class-I students) पढ़ना होगा। इसके लिए तैयारी करनी होगी, इसको तैयार

जाएगी। भारत सरकार के स्तर पर जेंडर इनक्लूसन फंड (Gender Inclusion Fund) बनाया जाएगा जो राज्यों में बालिका शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। यूआरजी के बच्चों की शिक्षा आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अध्यापकों, स्कूल मुखिया, परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

कलस्टर स्कूल अथवा कॉम्पलेक्स स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, जिसमें 8 से 10 स्कूलों के समूह में एक बड़ा स्कूल होगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधा, संसाधन होंगें। सभी विषयों में पढ़ने की व्यवस्था होगी। विद्यार्थी निःशुल्क यातायात सुविधा प्राप्त करके बड़े स्कूल में पढ़ेंगे। ये स्कूल सभी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। छोटे स्कूल विद्यार्थियों के विकास में ज्यादा लाभदायक नहीं रहे हैं, वहाँ पर समूह से सीखने के अधिक अवसर नहीं हैं, अतः छोटे स्कूलों को बन्द किया जाएगा तथा 2025 तक इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी।

स्कूलों के नियन्त्रण एवं मान्यता के लिए भी पॉलिसी में बहुत कुछ कहा गया है। आज स्कूलों को मान्यता देने का, सरकारी स्कूलों को चलाने का तथा योजना बनाने का काम एक ही संस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है जो डीईओ/डीईईओ के माध्यम से होता है। यह व्यवस्था शिक्षा के व्यापारीकरण को नियन्त्रण करने में सफल नहीं हुई है। इसके लिए पॉलिसी में प्रस्ताव दिया गया है। स्कूलों को नियन्त्रण करने के लिए एक अलग संस्था एसएसआरए होगी जो बच्चों की सुरक्षा, अनिवार्य ढाँचा, छात्र अध्यापक अनुपात (विषयवार-कक्षावार) ईमानदारी तथा शासन की निष्पक्ष व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगी। एससीईआरटी इसके लिए मार्गदर्शिका का निर्माण करेगी। पर्यवेक्षण और निजी निर्माण का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग के पास रहेगा। सभी प्रकार के शैक्षणिक मामले जैसे पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन आदि एससीईआरटी द्वारा ही नियन्त्रित किए जाएँगे जो एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में बनाए जाएँगे तथा बीआरसी, डाइट आदि के माध्यम से अग्रेषित होंगे। परीक्षा लेने का कार्य तथा प्रमाण पत्र देने का कार्य शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को एक जैसे मापदण्डों के आधार पर ही नियन्त्रित किया जाएगा। इसमें पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूलों को सभी प्रकार की सूचना जन अवलोकनार्थ अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी होगी। स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियन्त्रण रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी।

पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात को जानने के लिए नेशनल अचीवमैंट सर्वे जो एनसीईआरटी द्वारा करवाया जाता है, उसे नियमित रूप से करवाया जाना चाहिए। राज्य सरकारें भी अगर चाहें तो अपना इस प्रकार का सर्वेक्षण करवा सकती हैं ताकि स्कूलों को अपने लक्ष्यों के निर्धारण में मजबूती मिल सके। विद्यार्थियों की सुरक्षा, उनके अधिकार, उनके किशोरावस्था के पेचीदा मामले का बेहतर समाधान करना, लड़कियों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव के मामले बिना देरी के समुचित समाधान तक पहुँचाने अनिवार्य हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था भयमुक्त, बाल केन्द्रित, बाल मित्रवत, रुचिकर, सरल, गतिविधि आधारित हो जो केवल अक्षर ज्ञान देने तक सीमित न हो अपितु राष्ट्र के लिए सच्चे, ईमानदार, मेहनती नागरिक तैयार करे तथा जो मानव मूल्यों को गम्भीरता से समझें।

**प्रमोद कुमार**
**कार्यक्रम अधिकारी**
**शैक्षणिक प्रकोष्ठ**
**माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा**

करने के लिए अप्रैल, 2021 तक का समय है।

2. **नई पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का कार्यन्वयन-** इस कार्य के लिए विभाग की ओर से डीएसई, डीईई, एसपीडी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तथा एससीईआरटी द्वारा मिलकर कार्य किया जाना है। इसकी समय सारणी कक्षा 9 से 12 तक के लिए अप्रैल 2021-22 से आरम्भ होगी जो अगले चार वर्षों में अर्थात् 2024-25 तक कक्षा 12वीं तक के लिए की जानी अनिवार्य है।

3. **नया परीक्षा पैटर्न-** उपरोक्त पर कार्यवाही भिवानी बोर्ड द्वारा की जानी है जो 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं तथा 2024-25 तक कक्षा 12वीं के लिए की जानी अनिवार्य है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कक्षा आठवीं की परीक्षा अब बोर्ड की नहीं होगी तथा अब कक्षा 3, 5 और 8 के लिए यह स्कूल स्तर की परीक्षा होगी। इसके लिए सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के साथ डीईई तथा एससीईआरटी की संयुक्त बैठक की जानी है।

4. **स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना (NCFSE)-** इस पर कार्य करने के लिए राज्यों को भी स्वतन्त्रता दी गई है तथा यह 2021-22 तक तैयार किया जाना है जिसका हर पाँच वर्ष बाद अद्यतन किया जाएगा। इसके लिए एससीईआरटी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी, डीईई, डीएसई, एसपीडी की टीम का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

5. **ग्रेड-3 तक सभी शिक्षार्थियों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्राप्त करना-** उपरोक्त कार्य के लिए वर्ष 2025-26 तक का समय दिया गया है। यह कार्य एससीईआरटी के साथ शैक्षणिक शाखा, एसपीडी कार्यालय तथा डीईई के माध्यम से करवाया जाना है। इसमें विभाग के साथ कार्य कर रही संस्थाएँ जैसे सम्पर्क फाऊंडेशन, प्रथम जो 'असर'की रिपोर्ट जारी करती है, हुमाना पीपल टू पीपल, एससीएफ आदि के साथ एक संयुक्त कमेटी बनाकर कार्य किया जाएगा ताकि 2025-26 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुचित योजना बनाई जा सके।

6. **स्कूल कॉम्पलेक्सिस और रेशनलाइज़ेशन-** इसके लिए डीएसई, डीईई, एसपीडी कार्यालय के द्वारा समुचित कार्यवाही की जानी है। इसमें एसपीडी कार्यालय से प्लानिंग के सलाहकार तथा शैक्षणिक शाखा से सहायक निदेशक के साथ वर्क्स ब्रांच की, समग्र शिक्षा की सिविल विंग की संयुक्त कमेटी बना जानी है, जो इस पर विभाग को अक्तूबर, 2020 तक पूरी योजना प्रस्तुत करेगी।

7. **विद्यालय प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा-** इस मामले में 2025-26 तक कार्य किया जाना है। वर्तमान में एनएसक्यूएफ कक्षा नौंवी से बारहवीं के लिए है, इसका विस्तारीकरण कक्षा 6वीं से किया जाना है। अतः एसपीडी कार्यालय की एनएसक्यूएफ शाखा तथा शैक्षणिक शाखा मिलकर इस पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। यह कमेटी स्किल डिवेल्पमैंट डिपार्टमैंट, टेक्नीकल एजुकेशन के साथ मिलकर अपनी योजना प्रस्तुत करेगी जिसमें कक्षा छठी से आठवीं के लिए कौन-कौन से कोर्स आरम्भ किए जाएँ, उनका चयन करेगी और क्रियान्वयन की योजना बनाएगी, जिसे सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। यह कमेटी डीईई तथा एसपीडी के नेतृत्व में कार्य करेगी।

8. **शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहुविषयक एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम-** इस विषय पर कार्य करने के लिए एससीईआरटी, प्रारम्भ संस्थान झज्जर तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की एक संयुक्त कमेटी बनाए जाने का प्रस्ताव है जो एनसीटीई से मार्गदर्शन लेकर कार्य करेगी।

9. **परीक्षा का माध्यम-** पाँचवी कक्षा तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। राज्य में इस समय अधिकतर प्राइवेट स्कूल जो सीबीएसई, आईसीएसई, हरियाणा बोर्ड व अन्य बोर्ड से हैं, वहाँ शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है। राज्य सरकार द्वारा भी 'बैग फ्री इंग्लिश मीडियम वियद्यालयों' की स्थापना की गई है। इस विषय को लेकर एक कमेटी बनाई जानी प्रस्तावित है जिसमें सभी बोर्डों से चर्चा करके, प्राइवेट विद्यालयों के संगठनों से चर्चा करके निर्णय लिया जाना है।

10. **चार वर्षीय अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम-** इस पॉलिसी में बीएड कार्यक्रम चार वर्षीय बनाया गया है। राज्य में जो डाइट और गैटी संचालित हैं उनको लेकर भी निर्णय लेना होगा। इसके लिए एससीईआरटी, प्रारम्भ संस्थान झज्जर तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की एक संयुक्त कमेटी बनाए जाने का प्रस्ताव है जो एनसीटीई से मार्गदर्शन लेकर कार्य करेगी।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

# बाल्यावस्था देखभाल एवं प्रारंभिक शिक्षा को लेकर हुए महत्त्वपूर्ण प्रावधान

**अरुण कुमार कैहरबा**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा ढाँचे में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव है। इसमें 10+2+3 के शैक्षिक ढाँचे को पूरी तरह बदल दिया गया है। पहले 10+2 स्कूली शिक्षा से संबंधित था और जमा 3 स्नातक की पढ़ाई के लिए दिया गया था। 10+2 के अनुसार पढ़ाई छह साल से शुरू होती थी। शिक्षा के अधिकार को लेकर किए गए संविधान संशोधन में भी छह से 14 साल तक की शिक्षा को अधिकार बनाया गया। बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भी छह साल की उम्र में पहली कक्षा से लेकर 14 साल तक आठवीं कक्षा तक शिक्षा को अधिकार में शामिल किया गया था। अब स्कूली ढाँचा 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि अब स्कूली शिक्षा को 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए बाँटा गया है। इसमें तीन से लेकर आठ साल के बच्चों के लिए पाँच साल की नर्सरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, आठ से 11 साल के बच्चों के लिए तीसरी से पाँचवीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौवीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। यह महत्त्वपूर्ण है कि देश में अधिकतर बच्चों की शिक्षा ढ़ाई-तीन साल की उम्र में ही शुरू होती है। साधन-सम्पन्न वर्ग काफी पैसा खर्च करके नर्सरी या प्री-प्राइमरी प्ले स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराता है। निजी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग से सुसज्जित भवन बनाए गए हैं, जहाँ पर केजी, एलकेजी व यूकेजी आदि कक्षाएँ लगाई जाती हैं। विभिन्न चरणों से होते हुए बच्चे पहली कक्षा तक पहुँचते हैं। इन निजी संस्थानों की अलग-अलग श्रेणियाँ हैं तथा गुणवत्ता व शुल्क के भी कई स्तर हैं। बहुत से स्कूलों में लाखों रुपये की डोनेशन फीस जमा करवाकर बच्चों को दाखिल करवाया जाता है। अधिकतर निजी स्कूलों में पालकों पर आर्थिक बोझ तो बहुत अधिक पड़ता है, लेकिन पढ़ाई की बात करें तो ऊँची दुकान-फीके पकवान वाली कहावत चरितार्थ होती है।

कहने को तो सरकारी स्तर पर भी आँगनवाड़ियाँ बनाई गई हैं, जोकि बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पोषाहार, स्वास्थ्य आदि के लिए ही शुरू हुई थीं। शिक्षाविदों और बाल-विशेषज्ञों ने इसकी जरूरत और गुणवत्ता को रेखांकित किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को दिए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों के कारण वे पढ़ाई का कार्य नहीं करवा पाती हैं। आँगनवाड़ी केंद्र में सुविधाओं का अभाव व गैर-शैक्षणिक कार्यों में कर्मियों की अत्यधिक व्यस्तता के कारण समाज के एक हिस्से ने तो उनसे पूरी तरह मुँह मोड़ लिया है। बहुत कम उम्र में ही निजी संस्थानों में चले गए बच्चों का अपने स्कूलों के साथ लगाव भी होता है और फिर पहली कक्षा में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होने के बावजूद उनका

सरकारी स्कूलों में आना संभव नहीं हो पाता। सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम होती संख्या का यह एक बड़ा कारण साबित होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राजकीय पाठशालाओं के अध्यापकों ने प्रयास न किए हों। प्रावधान नहीं होने के बावजूद बहुत सारे राजकीय स्कूलों ने अपने स्तर पर नर्सरी कक्षाएँ चलाई हैं। इसके लिए पंचायतों व समुदाय का सहयोग लेकर स्वैच्छिक शिक्षकों को भी रखा जाता है। जिन स्कूलों ने अपने स्तर पर पहलकदमी करते हुए यह व्यवस्था की है, उन स्कूलों में बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए दाखिल किए गए बच्चों को मिड-डे-मील से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके लिए औपचारिक रूप से व्यवस्था नहीं होने के बावजूद आपसी सहयोग से अध्यापक यह प्रबंध करते हैं। अध्यापक लंबे समय से प्राथमिक स्कूलों में नर्सरी कक्षाएँ लगाए जाने और उसके लिए अध्यापकों की व्यवस्था करने की माँग कर रहे हैं।

अब जब यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी थी तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा ढाँचे में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए तीन से छह साल तक के बच्चों को समाहित करना एक सुखद अहसास कराने वाला है। हालांकि यह भी तय है कि इसे लागू करने में जितनी देरी होगी, उतना ही नुकसान बढ़ता जाएगा। नीति में कहा गया है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास छह वर्ष से पहले ही हो जाता है। इसलिए बच्चों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए जीवन के पहले छह वर्ष काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं। समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण समाज के सबसे वंचित वर्ग के बच्चे गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस तरह से वे समान रूप से शिक्षा प्रणाली में हिस्सा लेने के अपने अधिकार से भी वंचित हो रहे हैं।

शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को सीखने की नींव बताया गया है। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जो करोड़ों बच्चे गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई से वंचित हो रहे हैं, उनके लिए निवेश को बढ़ाने की बात भी की गई है। ईसीसीई के लिए दो भागों में उत्कृष्ट पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक ढाँचा विकसित करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी गई है। पहले भाग में 0-3 वर्ष तक के बच्चों के लिए सब-फ्रेमवर्क और दूसरे भाग में 3-8 वर्ष तक के लिए सब-फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसके लिए बाल्यावस्था में देखभाल के लिए स्थानीय परंपराओं और भारत में प्राचीन काल से चली रही परंपराओं के अनुकूल राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय नवाचार पर शोध किया जाएगा। ईसीसीई में कला-शिल्प, कहानियाँ, कविता, गीत और खेल सब कुछ शामिल होंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए विकसित किया जाने वाला यह मॉडल माता-पिता और आँगनवाड़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेगा। इसके लिए उच्चतर गुणवत्ता के ईसीसीई संस्थान स्थापित किए जाएँगे, जिनके द्वारा ईसीसीई प्रणाली को पहले से चल रहे आँगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों में चल रहे आँगनवाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक पाठशालाओं, प्री-प्राइमरी स्कूलों, प्ले स्कूलों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके लिए ईसीसीई पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित कर्मचारियों व शिक्षकों की भर्ती करने की बात भी कही गई है।

लचीली, बहु आयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित व खोज आधारित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकास एवं शिक्षण-विधि की सारी जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी। ईसीसीई का स्कूलों में सहज एकीकरण एवं मार्गदर्शन को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी। ईसीसीई के आयोजन एवं क्रियान्वयन में शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय मिलकर कार्य करेंगे।

वर्तमान में आँगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों की शिक्षा के जिन विविध पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की बात की गई है। मजबूत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के अभाव में बहुत से बच्चे बुनियादी साक्षरता व भाषा ज्ञान व संख्या ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। वर्तमान प्राथमिक पाठशालाओं में पूरे देश में ऐसे बच्चों की अनुमानित संख्या 5 करोड़ है। यह सीखने की एक गंभीर समस्या है। यह समस्या बाल्यावस्था को बोझिल बनाते हुए निराशा से भर देती है और अंत में बच्चे ड्रॉपआउट हो जाते हैं। शिक्षा नीति में तीसरी कक्षा तक अनिवार्य रूप से मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अभियान बनाए जाने का संकल्प किया गया है। इसके लिए 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया गया है और इसके लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की भी बात की गई है। इस महत्त्वपूर्ण एवं महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निश्चय ही स्कूलों में अध्यापकों की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके लिए अध्यापकों की भर्ती और प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात 30:1 से कम और जिन स्कूलों में वंचित समुदाय के बच्चों की अधिकता होती है, उनमें यह अनुपात 25:1 से कम होगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में बच्चों को पारंगत बनाने के लिए सतत रचनात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाए जाने और बच्चों के सीखने को ट्रैक करने की नीति अपनाई जाएगी। द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर इससे संबंधित उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री का राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध करवाया जाएगा। अध्यापकों के सतत व्यावसायिक विकास एवं प्रशिक्षण के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों के सीखने को आनंददायी बनाने के लिए अध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन में पीयर ट्यूटरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

शिक्षा नीति में पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पुस्तकालयों को विकसित करने और नए पुस्तकालयों की स्थापना और उनमें बालोपयोगी उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनकी स्वास्थ्य जाँच नियमित रूप से की जाएगी।

बच्चों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए और सीखने को बढ़ावा देने के लिए पौष्टिक भोजन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। गरीबी और बेरोजगारी की दशा का बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज भी बहुत से बच्चे भूखे पेट स्कूलों में आते हैं। उनके लिए मिड-डे-मील ही सहारा होता है। मिड-डे-मील योजना को बढ़ाने के लिए माध्याह्न भोजन के साथ-साथ पौष्टिक नाश्ते की जरूरत को शिक्षा नीति ने रेखांकित किया है। सुबह के भोजन के लिए भोजन पकाने की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में अन्य पोषाहार व फल आदि उपलब्ध करने की बात की गई है।

इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 स्कूली शिक्षा में बहुत से महत्त्वपूर्ण प्रावधान कर रही है। तीन वर्ष के बच्चों के प्रति प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के रूप में राष्ट्रीय जिम्मेदारी का विस्तार करके महत्त्वपूर्ण प्रावधान कर रही है। हालांकि इसको स्कूलों के साथ समेकित किया जाना भी बहुत जरूरी है। आँगनवाड़ियाँ स्कूलों से अलग-थलग नहीं होनी चाहियें। इसे शीघ्रता से लागू किए जाने की तरफ बढ़ना चाहिए।

**हिन्दी प्राध्यापक**
**राजकीय उच्च विद्यालय, करेड़ा खुर्द**
**खंड-जगाधरी, जिला-यमुनानगर**

# जनाकांक्षाओं के अनुरूप बनी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति

भारत में 34 वर्षों बाद शिक्षा नीति में बदलाव आया है। अब तक हमारी शिक्षा-नीति दस जमा दो के फॉर्मेट पर चलती थी, और अब पाँच जमा तीन जमा तीन जमा चार के फॉर्मेट पर बदल दिया गया है। इसे बदलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हायर एजुकेशन तक केवल 27 प्रतिशत बच्चे ही पहुँच पाते थे। स्नातक करने के बाद भी छात्रों में कोई स्किल नहीं होती थी, जिससे उन्हें रोज़गार मिल सके। हमारी शिक्षा-नीति रटंत विधि पर आधारित थी। पाठ्यक्रम अधिक होने के साथ-साथ ज्यादातर, प्रासंगिक भी नहीं था। प्रैक्टिकल न होने के कारण, छात्रों में आत्मविश्वास की कमी थी। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के छात्रों में गहरी खाई थी। अब पूरे भारत वर्ष में, सिलेबस एक जैसा कर दिया गया है। स्किल्ड स्कूली शिक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा ताकि शिक्षा रोज़गार दे सके। अब छात्र स्कूल से निकलेगा तो स्किल्ड होगा। अब साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स को एक समान समझा जाएगा और सभी विषयों को समान अहमियत दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाएगा। बच्चों के मानसिक स्तर पर सुधार लाया जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई में रुचि विकसित की जाएगी व नैतिकता की शिक्षा प्रारंभ से दी जाएगी। अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रथम पाँच साल को फाउंडेशनल स्टेज का नाम दिया है, यानि बच्चे की नींव मज़बूत की तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्री-प्राइमरी में बच्चे खेल-खेल में सीखेंगे। किताबों का बोझ कम किया जाएगा। नर्सरी से दूसरी क्लास तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में करवाई जाएगी। इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे आएँगे। इसके उपरांत तीसरी, चौथी तथा पाँचवीं कक्षा की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाए जाएँगे। इसमें छात्र 8 से 11 वर्ष की उम्र के होंगे। कॉर्पोरल पनिशमेंट को अपराध समझा जाएगा। 6-8 कक्षा के छात्रों को निश्चित पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाएगा, जिसमें लगभग सभी विषय होंगे तथा वोकेशनल कोर्सेस का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। कम्प्यूटर शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छात्र आठवीं कक्षा तक कोई न कोई वोकेशनल स्किल में निपुण हो जाएगा।

नौवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई में सभी स्ट्रीम में से, अपने मनपसंद विषयों का चयन कर सकेंगे यानि साइंस का विद्यार्थी इतिहास तथा राजनीतिक शास्त्र के साथ एकाउंट्स भी पढ़ सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि विषयों के ज्ञानार्जन के साथ-साथ, शिक्षा रोज़गारपरक बनाने में विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा का माध्यम हिन्दी व अंग्रेज़ी रहेगा। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा यानी रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। परीक्षा का भय समाप्त किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहले 6 से 14 वर्ष था और अब 3-18 वर्ष कर दिया गया है। मिड-डे-मील में ब्रेकफास्ट को भी शामिल करने का प्रपोज़ल है। स्कूल कॉम्प्लेक्स की फ़ैसिलिटी को एक्टिविटी के लिए आसपास के स्कूलों के साथ जोड़ा जाएगा। अध्यापकों को कॉन्ट्रैक्ट की बजाय उन्हें परमानेंट नौकरी देने का भी सुझाव है।

कॉलेज में दाखिले के लिए कैट यानी कि कॉमन एप्टीट्यूट टेस्ट होगा जिसमें बारहवीं कक्षा के अंक तथा कैट के अंकों को मिलाकर विश्वविद्यालय व कॉलेज में बहुस्तरीय परीक्षा एवं निकासी व्यवस्था की गई है। जिसमें स्नातक तक की पढ़ाई 3 तथा चार वर्ष की होगी जिसमें प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट कोर्स, द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा तीसरे वर्ष में स्नातक डिग्री कर सकेंगे। इसमें विभिन्न विषय पढ़ाए जाएँगे तथा अपनी रुचि के आधार पर छात्र विषय का चुनाव कर सकेंगे। सभी विषयों की महत्ता एक समान होगी। चौथे वर्ष में पीएच-डी कर सकेंगे, इसमें अब एमफिल की जरूरत नहीं रहेगी। नई शिक्षा नीति ग्लोबल स्तर पर भी मददगार रहेगी। छात्र देश-विदेश में अपना भविष्य निर्धारित कर सकेंगे। स्कूलों, कॉलेजों में काउंसलर्स की भूमिका अहम रहेगी तथा उनकी क्षमता व ज्ञान के आधार पर उन्हें रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा। प्राइवेट तथा सरकारी स्कूलों की फीस को भी निर्धारित किया जाएगा जिससे प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे।

हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जैसे हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती है। नई शिक्षा नीति को मद्देनज़र रखते हुए, हमें देश की गरीबी का भी ध्यान रखना चाहिए। कई गाँवों के विद्यालयों में तो सामान्य सुविधाओं का भी अभाव है। उन पर विशेष ध्यान देना होगा।

अगर पाठ्यक्रम में बदलाव लाना है तो पुस्तकों को उपलब्ध कराना, कम्प्यूटर शिक्षा का इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में कर पाना, एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण इलाकों में अगर कंप्यूटर की व्यवस्था भी की भी जाती है तो स्कूल समय में बिजली की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। बदलाव हमेशा अखरता है, मगर दूरगामी परिणाम अच्छे ही होते हैं। अतः हम सबको सकारात्मकता के भाव से, नई शिक्षा नीति का स्वागत करना चाहिए तथा इसको लागू करने में हरसंभव प्रयत्न करना चाहिए।

**इंद्रा बेनीवाल**
**उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा**

## बजघेड़ा, गुरुग्राम के शिक्षक

# मनोज लाकड़ा को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो आज भी शिक्षण कार्य का सामाजिक दायित्व के रूप में निर्वहन करना पसंद करते हैं। शिक्षण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर न केवल अपने विषय का बल्कि अन्य विषयों को भी सुगम बनाने का प्रयास करते रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2020 प्राप्त मनोज लाकड़ा ऐसे ही शिक्षक हैं। 5 सितंबर 2020 का शिक्षक मनोज लाकड़ा और उनके परिवार के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण रहा है। वे अपनी परिवार में 'राष्ट्रपति पुरस्कार' प्राप्त करने वाले दूसरे सदस्य बने। गौरतलब है कि उनके पिता श्री सूरत सिंह को भी 1972 में तत्कालीन राष्ट्रपति सम्मानित कर चुके हैं।

मनोज कुमार शिक्षक तो हिंदी के हैं लेकिन अपनी प्रयोगधर्मिता व पेशे के प्रति समर्पण के बूते विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने सफलता की कई इबारतें लिख डाली हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें विज्ञान विषय बहुत पसंद था, लेकिन उन्हें इस विषय में उच्चतर शिक्षा हासिल करने का मौका नहीं मिल सका। वे कई वर्षों से विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा को तराशने का काम कर रहे हैं। कई विद्यार्थियों को उनके मार्गदर्शन में सफलता मिली है। ऐसे में उन्होंने अपने स्कूलों के विद्यार्थियों को विज्ञान की नई खोजों के लिए प्रेरित करने का काम किया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने कई एप व प्रोजेक्ट बनाए, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।

मनोज लाकड़ा के मार्गदर्शन में उनकी कक्षा के 4 छात्रों द्वारा मिड-डे-मील हरियाणा ऐप को डेवलेप किया गया जिसे हरियाणा के हजारों शिक्षकों के साथ-साथ अन्य राज्यों के शिक्षकों को भी काफी फायदा हुआ। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के इस एप को अपनाया गया वह सभी सरकारी विद्यालय में लागू किया गया। इसके साथ-साथ अध्यापक मनोज लाकड़ा के मार्गदर्शन में इन छात्रों ने समग्र मूल्यांकन, ऑफिस रजिस्टर, फंड एवं स्टॉक रजिस्टर ऐप, स्काउट व गाइड ऐप, प्रगति पथ एप को तैयार किया। विद्यालय वेबसाइट, ई-मैग्जीन, सरकारी विद्यालयों की गूगल मैपिंग आदि अनेक कार्यों में इन छात्रों ने मनोज लाकड़ा के मार्गदर्शन में कार्य किया। इन छात्रों सहित मनोज लाकड़ा को तत्कालीन हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। छात्रों के लिए अपने स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी सफल आयोजन मनोज लाकड़ा के द्वारा किया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्तर जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता, एससीईआरटी-एनसीईआरटी में लगातार तीन वर्ष पुरस्कार हासिल कर उनके छात्रों ने इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इनमें मुख्य बात सोलर हेलमेट के निर्माण की रही। इसकी विशेषता यह है कि जब तक आप इसको नहीं लगाओगे तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इससे बाइक चोरी की घटनाएँ नहीं होंगी व बाइक सवार के लिए हेलमेट की अनिवार्यता हो जाएगी।

मनोज कुमार लाकड़ा को किर्गिस्तान स्थित ओश स्टेट विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'सतत विकास में शिक्षा का महत्त्व' विषय पर अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसमें शिक्षा-दीक्षा के आठ अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। इस गोष्ठी में 24 देशों के शिक्षाविदों ने भाग लिया था। उन्होंने 'सतत विकास में शिक्षा की भूमिका' विषय पर अपना शोध-पत्र प्रस्तुत किया था।

उनके द्वारा बिना बिजली के मोबाइल टीवी का निर्माण किया गया, जिससे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को आसानी से स्मार्ट कक्षा में बदला जा सकता है। इसमें बिजली कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने इस मोबाइल टीवी को हरियाणा के अनेक विद्यालयों में अपने जेब खर्च से उपलब्ध करवाया है।

आजकल वे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुरुग्राम जिले के बजघेड़ा विद्यालय में मौलिक मुख्याध्यापक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। उनकी कार्य शैली दूसरों के लिए प्रेरणा है। उन्हें बहुत-बहुत बधाई।

**हरपाल आर्य**
**प्राथमिक अध्यापक**
**राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला**
**काकड़ोली हुकमी**
**चरखी दादरी, हरियाणा**

# बुक-बैंक बनवाकर बचा लिए नन्ही आँखों के सतरंगी ख्वाब

**अंबाला जिले के विद्यालयों में चल रहा है बुक बैंकों की स्थापना का अनूठा अभियान, संयुक्त निदेशक सतिंद्र सिवाच की प्रेरणा व प्रयासों से हुआ संभव**

**डॉ. प्रदीप राठौर**

विद्यालय का नया सत्र माता-पिता के कंधों पर ढेर सारा आर्थिक बोझ लेकर आता है। निजी विद्यालयों के संदर्भ में बात करें तो अभिभावकों को दोहरी मार पड़ती है। प्रतिवर्ष बढ़ने वाली फीस और लगातार महँगी हो रही पुस्तकों को खरीदने का खर्च उनकी कमर तोड़ देता है। एनसीईआरटी की पुस्तकें सब प्रकार से श्रेष्ठ व सस्ती होने के बावजूद सभी निजी विद्यालयों में प्राइवेट प्रकाशन की पुस्तकें लगाई जाती हैं। ऊपर से प्रतिवर्ष उन पुस्तकों में आंशिक परिवर्तन भी कर दिए जाते हैं ताकि पिछली कक्षा की पुस्तकें घर में किसी छोटे भाई-बहन के भी काम न आ सकें और मजबूरन माता-पिता को नई किताबें खरीदनी पड़ें। कमाई के इस खेल में प्रकाशक, मुद्रक, विक्रेता के तो वारे-न्यारे होते ही हैं, विद्यालय प्रबंधकों और संचालकों को भी मोटा कमीशन मिलता है। एक सामान्य आदमी पिसता है तो पिसता रहे, करोड़ों पुस्तकें प्रतिवर्ष रद्दी में तबदील होती हैं तो होती रहें, लाखों टन कागज़ के निर्माण में जंगलों का सफाया होता है तो होता रहे, चिंता किसे?

### अब नहीं होती सेंकेंड हैंड किताबों की खरीद-फरोख्त-

एक ज़माना था जब पुरानी पुस्तकों की खरीद-फरोख्त की प्रथा समाज में प्रचलित थी। सरकारी विद्यालयों में पढ़ी पिछली पीढ़ी इस बात को जानती है। सत्र के बाद विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा समूह अपनी पिछली कक्षा की पुस्तकों को आधे दामों पर बेच कर नई कक्षा की पुस्तकें आधे दामों में खरीद लेता था। यह प्रथा समाज में आम प्रचलन में होने के कारण किसी प्रकार की हीनता का भाव किसी के मन में न आता था। लेकिन अब समाज में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।

### आठवीं तक दी जाती हैं निःशुल्क पुस्तकें -

अगर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की बात करें तो यहाँ आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की ओर से पुस्तकें मुहैया कराई जाती हैं। जब नई पुस्तक निःशुल्क मिल रही हो तो कोई पुरानी पुस्तक का उपयोग क्यों करेगा ? क्या यह बात विचारणीय नहीं कि पुस्तकों को हर वर्ष प्रकाशित करने के स्थान पर इनका पनः उपयोग अनिवार्य कर दिया जाए। पाँचवीं कक्षा तक की बात करें, छोटे बच्चे अक्सर जल्दी ही पुस्तकों की दशा बिगाड़ देते हैं, लेकिन छठी या इससे ऊपर की कक्षाओं की पुस्तकों का तो आसानी से दोबारा इस्तेमाल हो सकता है।

### क्यों न हर विद्यालय में हो 'बुक बैंक'?

कितना अच्छा हो कि सभी विद्यालयों में 'बुक बैंकों' की स्थापना की जाए। कक्षा उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में जाने वाले विद्यार्थी अपनी पुस्तकें बुक बैंक में जमा करा दें। उस कक्षा में आए नये विद्यार्थियों को ये पुस्तकें वितरित की जा सकती हैं। बताने की आवश्यकता नहीं हैं कि हमारे देश में आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो साधन-सम्पन्न नहीं है। परिवारों की आर्थिक अक्षमता बच्चों की शिक्षा को अधर में छोड़ने का बड़ा कारण बनती है। ऐसे

यह अत्यंत उत्साहजनक है कि विद्यालयों के मुखियाओं ने अपने विद्यालयों में बुक बैंक स्थापित करने के मेरे विचार को पूरे मनोयोग के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। निजी स्कूल संघ व अंबाला-1 के खंड शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा का इस अभियान को आगे बढ़ाने में मुझे पूरा सहयोग व समर्थन मिला। बुक बैंकों की स्थापना से पुस्तकों का पुनर्प्रयोग होगा जिससे न केवल कागज़ और पेड़ों की बचत होगी बल्कि पर्यावरण व राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण भी होगा। इससे विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना भी विकसित होती है। आज के स्वार्थ और आपाधापी के जमाने में विद्यार्थियों के मन को इस दिशा में संवेदनशील बनाना अत्यावश्यक है। विद्यालयों को चाहिए कि वे बुक-बैंकों के अलावा 'यूनिफार्म बैंकों' की स्थापना भी करें। अंबाला में सफलतापूर्वक चल रहे इस अभियान को अब उच्चाधिकारियों से परामर्श करके पूरे प्रदेश में चलाने का प्रयास किया जाएगा।

**- सतिंद्र सिवाच,**
**संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा**

में ये 'बुक बैंक' उनके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। एक पुस्तक कम से कम तीन वर्ष तक इस्तेमाल की जा सकती है। इस लिहाज से देखें तो एक छोटी सी शुरुआत से हम अपने कितने संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं।

आठवीं तक की पुस्तकें भले ही निःशुल्क मिलती हों, नौवीं से बारहवीं की पुस्तकें तो राजकीय विद्यालयों में भी विद्यार्थियों को स्वयं खरीदनी पड़ती हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में वर्तमान में नौवीं से बारहवीं कक्षा में 6,19,256 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक विद्यार्थी को आठ से दस पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं। अगर हर विद्यार्थी नई पुस्तक खरीदे और इनका पुनः उपयोग न हो तो हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में ही कक्षा नौवीं से बारहवीं की लगभग 60 लाख पुस्तकें प्रतिवर्ष रद्दी बन जाएँगी। इतनी पुस्तकों के निर्माण में हजारों टन कागज़ प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाएगा। अगर आठवीं तक की पुस्तकों की प्रतिवर्ष छपाई को भी इसमें जोड़ा जाए तो आँकड़ा और भी बढ़ जाएगा। जिस देश के भू-क्षेत्रफल पर वनों का क्षेत्र सिमटकर केवल 24.39 रह गया हो (ISFR -India State of Forest Report 2017) वहाँ यह बात कितनी चिंतनीय हो सकती है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण के तीन 'आर' (रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज़) पर्यावरण में बढ़ रहे अपशिष्ट को कम करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। जहाँ तक पुस्तकों का प्रश्न हैं इनके रिसाइकल होने से पहले इनका आसानी से रियूज़ भी हो सकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो न केवल कागज की खरीद और छपाई पर होने वाला करोड़ों का खर्च बचेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की ओर भी यह एक बड़ा कदम होगा। वृक्ष कटने से बचेंगे, कागज़ बनाने की प्रक्रिया में खतरनाक रसायन नदियों में घुलकर पानी को विषैला नहीं बनाएँगे। गौरतलब है कि 'नेशनल ग्रीन टिब्यूनल, नई दिल्ली' द्वारा राज्यों को बार-बार सुझाव दिए जाते हैं कि वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरानी पुस्तकों का पुनर्प्रयोग करने की नीति बनाई जाए।

कई बार प्रेरणा की एक छोटी सी थपकी ऐसे उत्साहजनक परिणाम दे देती है जो कई बार कड़ी भाषा वाले प्रशासनिक आदेशों के बावजूद भी नहीं मिलते। यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिला है। श्री सतिंद्र सिवाच की प्रेरणा का ही प्रभाव था कि हम इस अभियान को सफल बनाने में जी-जान से जुट गए। अभियान के प्रति उनका समर्पण व जुनून का भाव हमारे लिए पग-पग पर प्रेरक बना। निजी विद्यालयों ने भी अपने कमीशन का लालच छोड़कर हमारे इस अनुरोध को माना कि वे हर वर्ष पाठ्यपुस्तकें भी नहीं बदलेंगे, ताकि बुक बैंक की पुस्तकें अगले वर्ष विद्यार्थियों के काम आती रहें। निश्चित तौर पर इसके लिए अंबाला के निजी विद्यालय संघ को भी साधुवाद देना चाहूँगा।

**-सुधीर कालड़ा**
**उप जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला**

## अंबाला में आरंभ हुई एक अनूठी मुहिम-

सरकारी व निजी विद्यालयों में ऐसे बुक बैंक स्थापना की मुहिम अंबाला में 2018 में आरंभ की गई। इसके सूत्रधार थे वहाँ के तत्कालीन उपमंडल अधिकारी (नागरिक) श्री सतिंद्र सिवाच। दरअसल 'विद्यालय सुरक्षा मानकों' पर आयोजित मासिक बैठक में उन्होंने पहली बार खंड शिक्षा अधिकारी अंबाला (1) श्री सुधीर कालड़ा तथा निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों के सामने यह विचार रखा कि क्यों न यहाँ के निजी व राजकीय विद्यालयों को बुक बैंकों की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए।

यदि विचार नेक हो और लागू करवाने वाले की मंशा निःस्वार्थ एवं उदारता से युक्त हो तो उसे आगे बढ़ाने में विशेष मशक्कत नहीं करनी पड़ती। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। विचार का एक सुर में स्वागत हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी ने इसी विषय को लेकर निजी विद्यालयों की बैठक बुलाई। राजकीय विद्यालयों की बजाय निजी विद्यालयों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि किताबें बेचने के नाम पर सबसे ज्यादा धंधेबाजी यहीं पर होती है।

प्रयासों का सुखद परिणाम यह हुआ कि पहले ही वर्ष यानी 2018 में खंड के 43 विद्यालयों में बुक बैंकों की स्थापना हो गई। विशेष बात यह रही कि इनमें से ज्यादा संख्या (28) निजी विद्यालयों की थी। विद्यालयों में एक अध्यापक को बुक बैंक का इंचार्ज बनाया गया जिसका नाम व संपर्क सूत्र खंड शिक्षा कार्यालय में भी उपलब्ध रहा। पुस्तकों के लेन-देन का बाकायदा रिकॉर्ड रखा गया। अल्प समय में ही खंड के 327 विद्यार्थियों ने अपनी 2950 पुस्तकें बुक बैंकों में जमा कराईं, जिन्हें अगले सत्र में ग्रीष्मावकाश से पहले जरूरतमंद विद्यार्थियों में वितरित कर दिया। यह आँकड़ा सभी के उत्साहवर्धन के लिए काफी था।

अभियान आशातीत सफलता से आगे बढ़ रहा था। शनैः-शनैः बुक बैंक वाले विद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही थी। चूंकि अभियान किसी सरकारी आदेश पर नहीं, बल्कि प्रेरणा और प्रोत्साहन की नींव पर टिका था, इसलिए निर्णय लिया गया कि इसमें सराहनीय कार्य करने वाले विद्यालयों को सम्मानित किया जाए। 10 अगस्त, 2018 को पंचायत भवन, अंबाला शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन करके 43 सराहनीय कार्य करने वाले विद्यालयों के मुखियाओं या प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, इस अभियान में सर्वाधिक योगदान देने वाले मुरलीधर डीएवी विद्यालय अंबाला शहर के बुक-बैंक इंचार्ज मदनलाल को तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित कराया गया।

अपने हाथों से रोपे गए पौधे को अपनी आँखों के सामने विकसित होता देख कर जो संतोष व प्रसन्नता होती है, वैसी ही अनुभूति श्री सिवाच को हो रही थी। वे लगातार जिले के शिक्षा अधिकारियों के संपर्क में रहकर अभियान की प्रगति की जानकारी लेते रहते और कार्यालयीन व्यस्तता से जब भी समय मिलता विद्यालयों में जाकर बुक-बैंक देखते, विद्यालय मुखिया और बुक-बैंक प्रभारी से बात करके उन्हें अधिकाधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ने की प्रेरणा देते। इन सब का परिणाम यह हुआ कि अगले ही सत्र में बुक बैंक स्थापित करने वाले विद्यालयों की संख्या का आँकडा 80 के पार हो

गया, जिनमें 2,575 बच्चों ने स्वेच्छा से अपनी 11,787 पुस्तकें दान में दीं।

श्री सिवाच द्वारा रोपे गए पौधे के संरक्षण में वहाँ के तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुधीर कालड़ा की विशेष भूमिका रही। इसी बीच सितंबर 2019 में श्री कालड़ा उप जिला शिक्षा अधिकारी बन गए तथा श्री सिवाच निदेशालय माध्यमिक शिक्षा में संयुक्त निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ देने लगे। मुहिम को आगे बढ़ाने वाले अधिकारीद्वय के पदनाम परिवर्तित हुए, लेकिन लक्ष्य नहीं।

फरवरी, 2020 तक अंबाला जिले में 3,621 विद्यार्थियों ने 20,092 पुस्तकें बुक बैंकों में जमा कराईं, जिन्हें 4,107 जरूरतमंद विद्यार्थियों में वितरित किया गया। जिन विद्यार्थियों को ये पुस्तकें मिलीं, निश्चित तौर पर उनमें से अनेक विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ चादर से सिर ढाँपने के प्रयास मे पाँव नंगे हो जाते होंगे, जिनके अभिभावक तन काटकर, अपनी लालसाओं का गला घोंटकर अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे होंगे। यह 'सहायता' उनके लिए कितनी लाभकारी रही होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

एक बार फिर महसूस किया गया कि अभियान को गतिमान रखने के लिए सतत प्रोत्साहन की जरूरत है। फलस्वरूप पीकेआर जैन विद्यालय अंबाला में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन सभी विद्यालयों के मुखियाओं को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपने-अपने विद्यालयों में 'बुक-बैंक' स्थापित किए थे। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में शरीक हुए श्री सिवाच ने सभी को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए तथा उनके प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए और अधिक मजबूती से इस मुहिम को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। जिन आठ विद्यालयों का प्रदर्शन उच्च कोटि का रहा, उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सारा खर्च रोटरी क्लब द्वारा उठाया गया जो इस बात की ओर इंगित करता है कि जब कोई अभियान जनहित व समाज-सेवा से जुड़ा हो तो बहुत सी समाज-सेवी संस्थाएँ भी स्वेच्छा से सहायता का हाथ बढ़ाने लगती हैं। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल श्रेष्ठ कार्य करने वालों का हौसला बढ़ाना था, बल्कि उनके माध्यम से अन्य विद्यालयों को भी संदेश देना था कि वे भी इस मुहिम से पूरे मन से जुड़ें।

विराट उद्देश्य को लेकर चल रहे इस अभियान को साधारण नहीं कहा जा सकता। यह दरअसल एक क्रांति है, भले ही यह एक छोटे से जिले में ही हुई हो। साढ़े तीन हज़ार विद्यार्थियों ने बुक-बैंकों में अपनी पुस्तकें दान में देकर एक साथ साधन-विपन्न समुदाय के प्रति जिम्मेदारी, सामाजिकता, समाज-सेवा, पर्यावरण संरक्षण का जो व्यावहारिक पाठ सीखा, वह निःसंदेह किसी पुस्तकीय पाठ पढ़ने से ज्यादा उनके जीवन के लिए उपादेय साबित होगा।

मुहिम का प्रसार सतत जारी है, अंबाला-1 खंड से आरंभ होते हुए अब यह धीरे-धीरे अंबाला के सभी छह खंडों में फैल गई है। प्रकारान्तर से कहें तो बुक-बैंक अभियान रूपी पौधा पल्लवित-पुष्पित होकर सुखद फल प्रदान करने की स्थिति में आ गया है। लेकिन अभी, न तो इसके प्रसार और विकास की संभावना थमी है, और न ही इस अभियान रूपी पौधे के बीज-रोपण करने वाले अधिकारी का उत्साह और जुनून। कोई विचित्र बात न होगी अगर शीघ्र ही इस अभियान का प्रचार-प्रसार आपको पूरे प्रदेश में देखने को मिले।

**drpradeeprathore@gmail.com**

# दीक्षा: अध्यापक क्षमता विकास के लिए ऑनलाइन मंच

मनोज कौशिक

दीक्षा (DIKSHA- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा हेतु विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह एक ऐसा अनुकूलन-योग्य नेशनल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर है जिसका उपयोग राज्य अपने शिक्षक और छात्र केंद्रित पहल (student-centric initiative) के लिए कर सकते हैं। यह शिक्षकों और छात्रों को सभी भारतीय भाषाओं में सभी विषयों और स्तरों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और आकलन संसाधनों तक पहुँचने और निर्मित करने में सक्षम बनाता है।

दीक्षा-हरियाणा का उद्देश्य शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें डिजिटल शिक्षण, अधिगम एवं प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शिक्षकों और छात्रों के लिए राज्य में सीखने के परिणामों (लर्निंग आउटकम्स) की गुणवत्ता और वितरण को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन मंच है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में, दीक्षा-हरियाणा को राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी), हरियाणा द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में लॉन्च किया गया है।

## दीक्षा का कार्य क्षेत्र-

दीक्षा के अंतर्गत मुख्यतः सात क्षेत्रों में कार्य किया जाता है-

1. शिक्षक प्रोफ़ाइल और रजिस्ट्री- दीक्षा पोर्टल या एप पर शिक्षक अपना प्रोफाइल एक उपयोगकर्ता के रूप में बना सकते हैं। अपने पसंदीदा लॉग इन क्रेडेंशियल्स के साथ स्वतंत्र रूप से डिजिटल विषय-वस्तु का निर्माण कर सकते हैं।
2. शिक्षण और शिक्षण सामग्री- दीक्षा पर एक इंटरैक्टिव और आकर्षक प्रारूप में शिक्षकों और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम से जुड़े संसाधन उपलब्ध हैं।
3. सामग्री निर्माण मंच- डिजिटल पठन-पाठन सामग्री बनाने और अपलोड करने के लिए उपकरण और प्लेटफार्म उपलब्ध हैं।
4. शिक्षक व्यावसायिक विकास- शिक्षकों को उनके व्यावसायिक विकास में सहयोग के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम संचालित करना दीक्षा का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है।
5. नवाचार और अभिनव शिक्षाशास्त्र- केस स्टडी, शोध पत्र और नवीन शैक्षणिक प्रथाओं के माध्यम से शिक्षक समुदाय के बीच सर्वोत्तम प्रयोगों और अनुभवों को साझा करने की सुविधा है।
6. आकलन- स्कूल स्तर के आकलन के लिए शिक्षकों, छात्रों के लिए संसाधन और उपकरण भी दीक्षा पर उपलब्ध हैं।
7. स्कूल नेतृत्व विकास- प्राचार्यों, उप-प्रधानाचार्यों और स्कूलों के प्रमुख की मदद करने के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रमों का भंडार, उनके नेतृत्व कौशल में सुधार करता है।

## मोबाइल के लिए दीक्षा:

दीक्षा प्लेटफॉर्म शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। अपने पाठों की आसान पहुँच के लिए दीक्षा ऐप डाउनलोड करें और अपनी पाठ्यपुस्तकों में क्यूआर कोड को स्कैन करें।

## ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ओसीबीपी)-

एससीईआरटी ने शिक्षकों की सेवाकालीन शिक्षा को संस्थागत बनाने के लिए एक गंभीर प्रयास किया है, क्योंकि यह उनके पेशेवर विकास के लिए एक आवश्यक घटक है। इसने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के आगमन के साथ,परंपरागत एवं आधुनिक तकनीक में संतुलन रखा है और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता और मात्रा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईसीटी के उपयोग को अधिक और प्रभावी तरीकों से तलाशना जारी रखा है। अध्यापकों के क्षमता विकास के लिए ऑनलाइन

कोर्सेज की शुरुआत एससीईआरटी द्वारा 2018-19 में हो गयी थी जब एलईपी पर आधारित दो ऑनलाइन कोर्सेज, सक्षम-अध्यापक (चॉकलिट) एप के माध्यम से सभी प्राइमरी शिक्षकों व प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराये गए। इस प्रयास को सभी प्रतिभागियों का समर्थन प्राप्त हुआ और अगले वर्ष ही विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों के लिए एनसीईआरटी के लर्निंग आउटकम पर आधारित चार ऑनलाइन कार्यक्रम, एससीईआरटी में चुने हुए अध्यापकों और विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार कर लागू कर दिए गए। इस वर्ष इन सभी प्रशिक्षण सामग्रियों का परिवर्धित रूप नए कोर्सेज के साथ दीक्षा पोर्टल व एप पर उपलब्ध होगा।

### दीक्षा ऑनलाइन कोर्सेज-

दीक्षा पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करती है। पंजीकृत उपयोगकर्ता इन पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं या जिस संस्थान से जुड़े हैं, उनके द्वारा पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निम्न प्रकार के पाठ्यक्रम दीक्षा पर उपलब्ध हैं:

मेरा पाठ्यक्रम (माई कोर्सिस): यह श्रेणी आपके द्वारा किए गए पाठ्यक्रम की सूची को आंशिक रूप से पूरा कर चुकी है या हाल ही में शामिल हुई है। इस सूची में वे पाठ्यक्रम भी शामिल है जिसमें आपको शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

मेरे राज्य का पाठ्यक्रम (माई स्टेट कोर्सिस): यह श्रेणी उपयोगकर्ता के राज्य द्वारा बनाए और अपलोड किए गए राज्य-विशिष्ट पाठ्यक्रम की सूची प्रदर्शित करती है। यह सूची केवल उस विशिष्ट राज्य में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए दिखाई देती है। यदि आप एक प्रमाणित राज्य उपयोगकर्ता के रूप में लॉग इन करते हैं, तो आप किसी भी बैच के लिए पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं जो नामांकन के लिए खुला है। सूची शीर्ष पर सबसे हाल ही में निर्मित पाठ्यक्रम प्रदर्शित किए जाते हैं।

चुनिंदा पाठ्यक्रम (फीचर्ड कोर्सिस): यह श्रेणी सभी उपलब्ध पाठ्यक्रम को प्रदर्शित करती है, चाहे जिस भी संगठन ने इसे बनाया हो। कोई भी लॉग-इन उपयोगकर्ता इस श्रेणी में दिखाए गए पाठ्यक्रम में शामिल हो सकता है।

नवीनतम पाठ्यक्रम (लेटेस्ट कोर्सिस): यह श्रेणी सबसे हाल ही में दीक्षा में जोड़े गए पाठ्यक्रम की एक सूची प्रदर्शित करती है।

### दीक्षा कोर्स ज्वाइन कैसे करें? -

दीक्षा कोर्स ज्वाइन करने के लिए यह आवश्यक है कि आप एक पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में लॉगइन हैं, और आपने कोर्स टैब पर टैप किया है। कोर्स पेज पर-

1. विशेष कोर्स श्रेणी के तहत कोर्स के लिए ब्राउज़ करें
2. कोर्स देखने के लिए सामग्री कार्ड पर टैप करें
3. कोर्स डिटेल पेज प्रदर्शित किया जाता है
4. ज्वाइन कोर्स पर टैप करें

दीक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता हैं। जब आप सफलतापूर्वक एक अनुशंसित पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, तो एक ईमेल अधिसूचना और / या एसएमएस को पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा यह सूचित करने के लिए भेजा जाता है कि प्रमाण पत्र तैयार होते हैं और डाउनलोड किए जा सकते हैं। आप इन प्रमाणपत्रों को पीडीएफ फाइलों के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट कर सकते हैं और अपने मोबाइल ऐप के साथ प्रमाणपत्रों पर मुद्रित क्यूआर कोड को स्कैन करके उन्हें सत्यापित कर सकते हैं। एक बार जब आप इन प्रमाणपत्रों को सत्यापित कर लेते हैं, तो वे आपकी प्रोफ़ाइल पर प्रकाशित हो सकते हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं को दिखाई देते हैं।

प्रशिक्षण में शिक्षकों की रुचि एवं व्यस्तता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीकों से घटनाओं और ऑनलाइन गतिविधियों का संचालन किया जाता है :

1. **प्रशिक्षण संबंधी संदेश :** शिक्षकों को प्रशिक्षण की घटनाओं और प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए उनसे संबंधित नियमित संदेश भेजे जाते हैं।
2. **व्हाट्सएप ग्रुप :** शिक्षकों के लिए व्हाट्सएप समूह बनाया गया है, जहाँ प्रशिक्षण संबंधी प्रश्नों का उत्तर पाया जा सकता है। जैसे- स्कूल के नाम, कक्षाओं में क्या भरना है। ऐप के साथ तकनीकी दिक्कतों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिये जाते हैं।
3. **मेंटर सहयोग :** बीआरपी, एबीआरसी तथा डाइट्स विशेषज्ञ ऑनलाइन कोर्सेज के दौरान हमारे अध्यापकों के मेंटर्स का कार्य करते हैं। मेंटर प्रतिभागियों के सवालों और चिंताओं का जवाब देने और उन्हें पूरा करने और साझा करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करते हैं। प्रशिक्षण की पूर्णता के लिए सहयोग प्रदान करना और कम प्रतिशत पूरा करने वाले शिक्षकों को फॉलो-अप करने के लिए नियमित संपर्क करना आदि मेंटर्स के कार्य में सम्मिलित है।

दीक्षा एप या पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। एससीईआरटी द्वारा 13 जुलाई, 2020 से **सवाल पूछने के कौशल** नामक कोर्स से इसका शुभारम्भ हो चुका है। राष्ट्रीय दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध अति उपयोगी एवं गुणवत्ता वाले 13 कोर्सेज का चयन विशेषज्ञों द्वारा कर एक तय समय-सारिणी के तहत शिक्षकों की क्षमता निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। समय-समय पर शिक्षकों, प्रशिक्षकों तथा शिक्षा अधिकारियों की आवश्यकतानुसार, राज्य स्तर पर तैयार गुणवत्ता पूर्ण सामग्री सभी को दीक्षा ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में मिलती रहेगी।

**नोडल कोऑर्डिनेटर**
**दीक्षा, हरियाणा**

# हिंदी है जन-जन की भाषा

सुरेश राणा

भाषा भावों, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा सर्वव्यापी है। यह हमारे विचार,स्वप्न, वार्तालाप, उपासना, प्रार्थना और संचार सबमें उपस्थित है। भाषा ही किसी देश की सच्ची पहचान, उस देश की सभ्यता-संस्कृति की संवाहिका होती है। किसी भी देश की वैचारिक एवं सामाजिक एकता का आधार भाषा ही तो होती है। बिना भाषा के समाज और देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा ही किसी भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती है।

हिंदी विशाल जन-समूह की भाषा है। हिंदी हमारे जीवन-मूल्यों, संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कार की संवाहिका है। हिंदी भारत का स्वाभिमान है,गरिमा है। भारत के सांस्कृतिक वैभव, राष्ट्रीय गौरव और अस्मिता को बचाने में हिंदी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। धर्म, अध्यात्म, दर्शन तथा साहित्य के क्षेत्र में पहले जो कार्य संस्कृत भाषा ने किया, वही कार्य आज हिंदी भाषा कर रही है।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था, अगर हम भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है।

देश आजाद हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया। आजादी के आंदोलन में हिंदी देश की राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक रही है। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कहा था- प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। अपनी प्रान्तीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न ही हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं। पर सारे प्रान्तों की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिला है।

हिंदी एक उदार भाषा है जो विभिन्न भाषाओं की की अच्छाइयों को आत्मसात् किए हुए है। हिंदी का विशाल फ़लक देश की विभिन्न बोलियों के शब्दों को आत्मसात् कर ही रहा है, विदेशी भाषाओं के शब्द भी इसमें समाहित होते जा रहे हैं। हिंदी के कई रूप देश की अनेक बोलियों में बिखरे पड़े हैं। हम हिंदी को इन बोलियों से अलग करके नहीं देख सकते देश की एकता-अखंडता और हिंदी की समृद्धि के लिए यह अच्छा भी है। विश्व कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर बंगाली थे, किंतु वे भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर देखना चाहते थे। टैगोर ने कहा था- भारतीय भाषाएँ नदियाँ हैं, जबकि हिंदी महानदी है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विरोध इसलिए नहीं है,क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य अध्यात्ममूलक है। सभी में रामकथा है, सन्त की महिमा है व भौतिक तथा अध्यात्म का समन्वय है। महात्मा गाँधी जी का भी कहना है ,जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो, वह अत्यंत ही पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा ठहर ही नहीं सकती।

अनेक विदेशी विद्वानों ने भी हिंदी को विश्व की एक श्रेष्ठ भाषा बताया है। विद्वान जॉन ग्रिलक्राइस्ट के अनुसार मानव के से मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमाला

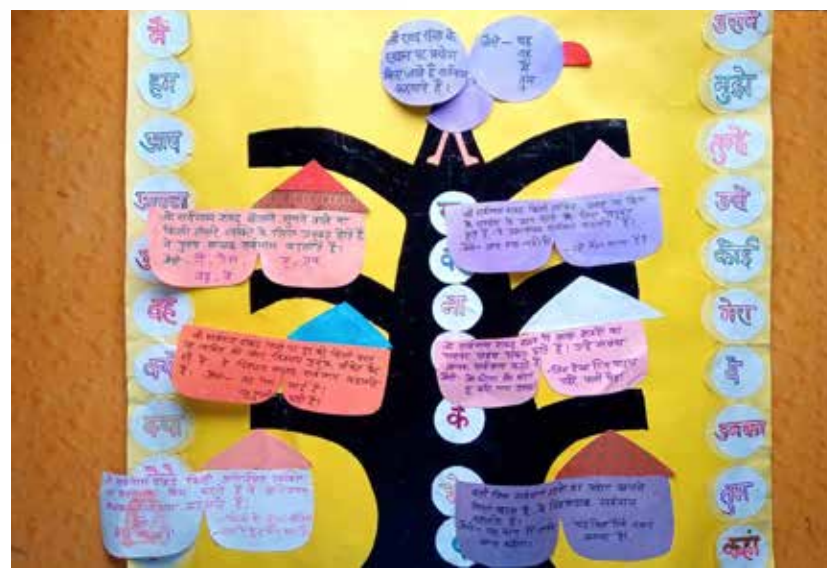

में देवनागरी सर्वाधिक पूर्ण वर्णमाला है। हिंदी के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी हिंदी कोश के रचयिता फादर कामिल बुल्के ने लिखा है, विश्व में कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो सरलता और अभिव्यक्ति की क्षमता में हिंदी की बराबरी कर सके। इसकी लिखाई और उच्चारण में आश्चर्यजनक अनुरूपता है। अंग्रेज विद्वान टॉमस ने लिखा है- मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक या बंग से सिंध के मुहाने तक इस विश्वास के साथ यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएँगे, जो हिंदी बोल लेते होंगे।

हिंदी का विशाल साहित्य एवं शब्द-भंडार अत्यंत विस्तृत है, व्याकरण सरल तथा तर्कसंगत है। इसकी लिपि देवनागरी अत्यंत सुगम, बोधगम्य एवं कलात्मक है। हिंदी पूरी तरह से ध्वनि और उच्चारण आधारित भाषा है, जिसमें लगभग सभी ध्वनियों को अभिव्यक्त करने व सम्प्रेषित करने की क्षमता है।

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में हिंदी वैश्विक स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। हिंदी अब केवल हिन्द की ही भाषा नहीं रही अपितु सुदूर फिजी से लेकर सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना, नेपाल आदि देशों में बोली जाती है। हिंदी भाषी देशों के आलावा अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा आदि देशों में प्रवासी भारतीयों के कारण हिंदी अपना परचम लहरा रही है। दुनिया में हिंदी की महत्ता दिनोंदिन बढ़ रही है, इसका खुमार वैश्विक स्तर पर सर चढ़कर बोल रहा है। देवनागरी लिपि के कारण इसे इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी तथा जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक लोकप्रियता मिली है।

हिंदी को विश्वव्यापी बनाने में मीडिया, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया आदि के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता। फिल्में, चित्रपट, छोटा परदा, हिंदी गीत इसके प्रचार-प्रसार का माध्यम बन रहे हैं तथा हिंदी को आमजन और विश्व की भाषा बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। दूरदराज मेघालय के चेरापूँजी में टैक्सी चालक हिंदी गाने बड़े चाव से गाता है तो सुदूर तमिलनाडु का मछुआरा बड़े शौक से हिंदी गाने सुनता है। यह और बात है कि दोनों ठीक से हिंदी बोल नहीं पाते परन्तु दोनों ही हिंदी गानों का आनन्द उठाते हैं।

हिंदी अब रोजगार एवं तकनीक की भाषा बन चुकी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए हिंदी को बेहिचक अपनाती जा रही हैं। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो विश्व में हिंदी बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं, जो एक बहुत बड़ा बाज़ार उपलब्ध करवाते हैं। विश्व को बाज़ारवाद के दबाव के चलते कारोबार, खेल, विज्ञान आदि से जुड़ी जानकारियों को हिंदी में परोसने पर विवश होना पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, अलीबाबा जैसी अनेक विश्व स्तरीय कम्पनियाँ व्यापक बाज़ार पर भारी मुनाफे को देखते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख ने हिंदी जानने समझने के लिए विवश कर दिया है।

वर्तमान समय में हिंदी सुदृढ़ होकर उभर रही है। हिंदी अपने व्यावहारिक गुण, वैज्ञानिक लिपि, समृद्ध साहित्य के कारण अपने विकास के लिए अपार सम्भावनाएँ खोज सकती है। लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे परन्तु हिंदी विश्व में नए आयाम स्थापित करती रहेगी। हिंदी में वैश्विक भाषा बनने की क्षमता है। जैसे-जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, हिंदी का वर्चस्व बढ़ेगा।

**हिंदी प्राध्यापक**
**राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय**
**कमालपुर, खण्ड- कलायत, कैथल, हरियाणा**

## आने वाला दशक हिंदी का होगा

यदि कंप्यूटर की मौलिक अवधारणाएँ हिंदी में आने लगें और हिंदी में ही प्रोग्रामिंग हो तो आने वाला दशक हिंदी का है। साथ ही हिंदी को वैश्विक बाजार भी मिलना जरूरी है। संचार क्रांति के दौर में सभी भाषाओं का क्रांतिकारिक विकास हुआ है। इनमें हिंदी सबसे ऊपर है। आज अंग्रेजी चैनलों को हिंदी में प्रसारण और अंग्रेजी प्रकाशकों को हिंदी में प्रकाशन करने पर मजबूर होना पड़ा है। बीबीसी, स्टार, नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी जैसे चैनल अपने कार्यक्रमों को हिंदी में डब करके प्रसारित कर रहे हैं। पैंगुविन जैसे प्रकाशकों ने हिंदी में पुस्तकें छापनी शुरू कर दी हैं। दुनिया के लगभग 122 देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। यह सच है कि आज दुनियाभर के अलावा दक्षिण भारत में भी लोग हिंदी का ट्यूशन ले रहे हैं। दुनियाभर में हिंदी रोजगार की भाषा बनकर उभर रही है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि आज बड़ी से बड़ी हॉलीवुड की फिल्में रिलीज होते ही हिंदी में डब की जाती हैं, जिसके लिए दुनियाभर में हिंदी के जानकार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। जन-जीवन के बीच हिंदी का वर्चस्व बहुत है। देश के अंदर भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। लेकिन अधिकतर काम सहभाषा अंग्रेजी में होता है। इस कार्यप्रणाली में बदलाव जरूरी है। अब नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद यह तय है कि आने वाला दशक हिंदी का होगा।

**माधव कौशिक**
**राष्ट्रीय उपाध्यक्ष**
**साहित्य अकादमी**

# कोरोना महामारी का दौर और बच्चों की शिक्षा

विश्व व्यापी कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। दुनिया भर में लाखों लोग इसके शिकार हो चुके हैं। हजारों लोग जान गँवा चुके हैं। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए समस्त भारत में लॉकडाउन करना पड़ा। जनता कर्फ्यू से शुरू करके लॉकडाउन और फिर बाद में अनलॉक के विभिन्न चरण हो चुके हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद हुए थे। स्कूल खुल भी गए, लेकिन स्कूलों में बच्चों के आने और उनकी शिक्षा का रास्ता नहीं खुल पाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोरोना महामारी से शिक्षा-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।

महामारी से पूर्व अध्यापक स्कूलों में हर रोज बच्चों के साथ सीखने-सिखाने की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते थे। स्कूल से जाने के बाद अगले दिन की योजना को लेकर चिंतन-मनन करना व योजनाएँ बनाना आए दिन का कार्य था। बच्चों का हर्षोल्लास व रंग-उमंग स्कूल के वातावरण को जीवंतता प्रदान करते थे। प्रातःकालीन सभा में कक्षावार पंक्तिबद्ध होकर सभी बच्चों का खड़े होना। अध्यापकों द्वारा उठाई गई सावधान-विश्राम की तान पर विद्यार्थियों का कदम-ताल करना। नन्हें-नन्हें हाथों को जोड़कर एक सुर में प्रार्थना, राष्ट्रगान व चेतना गीत गाना। चेतना जगाने वाले नारों से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देना। अध्यापकों के दिशा-निर्देश और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए पीछे समय अधिक होने की खुसर-फुसर शुरू हो जाना। सभा के समापन पर विद्यार्थियों का फौजियों की तरह कदम-ताल करते हुए कक्षाओं की तरफ आगे बढ़ना। कभी अध्यापकों के निर्देश पर प्रांगण में स्वच्छता अभियान चलाना। और कभी पूरे जोशो-खरोश के साथ खेल के मैदान में उतर पड़ना। पुस्तकालय में किताबें ढूँढ़ते और पढ़ते बच्चे। कई बार बच्चों का आपस में लड़-झगड़ पड़ना। उस झगड़े को सुलझाने की तरह-तरह की युक्तियाँ लड़ाते हम अध्यापक। अध्यापक के कक्षा में पहुँचने से पहले बच्चों का ऊँचा उठता शोर, जिससे कई बार पड़ोस की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों और अध्यापकों को परेशानी होती। कई बार समय पूरा होने के बावजूद कक्षा से दूसरे अध्यापक का न निकलना और कक्षा-कक्षा के बाहर इंतजार करते हुए होने वाली उकताहट। कई बार समय पूरा होने पर विषय पूरा नहीं होने या फिर हो रही गर्मागर्म चर्चा के बीच में रुकने का अफसोस। बाहर खड़े अध्यापक द्वारा दरवाजा खटखटाकर बताना कि इस कक्षा में आपका एक कालांश पूरा हो चुका है और अब बारी उनकी है। पढ़ने-पढ़ाने की क्रियाओं के बीच समय का इशारा करने वाली घंटी की स्वरलहरियाँ। निश्चय ही आधी छुट्टी और पूरी छुट्टी की घंटी बच्चों के लिए विशेष महत्त्व रखती है। पूरी छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चों का कुलांचें भरते और शोर करते हुए घरों की तरफ दौड़ना। अध्यापकों के आपसी संवाद से सीखने-सिखाने की क्रियाओं को जिंदादिल बनाने की जरूरत पर चर्चाएँ करना। खाली समय में बैठ कर चाय की चुस्कियाँ लेना। आधी छुट्टी में बच्चों को खाना खिलाने के लिए लाइन बनाने की मशक्कत।

रंग-बिरंगी किताबें पढ़ने, बातें करने, कहानियाँ, कविताएँ, संस्मरण, जीवन अनुभव पर चर्चाएँ और विभिन्न विषयों के सीखने-सिखाने की सामूहिक क्रियाओं से सभी को ऊर्जा मिलती थी।

लॉकडाउन के दौरान हम सब उससे वंचित हुए। सारा दिन घर में रहने की बोरियत से परेशान भी हुए। अब स्कूल में जाते भी हैं तो स्कूल में वह जान नहीं है, जो

बच्चों के साथ होती है। कोई बच्चा या उसके अभिभावक जब स्कूल में कभी आते भी हैं तो उनके चेहरों पर वह चमक नहीं होती। अभिभावकों के चेहरों पर उनके जीवन के संकट होते हैं। कई दिन तक काम-काज नहीं लगने के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। व्हाट्सअप ग्रुप या टेलिविजन के चैनलों पर चल रही पढ़ाई बारे उनसे बात होती है। कुछ बच्चों को छोड़ दें तो अधिकतक बच्चों के लिए शिक्षा का यह मार्ग सुगम नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप में भेजी जा रही वीडियो, ऑडियो, पाठ्य सामग्री आदि के प्रयोग के बारे में जब बात होती है तो कई बार बच्चे सारी स्थिति के बारे में नहीं बता पाते। कई बार कई भाई-बहनों के लिए एक मोबाइल फोन होने, नेट पैक नहीं होने, नेटवर्क नहीं आने, वीडियो नहीं खुलने, काम के दौरान मोबाइल पिता द्वारा ले जाने सहित अनेक प्रकार की मुश्किलें सामने आती हैं। उनके चेहरे से निराशा दूर करने के लिए यही कहना पड़ता है कि कोई बात नहीं, आप अपनी किताब से कुछ न कुछ पढ़ते रहा करें।

महामारी के इस संकट में व्हाट्सअप ग्रुपों में अध्यापकों द्वारा अंधाधुंध सामग्री भेजे जाने की स्थिति पर चिंता होती है। यह भी चिंता होती है कि ऑनलाइन शिक्षा के ऐसे दौर में उन बहुत से बच्चों का क्या होगा, जिनके पास मोबाइल की सुविधा ही नहीं है। घर में टेलिविजन भी नहीं है। ऐसे में अध्यापकों द्वारा यदि सिलेबस निपटा दिए जाने की बातें की जा रही हैं तो उसका उन बच्चों के लिए क्या मतलब है।

कुछ अभिभावकों ने तो यह भी बताया कि उनके बच्चे मोबाइल तो लेकर रखते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करने की बजाय कार्टून या अन्य चीजें देखने में करने लगे हैं। ऐसे में कहीं ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को गहरे गर्त में तो नहीं धकेल देगी? जिस मोबाइल से आज तक बचने के उपदेश दिए जाते थे, एक दम उसे शिक्षा का माध्यम बना देने की सैद्धांतिक बातें तो ठीक हैं, लेकिन इसे क्रियान्वित करने की मुश्किलों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

हालांकि बच्चों की सुरक्षा व स्वास्थ्य हम सबका ध्येय है। हमारे बच्चे किसी भी प्रकार के वायरस व अन्य असुरक्षित वातावरण के खतरों से बचे, यह महत्त्वपूर्ण है। इसके बावजूद बच्चों की अनुपस्थिति से बेजान हुए स्कूल से अध्यापकों में निराशा का माहौल है। ऐसे में जब बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं तो बच्चों की हुड़दंग से बहुत से अभिभावक भी परेशान हैं। उन्हें बच्चों को रचनात्मक कार्यों में लगाए रखने के तरीकों का नहीं पता है। ऐसे में बच्चों की ऊर्जा किसी न किसी तरीके से निकलती ही है।

उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही कोरोना वायरस व इससे उपजी महामारी को भी मानवता जल्द परास्त करके आगे बढ़ेगी। स्कूलों में बच्चों की आवाजाही और शिक्षा सुचारु होगी। कोरोना महामारी ने स्कूलों व शिक्षा संस्थानों के सामने एक नई चुनौती पेश की है। जब भी स्कूल खुलेंगे तो वायरस के बचाव के लिए कक्षाओं का स्वरूप भी बदल जाएगा। मास्क लगाना एक अनिवार्यता होगी। चिकित्सकों द्वारा सुझाए जा रहे अच्छी किस्म के सुविधाजनक मास्क सभी बच्चों को उपलब्ध करवाए जाने चाहियें ताकि वे इसका नियमित रूप से प्रयोग कर सकें। बच्चों में शारीरिक दूरी बनाए रखना भी आसान काम नहीं होगा। स्कूलों में स्वच्छता और कक्षा-कक्षा को सेनिटाइज करना होगा। आने वाले समय में स्कूलों को तैयार करने के लिए इच्छाशक्ति के साथ-साथ संसाधनों की भी जरूरत होगी।

**अरुण कुमार कैहरबा**
**हिन्दी प्राध्यापक**
**राजकीय उच्च विद्यालय, करेड़ा खुर्द,**
**खंड-जगाधरी, जिला-यमुनानगर, हरियाणा**

# गीता-ज्ञान

कुरुक्षेत्र की भूमि पै कुंतीपुत्र करे सवाल
श्री कृष्ण बोले हे अर्जुन! खोल बता दूँ सारा हाल।
जीवन क्या है कहो पुरुषोत्तम, जो कलंक बिना जिया जा सै,
मृत्यु क्या है कहो भगवन्, इस देह का त्याग किया जा सै,
मोक्ष बिना यहाँ क्या मिलता, हट-हट के जन्म लिया जा सै,
मोक्ष मिले इसा भेद बता दो, जब तत्व ज्ञान पिया जा सै,
श्रीकृष्ण बोले बात सुनो, खोल बता दूँ सारा हाल।

कौन बता है आदि-अजर, है अन्तर्यामी रूप मेरा,
कौन बता है ब्रहमा, ऊँ अक्षर का नाम धरा,
कौन बता अध्यात्म है, ये जीव आत्मा स्वरूप तेरा,
कौन बता संन्यासी है, जिसने मोह-माया का त्याग करा,
जीवन मरण छूट जा, जिसके लगी तत्व ज्ञान की बाल,
श्रीकृष्ण बोले बात सुनो, खोल बता दूँ सारा हाल।

सबसे प्यारा कौन जगत में, कर्म ही साथी होया करै,
मृत्यु बाद साथ ना छोड़े, वो धर्म हिमायती होया करै,
शुभ कर्मों से क्या मिलता है, मनुष्य की जाति होया करै,
मनुष्य जन्म ले अधर्म करता, वो खुद का घाती होया करै,
पाँचों का रंग मन पै चढ़जा तो, मन कपटी है चंडाल,
कुरुक्षेत्र की भूमि पै कुंतीपुत्र करे सवाल।

क्यों होती आसक्ति भगवन्, ध्यान विषयों में करने से,
काम क्रोध क्यों पैदा होते, कामना के विचरने से,
मोह माया का जाल बता क्यूँ, इन्द्रियों के वरने से,
इन्द्री कैसे वश में हों, वैराग्य के करने से,
कहै रामनिवास तू धनुष उठा ले, बाट देख रहा उनकी काल,
कुरुक्षेत्र की भूमि पै कुंतीपुत्र करे सवाल।

**रामनिवास**
**अधीक्षक**
**कार्यालय मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला**

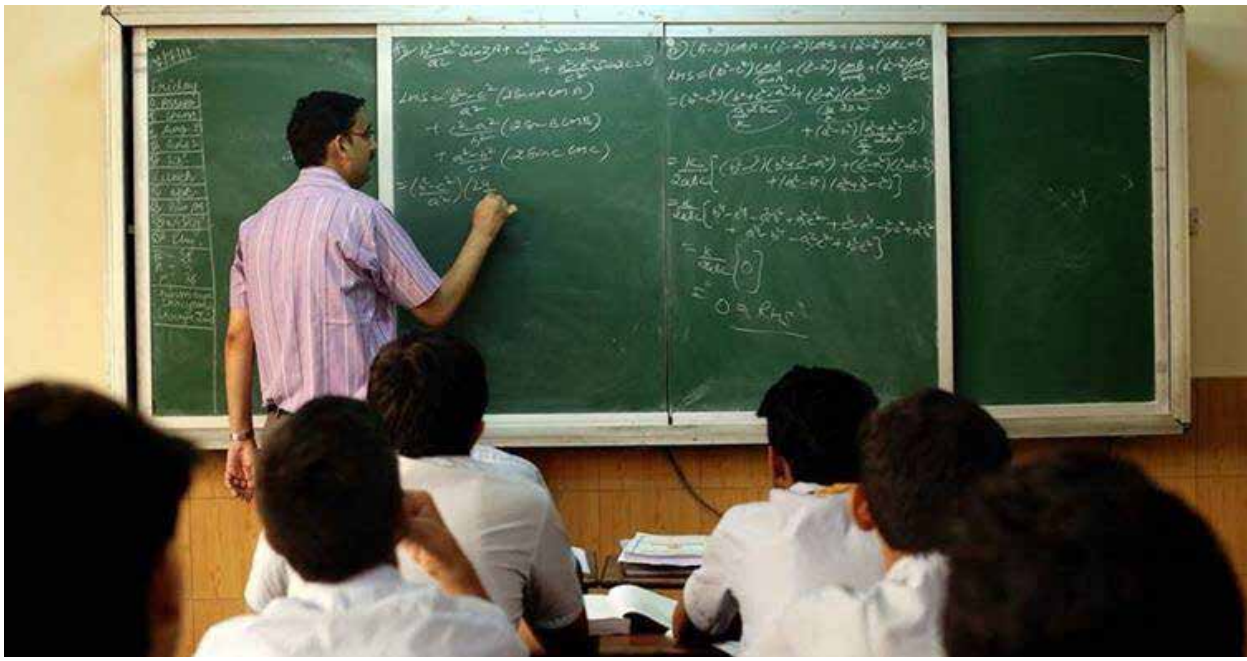

# शिक्षक की पाती अपने प्यारे विद्यार्थियों के नाम

**प्रिय बच्चो,**

**सदैव प्रसन्न रहो।**

प्रिय बच्चो! जब नन्हे पाँवों से तुम शाला की सीढ़ियाँ नापते तो तुम्हारे नन्हें पाँव वामन की तरह विराट विश्व को नापते लगते। तुम्हारे मुख मंडल पर खिली मुस्कान बरबस ही मेरे मुस्कराने का कारण बन जाती। सुबह-सुबह तुम्हारा मुझे नमस्कार करना, जय हिन्द करना किसी शिशु का माँ पुकारने पर माँ की भाँति खुश होने जैसा आह्लादित महसूस करता हूँ।

प्रार्थना सभा में जब पूरे जज्बे, जोश और जुनून से तुम प्रार्थना करते तब तुम अपने को देश के अच्छे नागरिक के रूप में गढ़ रहे प्रतीत होते।

कहने को मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, किंतु जाने-अनजाने न जाने कितनी बार मैं तुमसे शिक्षा ग्रहण करता रहता हूँ। कभी किसी का तेजस्वी आत्मविश्वास मुझे चमत्कृत करता, तो कभी किसी की विलक्षण अभिव्यक्ति क्षमता अभिभूत कर देती। कभी किसी की उज्ज्वल सोच मेरे चिंतन को स्फुरित करती, तो कभी सम्मानवश मेरे लिए लाए फूल मुझे शब्दहीन कर देते।

तुम्हारी स्फूर्ति-ऊर्जा से मुझे ऊर्जा मिलती। मैं सारे समय तरोताजा महसूस करता। तुम्हारी खिलखिलाहट, सजीवता और सक्रियता मेरे जीवन में खिलखिलाहट, सजीवता और सक्रियता लेकर आती। सच पूछो तो तुम मेरे जीवन में संजीवनी बूटी की तरह होते। तुम्हीं से मैं जीवन रस प्राप्त करता रहता।

रविवार और अन्य अवकाश के दिन घर पर काटे नहीं कटते। शाला के दिन सूरज जल्दी उगता ही नहीं लगता। शाला जाने की ललक मन में यों थाटें मारती कि मानों पंख होते तो उड़कर शाला पहुँच जाता। जानते हो ऐसा क्यों होता? केवल तम्हारे मासूम चेहरे पर खिली तुम्हारी निश्छल मुस्कान और तुम्हारी ठहाकेदार हँसी का दीदार करने। और इसलिए भी कि तुम्हें बताने के लिए मेरे पास बातों का एक पूरा पहाड़ होता।

कक्षा में पढ़ाते-पढ़ाते जीवन के अनुभव साझा करता। पाठ्य सामग्री के इतर भी जीवनोपयोगी बातें बताता। तुम्हारा इन सब बातों को ध्यान से सुनना मुझे आश्वस्त करता। तुम निश्चित ही एक दिन अपने माता-पिता के लाड़ले बनकर बताओगे और उनके सपनों के साथ खुद के भी सपने पूरा करोगे यह मुझे आश्वस्त करता।

तुम्हारी आँखों में सपनों के समंदर साफ नजर आते तो हृदय से कोटि-कोटि आशीर्वाद निकलते। शिक्षक होने का अनुपम अहसास सुखद अनुभूति कराता। कई बार डाँटता, दुख भी होता पर तुम कभी अन्यथा न लेते। मेरे प्रति सम्मान की भावना में कमी नहीं आती। मैं भावनाओं के अतिरेक में बोलता रहता अनवरत-अनथक...! ताकि तुम्हारे मन के तारों को झंकृत कर सकूँ और ओजस्वी बना सकूँ।

मेरे सुयोग्य सुशील बच्चो! तुम मेरे शिक्षक होने की सबसे अहम वजह होते। तुम्हारे धैर्य, अनुशासन और गरिमा से ही मेरी समझ, वैचारिकता और अभिव्यक्ति क्षमता समृद्ध और विस्तारित होती ।

तुम्हारी प्रफुल्लता ही मेरे अध्यापन की प्रेरणा बनती। तुम्हारी प्रखर मनीषा और जिज्ञासु संस्कार ही मुझे निरंतर पठन-अध्ययन के लिए प्रेरित-प्रोत्साहित करते। तुम्हारी जिज्ञासा और मेरे प्रति तुम्हारा सम्मान मेरे विश्वास को बढ़ाता। तुम्हारे होने से मेरा होना सार्थक होता।

जब तुम शाला छोड़ जाते तो साथ में छोड़ जाते तुम्हारी हँसी, ऊर्जावान चेहरे, शक्ति सम्पन्न शरीर का अहसास, जीवटता, जुझारूपन और उत्तरोत्तर उन्नति की अभिलाषा। यह सब मुझे जीवंत बनाए रखते, शाला को शाला बनाए रखते। तुम्हारे बिना न मैं शिक्षक रह पाता, न ही शाला शाला रह पाती।

मेरे बच्चो! तुम्हारी सफलता उत्तरोत्तर उन्नति, विकास और सम्मानजनक मुकाम हासिल करने में ही मेरा सच्चा सम्मान और संतोष निहित होता। इसमें तुम्हारा शिष्यत्व और मेरा शिक्षकत्व दोनों ही सार्थक हो उठते। और तुम इसे पूरा करने हेतु पूरे प्राणपन से जुट जाते। सस्नेह। शुभकामनाओं सहित।

**गोपाल कौशल**

**नागदा, जिला- धार, मध्य प्रदेश**

# लॉकडाउन में रचा अनूठा बाल साहित्य

शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति से जुड़े बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार **सत्यवीर नाहड़िया** ने कोरोनाकाल के अंतर्गत लॉकडाउन में बच्चों के लिए पर्यावरण, दिवस विशेष तथा महापुरुषों पर केंद्रित प्रेरक साहित्य रचा है। रेवाड़ी जिले के खोरी स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बतौर रसायनशास्त्र प्राध्यापक सेवारत श्री नाहड़िया इससे पूर्व दोहा, कुंडलिया, रागनी मुक्तक, आल्हा आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में करीब एक दर्जन कृतियाँ दे चुके हैं। हाल ही में प्रकाशित उनकी ये तीनों बाल कृतियाँ शिक्षा विभाग के लिए अनूठी सौगात हैं।

'पंचतत्व की पीर' पुस्तक में जहाँ श्री नाहड़िया ने पर्यावरण पर आधारित बाल दोहावली के माध्यम से पर्यावरण के घटक, पर्यावरण असंतुलन के कारण तथा संरक्षण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, वहीं 'दिवस खास त्योहार' नामक कृति में उन्होंने वर्ष भर स्कूलों में मनाए जाने वाले विभिन्न दिवसों, जयंतियों तथा पुण्यतिथियों के संदर्भ में बेहद रोचक एवं ज्ञानवर्धक बाल कविताएँ लिखी हैं। इसी प्रकार तीसरी कृति 'रचा नया इतिहास' में उन्होंने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के महापुरुषों के अलावा स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रीय कवि-लेखकों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों के संदर्भ में दोहों के माध्यम से प्रेरक परिचय लिखे हैं।

इन तीनों बाल कृतियों की विशेषता यह है कि इनकी भाषा बेहद सरल एवं सहज है तथा सभी रचनाएँ छंदबद्ध एवं रोचक होने के चलते बच्चों की जुबान पर चढ़ने का माद्दा रखती हैं, जिसके चलते इन कृतियों को शिक्षा विभाग की अनूठी पूँजी कहा जा सकता है। इतना ही नहीं ये सभी रचनाएँ शिक्षा विभाग के कैलेंडर में रची बसी हुई हैं।

उल्लेखनीय है कि श्री सत्यवीर ने एक ओर जहाँ रसायन शास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर अपने समर्पित टीम के साथ सरकारी स्कूल से आईआईटी तथा मेडिकल कॉलेजों के लिए रेवाड़ी जिले से सर्वाधिक विद्यार्थी दिए हैं, वहीं दो दशकों में उनके सैकड़ों विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, पत्र-वाचन, साइंस-ड्रामा, कला-उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव, कानूनी साक्षरता, गीता-जयंती तथा अन्य विभागीय कार्यक्रमों में जिले का राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व कर उत्कृष्टता हासिल की है, कोरोना के कठिन काल के लॉक डाउन के दौरान ये कृतियाँ उसी रचनात्मकता का प्रतिफल हैं।

इन कृतियों के संदर्भ में श्री नाहड़िया बताते हैं कि गत 20-22 वर्षों के अध्यापन काल में उन्होंने विभिन्न अवसरों पर प्रार्थना सभाओं तथा बाल सभाओं के लिए विद्यार्थियों हेतु जो रचनाएँ लिखीं, उन सब को संपादित कर नए सिरे से कलमबद्ध किया है।

इन पुस्तकों की भूमिका में प्रख्यात बाल साहित्यकार घमंडी लाल अग्रवाल ने जहाँ इन्हें छात्र जीवन की संजीवनी बूटी कहा है, वहीं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. कृष्णलता यादव ने इस रचनाधर्मिता को बाल मनोविज्ञान पर आधारित बाल उपयोगी साहित्य बताया है। दोहाकार रघुविंद्र यादव ने भाषा की सरलता और सहजता को कृतियों की खूबी करार दिया है।

**रमेश कुमार सीड़ा**
**अंग्रेजी प्रवक्ता**
**विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा**
**संप्रति प्रतिनियुक्ति पर चंडीगढ़ में**

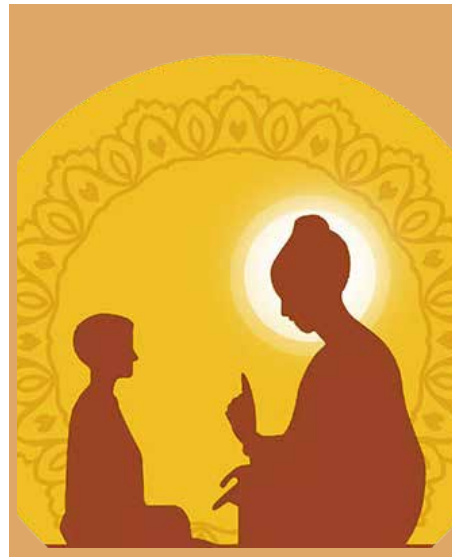

## गुरु का गौरव

गुरु पद इतना हो बड़ा, जितना हो आकाश।
अंधकार को हर करे, जीवन में प्रकाश।।

पहले पूजो गुरु को, बाद दूसरा देव।
भाग्य विधाता होत है, गुरुवर ही सदैव।।

गुरु बिन गति होती नहीं, कहते ज्ञानी लोग।
गुरु कृपा से ही मिटे, सकल जगत के रोग।।

पहली गुरु तो मात है, देती जीवन सार।
दूजा गुरु होते पिता, जो है पालनहार।।

माता से ममता मिले, और बाप से प्यार।
मिले गुरु से ज्ञान जब, तब हो बेड़ा पार।।

गुरुवाणी होती सदा, अमृत रस की धार।
श्रद्धाभाव से जो सुने, वो भवसागर पार।।

तरूवर फल देते हमें, नदिया देती नीर।
गुरुवर अपने ज्ञान से, हरते सारी पीर।।

गुरु आदि गुरु अंत है, गुरु का आर न पार।
ज्ञान बाँट करके करे, गुरु हम पर उपकार।।

**- भूपसिंह भारती, शिक्षक,**
**राजकीय माध्यमिक विद्यालय डेरोली अहीर**
**जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा**

प्यारे बच्चो!

आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित और प्रसन्न होंगे। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के कारण आपके विद्यालय बंद हैं। मुझे पता है कि आप बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब आपके विद्यालय खुलेंगे। उम्मीद करते हैं जल्दी ही स्थितियाँ सामान्य हो जाएँगी और आप सब की उपस्थिति से वीरान पड़े विद्यालयों में जल्दी ही रौनक लौट आएगी। तब तक आपके शिक्षण कार्य में व्यवधान न पड़े, इसके लिए विभाग ने काफी प्रयास किए हैं, जिनका लाभ भी आपको मिल रहा होगा। फोन, व्हट्सएप्प समूहों के जरिये आप अपने अध्यापकों के भी निरंतर संपर्क में हैं और हम जानते हैं कि आपका शिक्षण कार्य काफी अच्छे ढंग से चल भी रहा है। कुछ दिक्कतें भी आ रही होंगी, लेकिन इस संकट की घड़ी में हमें उनको भी सहना है। समाचारों के माध्यम से आपको पता लग रहा है कि हमारे अपने देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में हर रोज़ काफी वृद्धि हो रही है। हम चाहते हैं कि आप अपने आपको इस महामारी से बचाकर रखें। भले ही लॉकडाउन में काफी ढील मिल गई हो, लेकिन बिना वजह घर से न निकलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।

'बाल सारथी' आपको कैसा लगा, जरूर लिखना। अगले अंक में ज्ञान-विज्ञान और मनोरंजन की सामग्री लेकर फिर आपसे मिलूँगी।

**- तुम्हारी यामिका दीदी**

## सामान्य ज्ञान

1. किस मुगल राजा ने दीन-ए-इलाही की स्थापना की?
उत्तर- अकबर ने
2. हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है?
उत्तर- मोर
3. महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था?
उत्तर- 1869 में
4. विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
उत्तर- एशिया
5. जापान की राजधानी का नाम क्या है?
उत्तर- टोकियो
6. संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे?
उत्तर- बाबा साहब डॉ. भीम रॉव अम्बेडकर
7. हरियाणा की राजधानी का क्या नाम है?
उत्तर- चंडीगढ़
8. प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था?
उत्तर- 1914-1918 ई.

## पहेलियाँ

1. आदि कटे तो तल रहे,
यदि अंत कटे तो पीत ।
जो भी झटपट पूछ ले,
उसी की होगी जीत।।

2. उलटा हो कर होता राही,
बूझ सफलता पा मनचाही।।

3. उलटा होकर नाच दिखाये,
सीधा हो अनाज बन जाये।।

4. अन्त नहीं तो होता चाव,
मध्य नहीं तो बने चाल ।
अक्षर मात्र तीन ही हैं,
तुम पूछ लो तत्काल।।

5 अव्वल कटकर पानी बनता,
'ज' कटकर काल।
पहेली ने बिछाया देखो,
कैसा अनोखा जाल?

6. मन के आगे आगे चलता है,
करता कमल में है निवास।।
रहूँ चमक-दमक के बीच में,
रहे हरदम मेरा है निवास।।

7. शीश कटे तो टना रहे,
पेट कटे तो पना रहे ।
पैर कटै तो बने वस्त्र,
शहर समूचा बना रहे।।

8. आरा रहता बिन मध्य के,
बिना अन्त के रहता आग ।
अब पूछ सको तो पूछ लो,
मत करो हिम्मत त्याग ।।

उत्तर- 1.पीतल, 2.हीरा, 3.चना, 4.चावल, 5. काजल, 6.म, 7. पटना,8. आगरा

# रंगीन पंखों वाली चिड़िया

हमारे घर में रहती एक चिड़िया
रंगीन पंखों वाली सुंदर चिड़िया,
चोंच से चोंच मिलाकर वो मिलती
लगती है कोई जादू की पुड़िया।

तिनकों का घोंसला उसका परिवार है
बिन छोर का अम्बर उसका संसार है,
पल में दिखे कभी ओझल होती
उसके लिए हर दिन कोई त्यौहार है।

प्रभातफेरी सी वो जगती है
सूरज लपकने वो चल पड़ती है ,
उसके पंखों से इन्द्रधनुष भी चमके
सात रंगों में वो बसती है।

भीगे पंख भी उड़ती रहती
चाँद तारों को छूना चाहती,
उसको देख बादल भी उमड़ते
घर में नहीं सबके दिलों में रहती।

**लव कुमार 'लव'**
**हिन्दी अध्यापक**
**रामवि सम्भालवा, नारायणगढ़, अम्बाला**

# सूरज

सूरज दादा बन ठन आए
गूँज रही अंबर में शहनाई।
तारे बन कर आए बाराती
झुकी चाँदनी करे अगुवाई।

मेघ मुरैठा बाँध कर चलते
निशा ले रही है अँगड़ाई।
सूरज दूल्हा बना फिर रहा
देख उसे ऊषा शरमाई।

शीश मुकुट अति प्यारा है
साज रही है कमर कटारी।
सात फेरे लिए सूरज ने
ऊषा दुल्हन बन घर आई।

विनोद वर्मा 'दुर्गेश',
उप प्राचार्य, एलबीएस इंटरनेशनल स्कूल
गाँव तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा

# एकता की ताकत

एक बहेलिया जंगल में पक्षियों को पकड़ने के लिए गया और पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने जाल फैलाकर उसपर चावल के दाने बिखेर कर जंगल की झाड़ियों में छुप गया। इतने में झुण्ड में जाते हुए कबूतरों को जंगल में चावल के दाने दिखे तो उन सभी के मुँह में पानी भर आया। चावल के दाने चुगने के लिए सभी नीचे उतरे तो उनमें मौजूद एक बुद्धिमान कबूतर को कुछ शक हुआ कि भला जंगल में ऐसे चावल के दाने कहाँ से आ गये। इसमें कोई धोखा हो सकता है। उसके मना करने के बावजूद सभी कबूतर दाना चुगने लगे और इस तरह सभी कबूतर शिकारी द्वारा फैलाये जाल में फँस गये। सभी उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे सभी असफल रहे।

बुद्धिमान कबूतर बोला- दोस्तो! अगर हम सभी एक साथ पूरी शक्ति लगाकर उड़ें तो निश्चित ही हम सभी इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। इसके बाद कबूतर एक साथ पूरी ताकत से उड़ने लगे। पास में छिपा बहेलिया भी उनके पीछे दौड़ा, लेकिन कबूतरों की एकता की शक्ति के पीछे वह असफल रहा और उन कबूतरों को पकड़ नहीं पाया। फिर कबूतर अपने मित्र चूहे के पास पहुँचे। चूहे द्वारा जाल काटने के बाद एक बार फिर से आज़ाद हो गये। इस प्रकार उनकी एकता की ताकत ने उन्हें बहेलियें की कैद में पहुँचने से बचा लिया।

**-पंचतंत्र से**

# जीने की कला

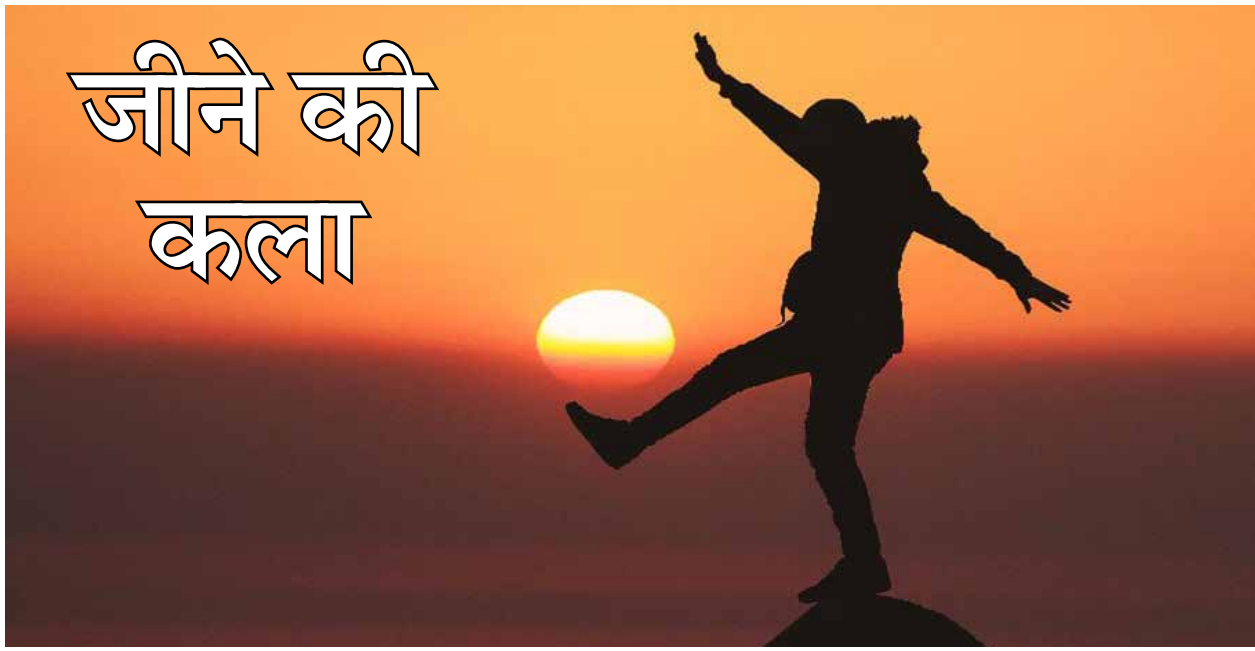

प्रकृति की सबसे बड़ी देन है-जीवन। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अपना महत्त्व होता है। उससे भी खास बात होती है कि किसी का जीवन कैसा है, कोई कैसे जीवन जीता है, किसी के जीने का क्या ढंग है, किसी का जीवन के प्रति क्या नजरिया है,आदि।

कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जो अपने जीवन को अपने अनुसार जीना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में कभी समझौता नहीं करते और कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन में न जाने कितनी बार समझौते करते हैं, भले ही फिर वे किसी की ख़ुशी के लिए किये गए हों या फिर किसी के दबाव में आकर या फिर मजबूरी वश।

जो इंसान स्वतंत्र विचारों के होते हैं, कभी किसी का दबाव नहीं मानते और अपनी भावनाओं और विचारों का पूरा ख्याल रखते हैं, वे जीवन में कभी किसी के अधीन होना भी पसंद नहीं करते। ये ऐसे इंसान होते हैं जो आशावादी, अभिलाषी और उन्मुक्त विचारों के होते हैं।

दूसरी तरफ कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको देखकर, जिनके रहन-सहन के तरीके को देखकर, जिनके विचारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी खुद की कोई जिंदगी ही नहीं है, उनके अंदर जैसे खुद की कोई भावना ही नहीं है या उनकी अपनी सोच या कोई खुद का ख्याल ही नहीं है। ऐसे इंसान न कभी खुलकर अपने को सबके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, न ही कभी अपना मजबूत पक्ष रख पाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनका अपना कोई जीने का नजरिया नहीं होता। ये दूसरों की सोच या तरीके को ही सही मान बैठते हैं। ऐसे इंसान अपनी जिंदगी चाहकर भी खुलकर नहीं जी पाते। एक तरह से इनकी अंदरूनी जिंदगी का कोई महत्त्व नहीं रहता। ये न तो कभी आत्मविश्वासी बन पाते हैं और न ही आत्मनिर्भर। इनको अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये दूसरे लोगों के दास बनकर रह जाते हैं। ये हर चीज़ को पाने के लिए तरसते रहते हैं और उसको पाने के लिए दूसरों का मुँह ताकते रहते हैं। इस तरह के लोगों का न तो भावनात्मक और न ही विचारात्मक पक्ष मजबूत हो पाता है और इस तरह के लोगों में निर्णय लेने की क्षमता भी क्षीण ही होती है।

ये खुद तो अपनी जिन्दगी को सही ढंग से जी नहीं पाते, बल्कि साथ में इससे वे अपनों की जिंदगी भी प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों की इसी सोच का असर घर-परिवार और समाज पर पड़ता है। ऐसे लोग दूसरों पर बोझ होते हैं और हमेशा अंदर-बाहर गुलामी के बन्धनों में ही रहते हैं। इस तरह ये लोग जीवन भर एक दास की तरह जीवन व्यतीत करते हैं।

ज़िंदगी बड़ी अनमोल होती है और इस ज़िंदगी को भी एक दास के रूप में गुजार दिया जाए तो इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी। हर इंसान के सीने में एक दिल धड़कता है। उस दिल में कई तरह की भावनाएँ हिलोरें लेती रहती हैं। अगर इंसान इन भावनाओं को दबा दे तो उसका अंदरूनी विकास वहीं रुक जाएगा। ऐसे में दो ही बातें सामने निकल कर आएँगी। एक तो यह कि वे दब्बू बनकर रहेगा और कभी उभरकर सामने नहीं आ पायेगा, दूसरी यह कि धीरे-धीरे उसमें नकारात्मक विचार हावी होने शुरू हो जायेंगे। इन नकारात्मक विचारों का पनपना ही भविष्य में विनाश की स्थिति पैदा कर सकता है

ऐसे नकारात्मक विचारों वाले लोगों को लगेगा कि जीवन छोटा-सा है और बस कुछ चीजें सीमित-सी हैं और जीवन जीने के भी ढंग सीमित ही हैं। ऐसे विचारों के साथ न वह कभी आगे बढ़ पायेगा और न ही उसे उम्मीद होगी कि आसपास भी कोई तरक्की होगी।

ऐसे नकारात्मक विचार जीवन की डोर को कमजोर करते हैं और इंसान समय से पहले ही न केवल बूढा हो जाता है, बल्कि इस संसार को जल्द अलविदा भी कह देता है। इस तरह के नकारात्मक विचारों का न आना, आत्मविश्वास का आना, अपनी भावनाओं की कद्र करना और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना ये सब मुमकिन है। बस ज़रुरत है कुछ प्रयासों को करने की।

सबसे पहले इंसान अपनी और अपनी भावनाओं की कद्र करे। खुद को ताक पर रखकर कभी समझौते न करे। अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक नजरिए से जिये। उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में दो चीजें और मदद करेंगी, और वे हैं- शिक्षा और रिश्तों में मधुरता होना। एक शिक्षित इंसान बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है और सभी के साथ बने मधुर रिश्तों से वह सब तरह की परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करके किसी भी कार्य को अंजाम दे सकता है।

दिल की कद्र करना, अपनी भावनाओं की कद्र करने की भावना इंसान को मजबूत बनाती है और दूसरों से जोड़ती है। इंसान का मन मजबूत होगा तो वह आत्मविश्वास के साथ आगे आएगा। एक आत्मविश्वासी इंसान कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता।

**विनोद कुमार, जीवविज्ञान प्राध्यापक**
**राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पीली मंदोरी**
**फतेहाबाद**

# हाँ, मैं सक्षम हूँ

राखी एक छोटे से कस्बे की निम्नवर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली बालिका है, पिता श्री रविन्द्र धीमान राज मिस्त्री का काम करते हैं तथा माँ गृहिणी हैं। दोनों की ही शिक्षा मैट्रिक से कम है। राखी बचपन में जब भी किसी अधिकारी को देखती तो अधिकारी बनने के सपने देखती थी। उसके पिताजी बड़े सपने न देखने की नसीहत देते, क्योंकि उनको पता था कि ये सपने टूटते हैं तो बड़ा दुःख होता है। राखी भी मन मसोसकर रह जाती थी, अपने आप को ही जवाब दे लेती थी कि हम सक्षम नहीं हैं। राखी ने अपनी आठवीं तक की पढ़ाई कस्बे के ही सरकारी विद्यालय से की, लेकिन नवमी कक्षा में वो एक अलग ही जिद्द करने लगी कि वह कस्बे से निकटवर्ती गाँव के विद्यालय में पढ़ने के लिए जायेगी। माँ ने बहुत समझाया कि वह कस्बे से गाँव में पढ़ने जाकर उलटी गंगा पहाड़ पर चढ़ा रही है, लेकिन राखी की हठ के आगे परिवार को झुकना पड़ा। इस विद्यालय में आकर राखी के सामने एक और समस्या आई। राखी हिंदी माध्यम से पढ़ी थी, लेकिन नये विद्यालय में तो विज्ञान, गणित के साथ सामाजिक विज्ञान भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता था। लेकिन राखी अपनी जिद्द की पक्की थी तो धुन की भी पक्की थी। उसने खूब मेहनत की और बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में 97% अंक लेकर जिले में तृतीय स्थान हासिल किया, लेकिन अपने इस प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसके विद्यालय की छात्रा ने गत वर्ष 98% अंक लेकर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया था।

राखी ने अपने विवेक से निर्णय लिया और कला संकाय को चुना। खूब मेहनत की और बोर्ड की 12 वीं की परीक्षा मे 98% अंक लेकर न केवल जिले में प्रथम स्थान लेकर निजी विद्यालयों के दंभ को तोड़ा, अपितु सभी सरकारी विद्यालयों में कला संकाय में राज्य भर में प्रथम स्थान हासिल किया तथा राजनीति विज्ञान विषय में 100/100 अंक लेकर विषय पर अपनी पकड़ बनाई।

ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। राखी हरियाणा के कैथल जिले के कलायत कस्बे की रहने वाली है तथा आरोही राजकीय विद्यालय रामगढ़ पांडवा की छात्रा है। उस दिन राखी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब कलायत की खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती परिणीता मधोक स्वयं मिठाई लेकर स्कूल पहुँची और न केवल राखी का मुँह मीठा करवाया बल्कि राखी को जिला उपायुक्त कैथल से मुलाकात करवाने का वादा भी किया। राखी को इतने बड़े अधिकारी से इतने स्नेह की आशा नहीं थी। आज उसका आत्मविश्वास यही कह रहा था- हाँ, मै सक्षम हूँ।

**जितेन्द्र राठौड़**
**प्राध्यापक राजनीतिक विज्ञान**
**आरोही राजकीय विद्यालय रामगढ़ पांडवा**
**कलायत, कैथल, हरियाणा**

## 2020

## सितंबर माह
### के त्यौहार व विशेष दिवस

1 सितंबर- राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
2 सितंबर - विश्व नारियल दिवस
5 सितंबर - शिक्षक दिवस
8 सितंबर - अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस
10 सितंबर - विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस
12 सितंबर - विश्व प्राथमिक उपचार दिवस
14 सितंबर - हिंदी दिवस
15 सितंबर - इंजीनियरों का दिन
16 सितंबर - ओजोन दिवस
23 सितंबर- हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस
24 सितंबर- विश्व समुद्री दिवस
27 सितंबर - विश्व पर्यटन दिवस
29 सितंबर - विश्व हृदय दिवस
30 सितंबर - अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस

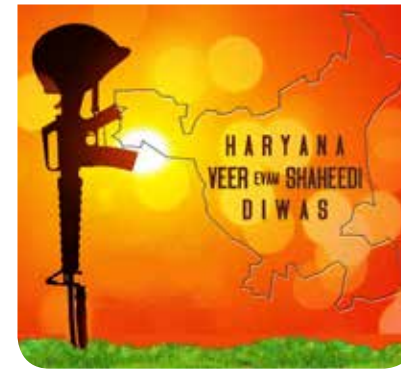


'शिक्षा सारथी' का यह अंक कैसा लगा? अपनी राय, विचार या सुझाव हमें अवश्य लिखें। लेखकों व शिक्षाविदों से अनुरोध है कि शिक्षा जगत से जुड़े विषयों, योजनाओं, मुद्दों से संबंधित रचनाएँ व लेख हमें भेजें। अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाली शिक्षा जगत की गतिविधियों की रिपोर्ट भी हमें भेजें। हमारा पता- शिक्षा सारथी, तृतीय तल, शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।
मेल भेजने का पता-
shikshasaarthi@gmail.com

# Can greater access to education be inequitable?

Chirantan Chatterjee

Eric Hanushek

Shreekanth Mahendiran

Right to Education Act, 2009, was designed to provide the right to free, quality school education to all 6-14 year olds in India. This article examines the influence of RTE on the expansion of private tutoring. It finds that the Act led to a significant increase in the number of private tuition centres that necessarily help the relatively well-off students who can afford them, thereby counteracting the goal of equitable access to schooling.

While the highest quality Indian schools and universities produce world-class scholars, innovators, and entrepreneurs, a significant portion of the population still cannot compete in global labour markets. India's Right to Education Act (RTE) – passed in 2009, and implemented across the nation in subsequent years – was designed to address the important underlying issue of providing access to quality education to all 6-14 year olds in the country. Whether it has been able to achieve its objectives will remain an important question in India's post-pandemic educational and human capital policies, going forward.

The promise of RTE was to expand the nation's human capital while simultaneously delivering more equitable

outcomes. By ensuring that all students could attend primary schools, the nation moved vigorously to help those left out of previous development.

Unfortunately, the outcomes of RTE illustrate how individual reactions to governmental programmes can subvert the intent of a programme. In recent research, we look at the causal influence of RTE on the expansion of private tutoring (Chatterjee et al. 2020). We find that universalising access to schools led to a significant expansion of private tutoring, which necessarily helps more advantaged students compared to those from low-income families. Thus, the move toward more equitable access to schools was counteracted by the expansion of tuition centres.

## India's Right to Education Act

In 2000, only 86% of Indian children were in primary schools, and the survival rate to grade 5 was 47% (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2003), underscoring India's longstanding challenge of providing broad access to schooling. With the worldwide push for expanded school access, India began moving toward universal access, and passed the RTE following a complicated path. In 2002, the 86th amendment to the Constitution introduced Article 21(a), which stated that "the State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine." The RTE was first presented to the parliament in 2006, but it was rejected and lack of funds was cited as the official reason. However, the RTE was approved by the Union Cabinet in 2008 and then passed through both the houses of the Parliament by August 2009, making it a national law. By 2012, all the state governments implemented the RTE by passing it in their own state legislatures.

RTE ensures that every child in the age group 6-14 years has the right to admission in a quality neighbourhood school, but does not mandate that a child must access only neighbourhood schools. Further, RTE mandates that any private unaided schools in the neighbourhood must allocate 25% of their entry-level seats (grade 1) to economically weaker sections and disadvantaged groups, and the compensation for the costs incurred by the private schools would come from the government. RTE mandates that all schools offering primary and upper-primary education must have good infrastructure in terms of a weather-proof building, boys' and girls' toilets, drinking water, ramps for the handicapped, a library, and so on. It also specified quality indicators for teacher preparation, class size, and the like.

Interestingly, however, the debate about RTE never considered that RTE might induce an expansion of private tutoring, and that this could offset the equity improvements from increased access to schooling.

## Tuition centres

Private tutoring is widely consumed around the world, but there are few analyses of the extent and character of

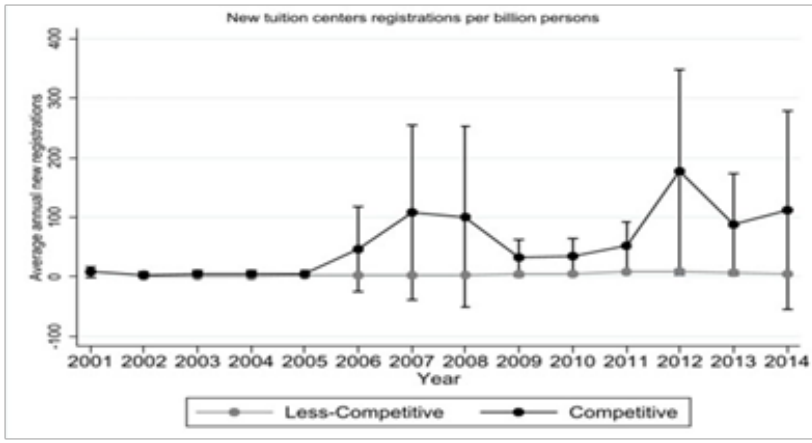


Figure 1. Parallel trends of new tuition centre registrations, per billion persons

such education (Bray 2017). Opinions on the impact of tuition centres tend to differ across countries – ranging from a useful complement to government schools to a source of inequity in society. The net impact on welfare is difficult to ascertain from existing literature.

In India, there has been a tradition of private tutoring since the 1980s (Azam 2016) with a recent report stating that parents in India lack trust in government schools and spend as much as 35% of household income on private schooling and supplemental education. A primary motivation for private tutoring that is frequently cited by Indian households is improving performance on key exams that determine schooling options, and access to quality post-secondary schools.

## RTE's impact on private tutoring

Our research considers the offsetting effects to equity improvements of RTE arising from induced expansion of private tutoring. We develop a unique database of registrations of new private educational institutions offering tutorial services, by local district, during 2001-2015. We estimate the causal impact of RTE on the expansion of private supplemental education by comparing the growth of these private tutorial institutions in districts identified a priori as having very competitive educational markets to those that had less competitive educational markets.

The key to our identification of the causal effect of RTE on private tutoring is comparing changes in private tutoring after passage of RTE for groups with intense educational competition and groups with less competitive pressures. Our main analysis leverages this intuition, and defines highly competitive districts as those containing one of the premier technical schools – an Indian Institute of Technology (IIT). The location and governance of the original IITs were exogenously set in 1961 as per the IIT Act. The admissions competition for these undergraduate schools is especially intense as they have been traditionally viewed as a clear gateway to economic success in India. The comparison less-competitive districts are those lacking one of these institutions. While students from throughout India can attend any given IIT, the importance and competition clearly rises in the local district.

The intuition behind our 'difference-in-differences' approach is that, if the educationally competitive and the less-competitive districts are following common trends in the development of tuition centres before RTE, those trends would continue in the absence of RTE. Deviations from trend after the introduction of RTE are interpreted as the causal effect of RTE on private tutoring. In the empirical analysis, we verify and validate this parallel trend assumption.

Figure 1 provides a visual display of the expansion of tuition centres between 2001 and 2015. The monthly registrations are flat until just before the final enactment of RTE, but thereafter show some increase with the anticipation of RTE, and a strong jump after enactment in the educationally competitive districts.

Overall, we find a strong causal impact of RTE on the private tutoring market. Our baseline findings show that, with the expansion of school access due to RTE, the number of private tutoring centres in India expanded at a monthly rate of 53 per billion people in our educationally competitive districts. For the post-RTE period through 2015, this implies a conservative, estimated expansion of about 172,000 tuition students in the 14 IIT districts. While India has a wide range of tertiary schools, the IITs actually have just 10% of this number of new tutoring students enrolled in them.

## Conclusions

Tuition centres may facilitate human capital generation either at the remedial or competition/excellence margin, but our results also show that, while the intent of education for all is noble, private behaviour can offset the equity enhancement implied by the expanded access. The issue is highlighted by the pre-RTE observation about the rise in shadow education in India of Amartya Sen (2009): "Underlying this rise is not only some increase in incomes and the affordability of having private tuition, but also an intensifica-

tion of the general conviction among the parents that private tuition is "unavoidable" if it can be at all afforded (78 per cent of the parents now believe it is indeed "unavoidable" – up from 62 per cent). For those who do not have arrangements for private tuition, 54 per cent indicate that they do not go for it mainly or only because they cannot afford the costs." The RTE compounded this problem.

The active neglect of the issue of tuition centres by Indian policymakers and administrators has recently also incentivised the rise of digital education firms in India, such as Byju's. These firms induce private behaviour by offering personalised services (such as dedicated mentor, one-to-one tutoring, etc.). They also charge different prices for varying levels of personalised services (like freemium model1) to increase its coverage and strengthen its market position. In addition, these new digital education firms may contribute to legitimisation of current practices of shadow education where students are taught strategies to score higher in competitive exams like JEE (Joint Entrance Examinations) for IIT entrance, and NEET (National Eligibility cum Entrance Test) for entrance into medical courses. Finally, the rise of in-person and online tuition services only weakens the role of teachers since students may choose to reserve their attention and effort for tuition classes and not towards teachers during school hours. In essence, the rise of digital tutoring firms like Byju's threatens the purpose and existence of formal education itself, further deepening the adverse welfare implications of our findings in terms of equity and educational outcomes of India's millions with RTE (for example, Jha et al. 2019).

While it is beyond our basic analysis of RTE, policymakers should consider these implications, building especially on the recently approved 2020 National Educational Policy of India. The answers are quite clear to us. High-quality education must be provided to all. It is not sufficient to mandate universal access without continuous monitoring of the quality of the delivery of education in the ecosystem. This needs to happen both for the brick-and-mortar shadow education startups in India, and their more recent digital siblings.

A version of this article has been published on VoxEU: https://voxeu.org/article/unintended-consequences-education-all-india-s-right-education-act

**Notes:**

1. Freemium is 'a pricing strategy by which a product or service is provided free of charge, but money is charged for additional features and services.'

**https://www.ideasforindia.in/topics/human-development/can-greater-access-to-education-be-inequitable.html**
**"Reprinted with permission from 'I4I' Ideas for India (www.ideasforindia.in)"**

**Indian Institute of Management Ahmedabad**
**chirantanc@iima.ac.in**

**Stanford University**
**hanushek@stanford.edu**

**University of Lausanne**
**Shreekanth.Mahendiran@unil.ch**

# Apps that stimulate learning

Md Iftekhar Alam

The current scenario of the world is very challenging, for the reason that no one could have predicted the present unthinkable moment due to the pandemic COVID-19. We must be ready to acclimatize with the demands of time and law of nature, as Charles Darwin rightly said that is "Survival of the Fittest". In fact most of us have already started working on alternative means in our respective fields. Work from home is the best substitute for most of us to protect ourselves from the clutches of Corona Virus. Nowadays, going digital has become the need of the hour in every field. Hence in the matter of our children's learning, which is one of the most important things to deal with during this pandemic, we should not kneel down.

India is a country where almost every third person has a smart phone and every single day a new stone is being turned in the field of software and mobile apps. Effective results are being seen where some smart apps have turned our Smartphone's into a virtual classroom providing all necessities and making learning as well as teaching simpler and enjoyable too. In the online education system, even co-curricular activities are not lagging behind. These apps are user friendly, easy to access and a very good platform to gain education at our own pace. But there are a plethora of apps and one may get confused about the pros and cons of them. Therefore, we must have an understanding of apps which are beneficial for us while learning. For this, right information about apps is needed as it is truly said, "Winning or getting Success in Anything is 70% about Right Information we have". So in the present paper you will get the information about some of the most fruitful and interesting educational apps.

epathshala learning on the go

E-pathshala is a Government of India initiative to provide access to educational material through digital medium. This app has been developed by experts from Central Institute of Educational Technology (CIET), NCERT.

Content on this app is available in three languages; English, Hindi and Urdu. The subject matter is present in the form of digital books benefitting not just students but teachers, parents and educators too. This provides a platform where a variety of educational resources are available which include textbooks, supplementary readers, exemplar problems etc. along with videos, audio clips related to topics for making the content easier. We may also download e-books of NCERT from this app if we want to read afterwards. All the content in this app is free of cost.

DIKSHA-An e-learning portal launched by MHRD in association with National Council for Teacher Education (NCTE) for enabling smooth and hassle free interaction between students and teachers. A national digital infrastructure for teachers is a step towards ensuring holistic learning for teachers and students too. Teachers and students can access the material after scanning the QR code provided in their NCERT books. One of the best things about this app is that, it encompasses content not only of NCERT but also from various States of India. State Council of Educational Research and Training (SCERT) of various States are involved in preparing teaching-learning material at the State level.

Conceptualized by Million sparks foundation, this mobile application provides scope of professional development for in-service teachers through online training with SCERTS/DoEs. Best part of CHALKLIT is helpful, fun filled and very interactive content. Teachers from Goa, Delhi, Haryana and Chhattisgarh have been benefitted from this app. Chalklit provides annual lesson plans for teachers which includes objectives of the lesson along with interesting videos and assessment techniques. Online teacher trainings are conducted at regular intervals on the recent advancements in the field of education. Teachers and mentors can also share their views and suggestions on the various topics.

Sampark Foundation, a non-governmental organisation has launched an app —Sampark Baithak—with a free learning platform in Hindi. The platform provides education to about two crore children across the entire Hindi-speaking belt of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and Madhya Pradesh. The app intends to teach children in the age group of 5-15, or up to class 8 providing animated videos, worksheet, gaming, puzzle making content easy and interesting for all subjects following state syllabus. The best thing is free download of content making later viewing possible. In Haryana, teachers and students of class 1 to 5 are being benefitted currently through this app.

Khan Academy app is also among the list of the best free educational apps for students. The app's mission is to provide a free and world-class education for all curious minds across the globe. Khan Academy has a unique way to drive knowledge into student's brains. All lessons are in forms of video tutorials on a virtual blackboard. Khan Academy also provides online courses for preparing for standardized tests like SAT, MCAT, LSAT, etc.

iChamp is an innovative digital platform that uses intuitive quiz-based learning to enhance Maths and English skills for children of 5-13 years age group. The biggest challenge for kids from class 1 to 8 was not understanding of concepts but lack of practice which became the stepping stone for iChamp. Even though the quality of teaching has improved in private schools across India, kids have a fear of Mathematics still leading to clear lack of motivation among kids resulting into lack of practice. iChamp uses elements of gamification like real-time challenges, rewards, competition, fun and social engagement to motivate a child to practice more. It is India's only truly gamified education platform, integrating the key features competition, rewards/recognition, and fun along with studies. This sets iChamp apart from other education portals in India that focus only on animation.

BYJU'S - The Learning App is one of the largest platforms for school stu-

dents with 42 million registered users offering comprehensive learning programs for students of classes 4th-12th along with test preparation courses for competitive exams like JEE, NEET and IAS. The app also personalises learning based on each student's pace and style of learning. The latest version of the app offers free 'Live Classes' by India's best teachers. The IAS aspirants get tricks and tips from IAS toppers to crack the CSAT, GS Prelims and Mains and also updated through current affairs videos, weekly current affairs quizzes. But in this app only some limited content is free of cost and the rest is chargeable.

The Interactive Learning app is one of its kind application which ensures concept learning through rich, interactive, virtual reality video modules giving 360 degree coverage of each and every topic building the opportunity for immersive learning. Towards the senior levels, the experiments get more nuanced suited to the needs of learning at that level. Every single experiment being a solid backbone of a learning flow which has been embedded in this app. The Learning App has built its loyal learner base, offering completely curriculum mapped solutions for CBSE and ICSE Board through the integration of pedagogy and technology.

Toppr Aasha, supported by Micheal and Susan Dell Foundation, started on June 2020 covering subjects like Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, History, Social Science, Business Studies, Economics, etc. Toppr plans to enrol meritorious students from low-income backgrounds, from class 9–12 and empower them free access to Toppr's Advance Pack Subscription and a team of academic counsellors, appointed to provide learning support to them throughout the year. Based on student's performance rewards worth up to Rs.10,000 will be provided. Along with education, this app provides platform to help students financially too.

## CONCLUSION

Mobile phones brought us to a new era of technology as now it isn't just a source of distraction but our basic need too. With the attack of this pandemic, our mobile phone has become an important tool for learning. By having an understanding of useful learning app students, teachers, parents and educators may benefit largely during this tough time.

Mobile phones are very bad Masters and best slaves.

**Pupil Teacher**
**Prarambh State Institute of Advanced Studies in Teacher Education**
**Jhajjar, Haryana**

# On-Line Teaching

## A Blessing in Disguise But with a Challenge

**Nirmal Gulia**

***'If a teacher is guided by a true passion to teach and bans the darkness with the light of knowledge, then nothing can extinguish that flame, nothing.'***

The outbreak of the Corona virus pandemic has created immediate challenges in the field of education. Undeniably the lockdown created an unpredicted pressure on the system to succour the education of nearly 300 million children across 1.4 million schools in the country .The concept of education changed overnight and in these times of crisis, digital learning has emerged an indispensable resource for education. This abrupt switch to online schools has been frustrating in the beginning from school management to teachers to students and parents. There has been a huge surge in search phrases like 'how to teach online', 'best online teaching platforms', 'online teaching tools', and 'online teaching techniques' means learning every hour, isn't it a blessing? The teachers have become overnight internet sensations trying to imbibe innovative modes of teaching through various trainings themselves and by the department.

***'Strength is built when Strength is tested'***

With responsibility comes greater burden. With the acceptance of this increased load come the feelings of newfound strength. The boundaries between study time, play time and me time having merged these days to the government regulations, keep the child engaged and the discipline to follow that routine. Surely it's time for the parents to be role models by providing a distraction free study corner and help them follow a daily schedule. The online environment offers unprecedented opportunities for students who would otherwise have limited access to edu-

cation as well as a new paradigm for educators in which dynamic courses and contents of the highest quality can be developed. Online teaching has also been positive in the sense that it has provided a platform for students to feel free to discuss their personal challenges with teachers, definitely enhances the bondage between the students-teachers and teachers –parents , a blissful gift.

However the online method of learning is not without issues. It has also brought to the fore some stark persistent realities of Indian society characterised by social inequalities in terms of availability of resources essential to access these online classes/ platforms, resulting in the digital divide between rural and urban, rich and poor. Due to financial constraints, students are not able to access the internet, and are devoid of electronic gadgets like laptops, smart phones, computers or even radio or T.V. Accessibility of internet and problem of interrupted electricity supply are big challenges. Experts point out that there is intense requirement of self discipline since responsibility is entirely upon the students to complete the work and studies on time. Lack of social interaction/personal connection with peers affects students' personality development. The students also require good management skills. Online classes have increased workloads but little practical experience.

***'A vision with action can change our life'***

Haryana Government has restored to a three –tier monitoring system of 'Daily Calls' to check whether the students are getting and doing H.W., watching lessons of EDUSAT, telecast on T.V., Doordarshan channel and on JIO T.V. for a week to the students' convenience and time.

Work leads to greater success. We live in an ever-changing world that is ripe with new possibilities. Thoughts must be transmitted and received for teaching to take place. We must facilitate the present time, better prepare to face the challenges of working in this new environment as well as embrace the new opportunities that it has to offer.

***'Be thankful for the bad times, for they herald the onset of the good'***

**Lecturer in English**
**DIET Machhrauli, Jhajjar**

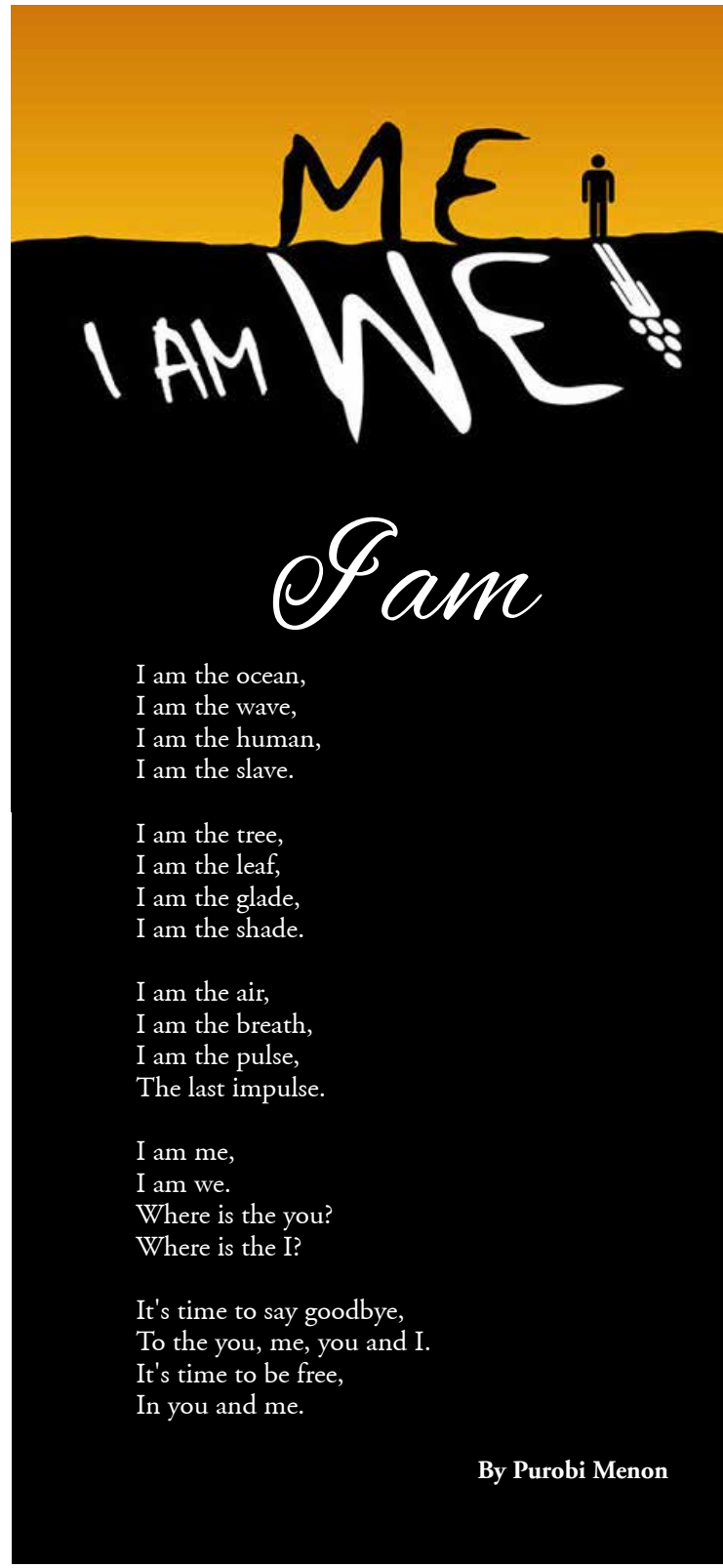


# I am

I am the ocean,
I am the wave,
I am the human,
I am the slave.

I am the tree,
I am the leaf,
I am the glade,
I am the shade.

I am the air,
I am the breath,
I am the pulse,
The last impulse.

I am me,
I am we.
Where is the you?
Where is the I?

It's time to say goodbye,
To the you, me, you and I.
It's time to be free,
In you and me.

**By Purobi Menon**

# Creating Language Rich Environment

Language is an essential part of all human beings and society. Every child learns her mother tongue/ first language naturally without any serious attempt to learn it. This shows the natural instinct and characteristics of humans to learn languages. As we grow, we learn many more languages in formal or informal settings. We know that a language cannot be learnt in isolation. It is best learnt when a learner gets input rich environment. Now days, students in schools are not attending schools due to the pandemic disease Covid-19. So it becomes imperative for teachers and parents to provide rich ambience in language learning. In this article we will discuss in short the ways how to create language rich environment for the students. Firstly, we must know that every teacher has to be a language teacher because language plays a pivotal role in the teaching learning

of content subjects. Language learning takes place while learning Maths, Social Science, Science, English and other subjects. Secondly, as language teachers we should know how to make use of the linguistic awareness and knowledge of children to enhance the learning of the first language further and to support second and third language learning. Linguistic awareness exists in the learners knowing how sounds are formed into words and words together make meaningful sentences. This shows they have an intrinsic grammar and know how to use it. (This does not imply that they know the rules of grammar well.) We need to build on whatever the children bring to their classroom and move forward to familiarize the second / new language like English or any second language. Thirdly, we must adopt the approach of multilingualism while teaching the second language like

English in Haryana state as the students almost relates to every part of the country. Multilingualism is a natural phenomenon which relates positively to cognitive flexibility and scholastic achievement also. Moreover, bilingual children not only have control over several different languages but are also academically more creative and socially more tolerant. Fourthly, children need to use the language in meaningful contexts in order to learn the language well. This can be said as, 'Learning to do it, Learn by doing it'. One cannot learn driving or swimming without driving car or motor practically on road or getting into water and trying to swim. Language learning has to provide opportunities for the children to use as they notice and get exposed to (new) language. In the period of students staying home, the teacher knows very well that the children may not know the structure and functions of the individual words or sentences they are using, but they know the meaning of them by visualizing the things and situations in context. The purpose is communication in a context. During the processes of using such phrases and sentences (we can call them as 'language chunks') the children learn the language subconsciously without any anxiety and they start using them spontaneously in their conversations. This 'input rich environment' where the language is seen, noticed and used by the children helps them learn the language and the proficiency in the language also increases. It is not enough to just provide language rich input in the classroom, it is also necessary for children to interact with their peers and the teachers and use the language for purposes more than what has been given to them during the input time. Language inputs received by children through teacher's language, printed material like textbook, supplementary materials and videos or text on digital screen need to be supported by scope for interactions in the homes and on telephones. Interaction with peers, with teachers and others in the language promotes children to use language for purposes. This enables children to acquire / learn the language in context. So we should encourage students to talk in English or in Hindi with correct accent and pronunciation. Learners should develop and possess both Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) and Cognitively Advanced Language Proficiency (CALP) (Cummins and Swain, 1986). The language ability that is associated with BICS largely involves the skills to perform effectively in situations that are rich in context and undemanding at the level of cognition. The language of here and now and that of peer group interaction belongs to the domain of BICS. That's why input rich environment should not provide information only but interactive and activity based learning to the learners particularly at primary and elementary level. CALP level abilities are needed to perform effectively in contextually poor and cognitively demanding situations. It would generally be acquired through instructed language settings. Fifthly, create conducive home or classroom environment and ensure that all children participate through online classes. Sixthly, connect language learning to the children' daily life, culture and society by facilitating the students through internet and other digital platforms. Seventhly, plan and use activities like pair work, group work, interactions effectively in the distance learning or in classroom situations. Eighthly, guide and facilitate students to create home libraries to promote reading, shared reading. Ninthly, use role-play and storytelling as a strategy to teach all the four skills in conjunction. Motivate the parents, grandparents and guardians to do so. Tenthly, reflect meaningfully on incidents which occur in day to day life. Eleventh and most importantly, use and promote students to use media inputs such as magazines, newspaper, ICT, etc. in the home or classroom situations.

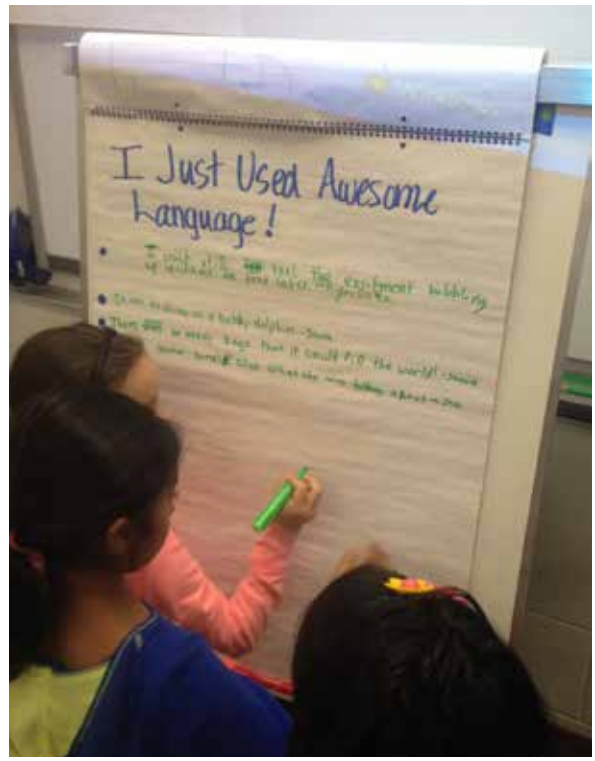


Reference: 1. NISHTHA Module by MHRD (now Ministry of Education) and NCERT.

**Lalit Kumar**
**Subject Expert,**
**SCERT Haryana, Gurugram**

# PUT ON YOUR THINKING CAP

Smt. RUPAM JHA

You learn to take your own decisions when you have your Thinking Cap on.

In today's rat race and competitive environment, the need to stand out in a crowd is important. Students need to know not only textual matters but contextual issues as well. For this, they have to put on their thinking caps. An end to rote learning is important. Education does not mean only cramming of the textbooks but an understanding of what is written.

Students should develop the ability to comprehend the lessons and conjure answers on their own. That is what learning is about. A lot of lessons are learnt that way. Individuality is encouraged and as students try and find solutions and right answers, language skills also develop. The right words and expressions have to be found, factoring in correct grammar and so all this leads to enhanced learning.

When a student learns to think, he becomes more capable for attempting other exams as well. It comes in handy, when the student has to take a competitive exam. Tricky questions normally have simple solutions if the student is able to think and then attempt an answer, then a solution to the question will be found by the student.

Thinking Out of the Box is now being encouraged in classroom level interactions. This gives an impetus to learning as the students tries to find out the how and why of the text being taught. In turn the student becomes more adept at comprehending the text and finding answers to questions.

Teachers should encourage students to think. Capability of the child will be brought out which further will help in bringing out hidden talent. Thinking and expressing should not mean indiscipline in the classroom but rather adding to classroom interaction.

Personality development and confidence building is part of the learning process. If a child is encouraged to think one of the by products will definitely be a confidence building exercise. It will lead to personality development which holds stead for life.

Whether it is thinking out loud or quietly in the mind, both should be encouraged among students. But many a times there are high thinking questions in public and competitive exams so thinking in the mind would be a better idea then. During self study,

Thinking

thinking aloud is alright.

Thinking does not mean day-dreaming but looking for real solutions to the questions put up in front of the student. Thinking is different from imagination too as thinking involves finding real answers to textual questions. Imagination too is important as it helps to motivate students, allowing them to think about a better future.

When you put on your thinking caps you learn to apply your mind and then act accordingly. Rational thinking emerges from this which generally leads to correct action.

Thinking can act like magic at times, in the human mind. The best example here would be "Think Slim" and the individual stops body shaming oneself. Like they say that battles are won in the mind. Dreams should soar and be motivational for the students, so my child! Do think.

So students, seek the how and why to find an answer to a question. Classroom interaction should not be a monologue; in fact the teacher must be able to elicit response from the taught. For this situation to emerge, students ought to be wearing their thinking caps.

Presence of mind develops in a thinking mind. This is because the mind is alert and responsive. Logical answers too can be derived from a thinking mind. This makes thinking more important.

Make thinking a habit, students to take note. It will be a part of your student life and gradually become part of your life. Maybe when schools organize a slogan writing competition, then one of the topics can be "Put on your Thinking Caps" and you can be the winner of that contest.

Thinking does not here mean that you add to your stress. Think positive and always think effortlessly. Negativity is to be always kept at bay especially in young and impressionable minds.

Think with a rational mind, think with a calm mind. Take note of the clarity of your thoughts and then act accordingly. This action will hold you in good stead.

So students, "Put on your Thinking Cap" and remember to keep it on!

Say yes to creativity and no to rote learning, think it out.

**Subject Expert**
**SCERT Haryana, Gurugram**

Those heroes without capes,
Those angels without wings.
Who helped to shape our lives,
And taught us everything.

Today we want to personally,
Thank everyone of you.
We will be forever grateful,
For everything you do.

When the World was alien to me,
You were always there.
When my hands shook while writing,
You took them to your care.

The times when you taught us,
How to stand in a queue.
The manners we have today,
Are only because of you.

You always held us,
When the winds blew strong.
And the way you corrected us,
When we were wrong.

You've been our inspiration,
From the time when we were young.
And many times throughout the year,
Your praises we have sung.

Forever we will keep your memory,
Stored within our heart.
Forever we will remember,
Just how you played a part.

You played a part by telling us,
Our dreams will all come true.
For teaching us how to believe,
Teachers, we are thanking you!

**By Shabih Fatima**
**Class VIII, Ahlcon International School, Delhi**

# Compendium of Academic Courses After +2

## INDUSTRIAL ENGINEERING

### Introduction

Even though the term industrial engineering is originally applied to manufacturing, it has extended its service to fields like operations research, systems engineering, ergonomics and quality engineering. Industrial engineering is also known as Operations management, Production Engineering, Manufacturing Engineering or Manufacturing Systems Engineering. In healthcare, Industrial Engineers are more commonly known as Management Engineers or Health Systems Engineers.

### Courses

1. B. Tech
2. M. Tech

### Eligibility

10+2

### Institutes/Universities

1. Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur
2. Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur

## INFORMATION, COMMUNICATION, ENTERTAINMENT

### Introduction

This is the age of Information-Communication- Entertainment (ICE) and massive expansion in broadcasting with the introduction of more television channels, direct broadcast satellites, T.V./Computer link ups, cable T.V. and rapid growth in both All India Radio and other broadcasting services particularly FM.

### Courses

1. B.A Mass Communication
2. B.A. Journalism

### Eligibility

After 10+2

### Institutes/Universities

1. Xaviers Institute of Communication (XIC),
2. Indraprastha College, Delhi University, New Delhi (Mass Communication)
3. Lady Sri Ram College, Delhi University, New Delhi (BA Hons, Journalism)
4. Communication and Culture Media Education Programme. Loyola College, Madras (Mass Communication)

### After Graduation

1. International Institute of Information Technology, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2. Chitrabani, Kolkata
3. Mass Communication Research Centre, Jamia, New Delhi
4. Indian Institute of Mass Communication, JNU Campus, New Delhi
5. Mudra Institute of Communication, Ahmedabad
6. Satyajit Ray Film And Television Institute, Kolkata
7. National Institute of design, Ahmedabad

8. Film And Television Institute of India, Pune
9. NIMT Institute of Mass Communication, Uttar Pradesh.

## INSTRUMENTATION ENGINEERING

### Introduction

Instrumentation engineering is a branch of electrical and electronics engineering that deals with the study of engineering principles and procedures of computing instruments used in designing and assembling automated systems.

### Courses

1. B.E. / B. Tech.
2. M.E. / M. Tech.
3. M. Phil.
4. Ph. D

### Eligibility

10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics as core subjects. Students must go through entrance exams such as JEE (Main) & JEE (Advance) for admissions to B. Tech. courses.

### Institutes/Universities

1. Bangalore Institute of Technology, Karnataka
2. Bharti Vidyapeeth College of Engineering, Maharashtra
3. BMS College Of Engineering, Karnataka
4. Dayananda Sagar Institute of Technology, Karnataka
5. M S Ramaiah Institute of Technology, Karnataka

## MANUFACTURING SCIENCE & ENGINEERING

### Introduction

Manufacturing Science and Engineering is the production of goods for use or sale using labour and machines, tools, chemical and biological processing, or formulation. Applied to industrial production, raw materials are transformed into

finished goods on a large scale to be used for manufacturing other, more complex products, such as aircrafts, household appliances or automobiles.

### Courses

B. E./ B. Tech.

### Eligibility

10+2 or equivalent,

The candidate must have a valid Joint Entrance Examination score.

### Institutes/Universities

1. Indian Institute of Technology, Kharagpur
2. Ranchi University, Ranchi, Jharkhand.
3. Siddaganga Institute of Technology, Tumkur, Karnataka.

## MARINE ENGINEERING

### Introduction

Marine engineering deals with the nautical architecture and science and basically is meant for research conducted in oceans, coastal or inland waters connected to the sea. Marine engineers have the entire responsibility of the ship's technical management.

### Courses

1. Diploma in Marine Engineering
2. Bachelor of Engineering in Marine Engineering
3. Bachelor of Technology in Marine Engineering
4. Bachelor of Technology in Naval architecture & Ocean Engineering
5. Master of Technology in Air Armament
6. Master of Engineering in Marine Engineering
7. Master of Technology in Marine Engineering
8. Master of Technology in Ocean Engineering and Naval Architecture

### Eligibility

(10+2) with biology, maths and chemistry.

For IITs, it is mandatory to qualify in the Joint Entrance Examinations (J.E.E). The duration of this course is 4 years.

### Institutes/Universities

1. IITs
2. International Institute of Maritime Science, (West Bengal),
3. College of Engineering, (Andhra Pradesh)
4. Maharashtra Academy of Naval Education & Training, (Maharashtra),
5. Marine Engineering Research Institute, (West Bengal),
6. Lal Bahadur Shastri College of Advanced Maritime Studies & Research, (Mumbai).

## MECHANICAL ENGINEERING

### Introduction

Mechanical engineering deals with

application of the principles of mechanics and energy to design machines and devices right from automobiles, trucks, airplanes to trains tractors, fax machines or even power plants. Robotic inspection systems, Cryogenic technology, Laser material processing are also some new emerging areas of study.

### Courses

1. Certificate in Mechanic of four Wheeler
2. Diploma in Mechatronics
3. Diploma in Mechanical Engineering
4. Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering
5. Bachelor of Technology in Mechanical & Automation Engineering
6. Bachelor of Technology in Mechanical Engineering
7. Bachelor of Technology in Mechatronics
8. Master of Engineering in Mechanical Engineering
9. Master of Engineering in Tool Design
10. Master of Technology in Mechanical Engineering
11. Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering

### Eligibility

(10+2) with biology, maths and chemistry.

For IITs, It is mandatory to qualify in the Joint Entrance Examinations. The duration of the course is 4 years.

### Institutes/Universities

1. IITS
2. Achutha Institute of Technology, Bangalore (Karnataka)
3. Reva Institute of Technology and Management, Bangalore (Karnataka)
4. HKBK College of Engineering, Bangalore (Karnataka)

Mechanical Engineering is a very popular course and perhaps one of the oldest also. The list of institutes is exhaustive apart from the few mentioned here. A number of other institutes conduct this course

## MEDICAL ELECTRONICS ENGINEERING

### Introduction

Medical Electronics engineering relates to the combined study of biology with engineering principles for developing artificial organs, prostheses (artificial devices that replace missing body parts), magnetic resonance imaging (MRI) and other health management systems. The course also offers specialisation in biomechanics, rehabilitation and orthopaedic engineering.

### Courses

1. Bachelor of Engineering in Medical Electronics
2. Bachelor of Technology in Medical Electronics
3. Bachelor of Engineering in Medical Electronics Engineering

### Eligibility

(10+2) examination with biology, maths and chemistry. For IITs, it is mandatory to qualify in the Joint Entrance Examinations. The duration of the course is 4 years.

### Institutes/Universities

1. IITs
2. BMS College of Engineering, Bengaluru.
3. Dayananda Sagar College of Engineering, Bengaluru. AFFILIATED TO VTU, APPROVED BY AICTE & UGC, ACCREDITED BY NAAC
4. Dr. Ambedkar Institute of Technology, Bangalore. affiliated to Visvesvaraya Technological University, Belgaum and accredited by AICTE.

# Amazing Facts

1. **Due to sugar shortages to make candy during World War II, movie theatre owners turned to popcorn, which is now the best selling snack at movie theatres today.**
2. The name of the award given to honor the best sites on the Internet is called "The Webby Award."
3. The United States Mint once considered producing donut-shaped coins.
4. A Hungarian named Ladislo Biro invented the first ballpoint pen in 1938.
5. Adolf Hitler loved chocolate cake.
6. Many years ago, a fish was caught that was 33 inches long and seemed to be heavier than it should. When they cut the fish, fishermen found a full of bottle of ale inside it.
7. In 1980, Saddam Hussein received a key to the city of Detroit.
8. The song "Strawberry Fields Forever" sung by the Beatles refers to an orphanage located in Liverpool.
9. False Bay, on the southern tip of Africa and close to Cape Town, South Africa, is a breeding ground for great white sharks, which feed off the thousands of seals in the bay. However, it is the only area in the known world in which these sharks are known to breach - they attack the seals by coming up vertically, often leaping clear of the water with their prey in their mouths.
10. In 1952, the first TV toy commercial aired. It was for Mr. Potato Head.
11. Mules have one horse and one donkey for a parent.
12. The name Hasbro was invented by the name of the founders: HASsenfeld BROthers.
13. Percentage of Africa that is wilderness: 28%. Percentage of North America that is wilderness: 38%
14. A group of whales is called a pod or gam.
15. Even though a polar bears fur looks white it is actually colourless and is made with hollow tubes. The reason the bear looks white is because the rough inner surface of the tubes make light scatter and reflect at many different angles which gives the white appearance.
16. There is a type of coffin made that can be used as a wine rack or picnic table before its final use.
17. One gallon of used motor oil can ruin approximately one million gallons of fresh water.
18. After the Eiffel Tower was built, one person was killed during the installation of the lifts. No one was killed during the actual construction of the tower.
19. Approximately 87% of dog owners say that when they watch T.V. their dog curls up beside them or at their feet.
20. People who meet their calcium need reduce their risk of developing kidney stones.
21. In every episode of Seinfeld there is a Superman somewhere.
22. The human heart weighs less than a pound.
23. The first Life Saver flavour, which was peppermint, was invented in 1912 and it was called Pep-O-Mint.
24. The average life span of a peasant during the medieval ages was 25 years.
25. Before 1859, baseball umpires were seated in padded chairs behind home plate.
26. On February 10, 1964 the first self-adhesive stamps were issued.
27. The ocean sunfish can produce thirty million eggs at once.
28. The highest point in France is Mont Blanc, located in the Alps.
29. Oak trees do not produce acorns until they are fifty years of age or older.
30. Moscow was founded in 1147 by Yury Dolgoruky.

**www.greatfacts.com/**

# General Quiz

1. How many cubic centimetres are in a cubic metre? **A million**
2. Who was appointed official wedding photographer to Prince William and Kate Middleton? **Mario Testino**
3. A 2010 study published in the Lancet suggested what medicine, recently found to reduce cancer development, aside from giving protection against strokes and heart attacks, is "...the most amazing drug in the world..."? **Aspirin**
4. What popular cereal brand has for decades featured a kilted athlete on its box? **Scott's Porage Oats**
5. Which European country is known as 'The Cockpit of Europe'? **Belgium**
6. Isaac Newton, Charles Darwin, Crick and Watson (DNA discoverers), the economist John Maynard Keynes, and the comedian John Cleese are among the notable alumni of which university? **Cambridge**
7. What type of food is Sapsago, also called Sap Sago and Schabziger? **Cheese**
8. What degree angle are the corners of a regular tetrahedron? **60**
9. Who directed the 1994 film 'Shal low Grave'? **Danny Boyle**
10. Name the Google phone and software system which, according to some news reports in 2010, ended Nokia's 10 years' of market dominance? **Android**
11. What is the full name of the football organization usually abbreviated to UEFA? **Union of European Football Associations**
12. The move called 'en passant' features in what board game? **Chess**
13. Named after its inventor, what is the signal lamp used to transmit Morse Code, devised in the late 1800s and still used today on naval ships? **Aldis Lamp**

14. Naxos, Santorini, and Mykanos are among what group of Greek islands? **Cyclades**
15. Which Scottish castle did Queen Victoria and husband Prince Albert buy in 1852? **Balmoral**
16. The five rivers of hate, oblivion, fire, woe, and lament feature in what mythical place? **Hades**
17. South-West is how many degrees on a compass? **225**
18. In the Blandings Castle stories by P G Wodehouse, what kind of animal is The Empress of Blandings? **Pig**
19. 'Cucumber Time' is the quiet season in which trade? **Tailoring**
20. Which bird, which lays the largest egg in proportion to its body size of all birds, is an apteryx? **Kiwi**

**https://www.businessballs.com/quiz/quiz-93-general-knowledge/**

आदरणीय संपादक जी,

नमस्कार।

'शिक्षा सारथी' अगस्त माह का अंक पढ़ने को मिला। यह देख कर मन हर्षित हुआ कि प्रदेश में चल रहे 'दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम' की 'डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट-2020' में भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। निश्चित तौर पर प्रदेश में विपरीत स्थितियों में शिक्षण कार्य सुभीते से चल रहा है। प्रमोद कुमार के लेख में बताया गया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणामों में पिछले छह-सात वर्षों से निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है, जो इस बात का शुभ संकेत है कि राजकीय विद्यालयों की स्थिति और शिक्षण स्तर अब काफी ऊँचा उठ गया है। बेटियों के सराहनीय प्रदर्शन की ओर इंगित करते सत्यवीर नाहड़िया और डॉ.प्रदीप राठौर के लेख बेहद पसंद आए। एक संतुलित, सारगर्भित व ज्ञान-विज्ञान की जानकारी से भरे इस अंक के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई।

**- अनिल कुमार,**
**कार्यक्रम अधिकारी**
**निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा**

आदरणीय संपादक जी,

'शिक्षा सारथी' का अगस्त अंक सदा की भाँति ज्ञान-विज्ञान की सामग्री के साथ-साथ विभाग की गतिविधियों पर केंद्रित रहा। यह अंक बोर्ड परीक्षा में सरकारी विद्यालयों के शानदार परीक्षा परिणामों पर केंद्रित था। 'कोरोना और स्कूली शिक्षा' लेखक बहुत पसंद आया। इसके लेखक प्रमोद कुमार को बधाई। बोधराज श्योराण ने अपने लेख में काबड़ी के सरकारी विद्यालय की उपलब्धियों को बड़े शानदार ढंग से प्रदर्शित किया। पत्रिका के स्थायी स्तंभ- खेल-खेल में विज्ञान और बाल सारथी हमेशा की तरह ज्ञानवर्धक सामग्री से भरे हुए थे। सुनील अरोड़ा का लेख पढ़कर अंजीर के विषय में नवीन जानकारी प्राप्त हुई।

**-नरेश कुमार शर्मा**
**प्रधानाचार्य**
**राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुंगा**
**जिला-पंचकूला, हरियाणा**

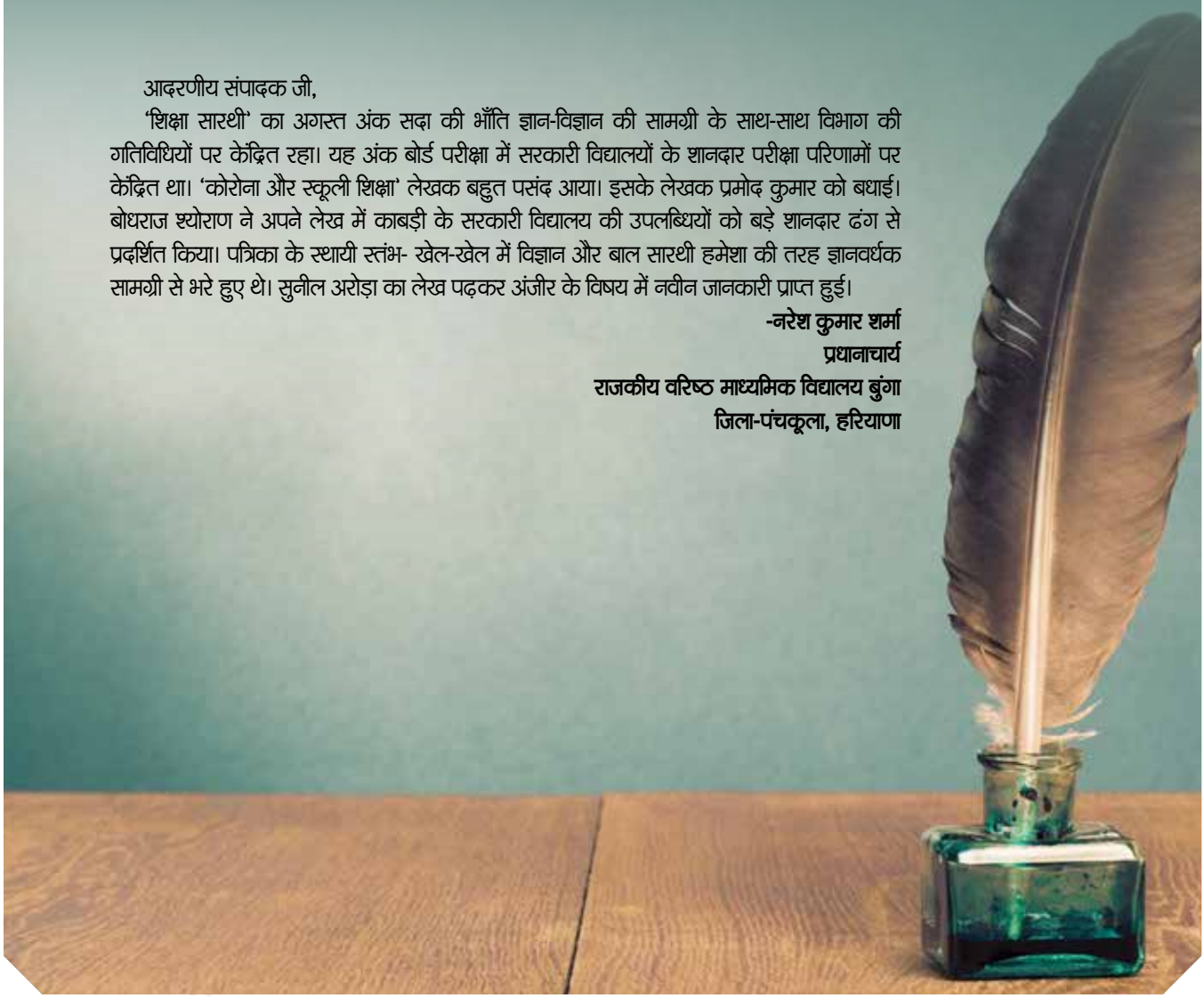

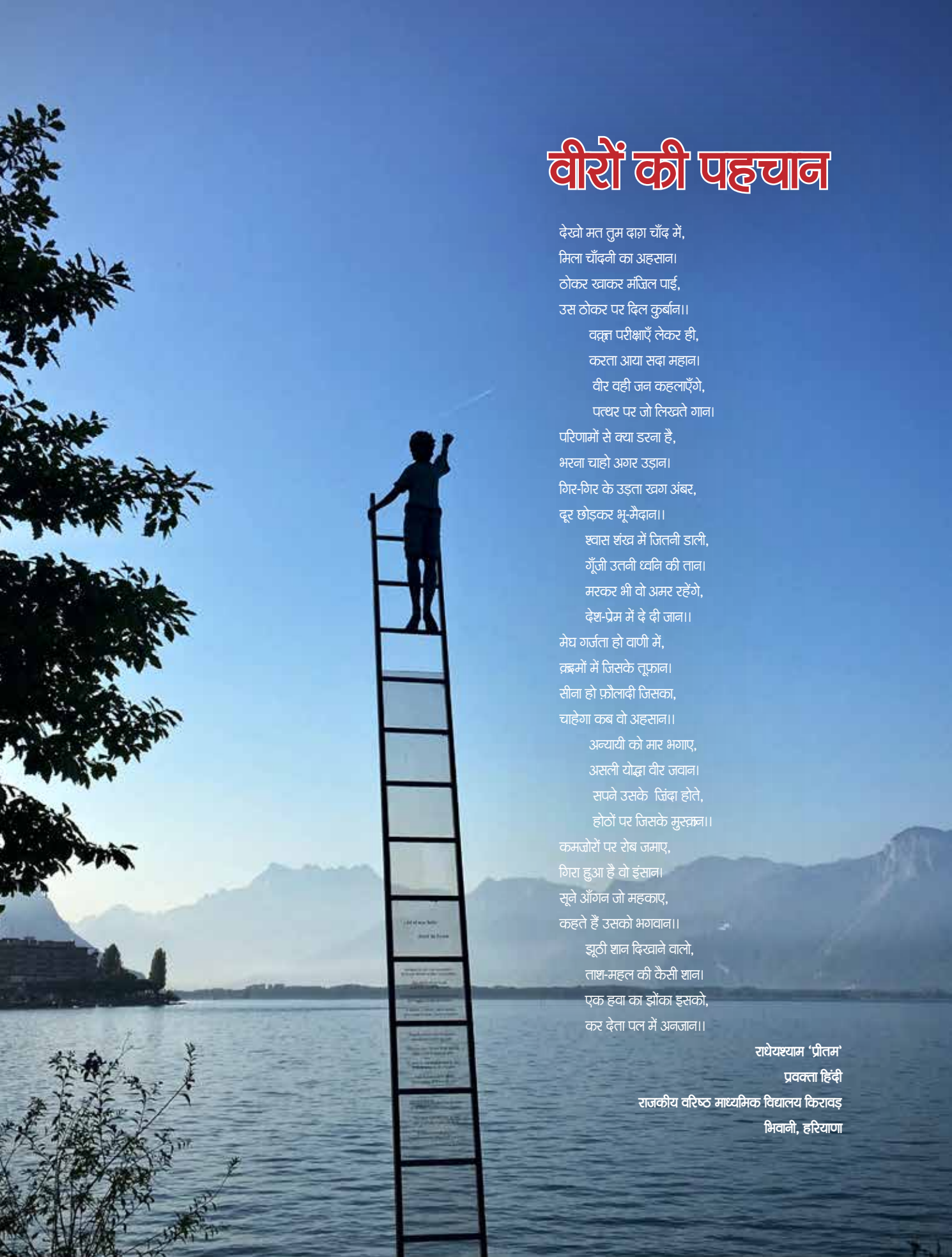

# वीरों की पहचान

देखो मत तुम दाग़ चाँद में,
मिला चाँदनी का अहसान।
ठोकर खाकर मंज़िल पाई,
उस ठोकर पर दिल कुर्बान।।

वक़्त परीक्षाएँ लेकर ही,
करता आया सदा महान।
वीर वही जन कहलाएँगे,
पत्थर पर जो लिखते गान।

परिणामों से क्या डरना है,
भरना चाहो अगर उड़ान।
गिर-गिर के उड़ता खग अंबर,
दूर छोड़कर भू-मैदान।।

श्वास शंख में जितनी डाली,
गूँजी उतनी ध्वनि की तान।
मरकर भी वो अमर रहेंगे,
देश-प्रेम में दे दी जान।।

मेघ गर्जता हो वाणी में,
वक्षमों में जिसके तूफ़ान।
सीना हो फ़ौलादी जिसका,
चाहेगा कब वो अहसान।।

अन्यायी को मार भगाए,
असली योद्धा वीर जवान।
सपने उसके जिंदा होते,
होठों पर जिसके मुस्कान।।

कमज़ोरों पर रोब जमाए,
गिरा हुआ है वो इंसान।
सूने आँगन जो महकाए,
कहते हैं उसको भगवान।।

झूठी शान दिखाने वालो,
ताश-महल की कैसी शान।
एक हवा का झोंका इसको,
कर देता पल में अनजान।।

**राधेश्याम 'प्रीतम'**
**प्रवक्ता हिंदी**
**राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किरावड़**
**भिवानी, हरियाणा**

RNI NO: HARBIL/2012/52385 POSTAL REGD NO: HR/AB-102/20-22

Government of Haryana

# ADOPT AYURVEDA TO BOOST IMMUNITY

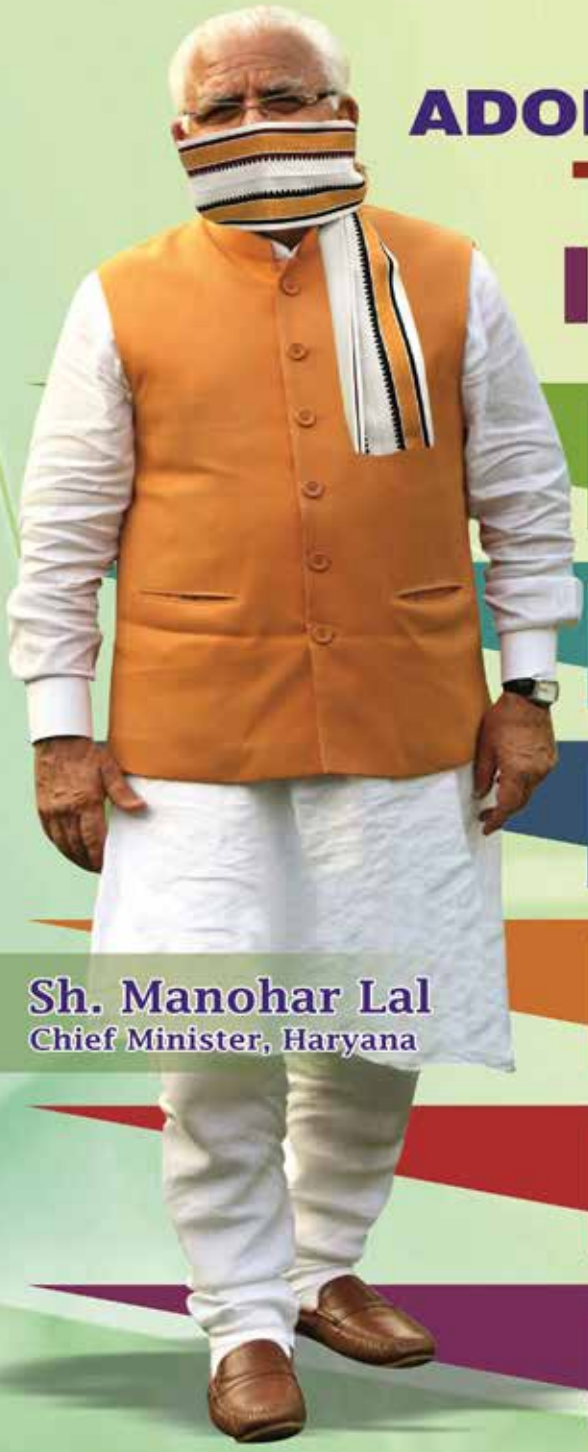

**Sh. Manohar Lal**
Chief Minister, Haryana

- Drink Herbal Decoction Made from Basil, Cinnamon, Black Pepper, Dry Ginger and Raisin

- Use Turmeric, Cumin, Coriander and Garlic in Cooking

- Drink Hot Golden (Turmeric) Milk

- Consume Giloy Everyday

- Use Sesame/Coconut Oil or Ghee Drops in Both the Nostrils

- Use AYUSH Kwath, Guduchi Ghan Vati/Samshmani Vati and Anu Tail with Doctor's Advice

Information, Public Relations & Languages Department, Haryana
www.prharyana.gov.in | @cmohry @DiprHaryana

If undelivered Please return to c/o Shiksha Saarthi Branch, 3rd Floor, Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula(HR)-134114